HP/129/SML/2019-2021 Title Code : HPBIL00313 RNI Reference No. 1328500 01-15 जून, 2019

मौसम का हाल

मौसम में बदलाव आऐगा। धूप के बाद बादलों का आना जाना लगा रहेगा । अगले हफ्ते में भी बादलों के बने रहने और बुंदाबांदी का मौसम रहेगा । हालांकि गर्मी से राहत मिलने के कम ही आसार है ।

द रीव टाइम्स

The RIEV Times

हिमाचल, वर्ष 1/ अंक 22/ पृष्ठ: 16 मूल्य: ₹ 25/-

www.therievtimes.com आलोचना के हर पत्थर से सफलता की सीढ़ीयों का निर्माण करें : डॉ॰ एल.सी. शर्मा

Towards Disaster Risk Reduction and Making Societies Resilient

Dr L.C. Sharma
Editor-in-Chief

As the entire world is striving for minimizing the loss of lives and economy due to various disasters and making the societies resilient, participating in Global Platform 2019 in UN Geneva as part of ARISE India Delegation proved to be an opportunity to increase the horizon of IIRD's humanitarian services.

In fact, when a person loses hope to receive instant support for surviving, recovering or progressing is a disaster irrespective of the causes like earthquake, flood, cyclone, drought or epidemic etc. Disaster has two aspects, one is the physical like earthquake, flood, drought, fire, epidemic, etc. and the second is subtle form which is intensively affects the mentale of the individual. The physical aspect does have the defined and structured mitigation measures and processes. The endeavours are being made by the government and non-govt. agencies on different magnitude to address the physical aspect.

The time has now come to evolve as Global Platform or as a country to consider the subtle aspect of Disaster as equally important because Disaster for a common person is the moment one loses hopes of instant support when required. And thus can we imagine to create platform or network whereby people especially of rural background, away from quick first response, get instant support not only in the situations like physical disaster but in every aspect where one starts losing hope from life. The risk of the disaster can be effectively reduced once we have support and facilitation system available for everyone.

We as IIRD in India, have been experimenting with the newly conceived facilitation support system under the patronage of ARISE INDIA named Mission RIEV (Ruralising India-Empowering Villages).

The process starts with the registration of the families collecting basic demographic and socio-economic status. In the second step, we make comprehensive Need Assessment age-wise, occupation-wise and others including education, health, agriculture, banking and finance, entrepreneurship and business development, social security, rural produce marketing, Utility services, etc. The team of dedicated functionaries deliver the customized services on low cost basis in the villages.

IIRD Board participating UN Global Platform Geneva as part of ARISE India

There are 3226 Village Administration Units / Gram Panchayats in the pilot state of Himachal Pradesh and every Gram Panchayat is being serviced by minimum 3 Service Associates totalling 10,000 Service Associates and the number likely to reach to 10 in each Gram Panchayat with the employment to around 35000 native youths of the Gram Panchayats. This entire process has witnessed multiple effects like:

- **1**.Creation of abundant employment opportunities to the youths in the villages; hence minimizing migration.
- **2**. People from cities / metros coming back to their roots; hence promoting Reverse Migration.
- **3**. Through various facilitation support; becoming instrumental in enhancing production and marketing system of rural produce; hence boosting rural economy.
- **4**. Facilitating in support required in different aspects of life; hence accelerating overall progress of life.
- **5**. And finally, evolving as First Response Force in case of any Disaster Like Situations; Caring for Uncared.

"We foresee to create the employment opportunities to around 10 Million people in India within next five years once the concept is replicated across country. And we are equally keen to partner with different countries especially the developing one to launch such ambitious programme of serving the humanity in most economic way. We invite different Govt, Non-Govt and International Organisations to visit and strengthen our hands to further foster the idea of SERVE and EARN."

विदेशों में भी रीव की मांग से इसकी सार्थकता पर लगी मुहर

यू एन में मिशन रीव की वाहवाही

अफ्रीकन देशों के प्रतिभागियों से होगी रीव पर चर्चा

टीम आईआईआरडी ग्लोबल प्लैटफॉर्म जिनेवा में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने सम्मिलित हुए प्रधानमंत्री के अतिरिक्त सचिव पी के मिश्रा के साथ

द रीव टाइम्स : हेम राज चौहान

आईआईआरडी का प्रतिनिधि मंडल अराईज़ इंडिया के साथ जिनेवा में यूएन की बैठक में मिशन रीव पर चर्चा के साथ भारत लौट आया है। प्रतिनिधि मंडल में चेयरमैन प्रो आर के गुप्ता, प्रबंध निदेशक डॉ. एल सी शर्मा, निदेशक सुषमा शर्मा एवं निदेशक मंडल के सदस्य ब्रिगेडियर वी के खन्ना शामिल थे। अपने प्रस्तुतिकरण में ब्रिगेडियर खन्ना और डॉ. एल सी शर्मा ने मिशन रीव की आज के संदर्भ में प्रासंगिकता को बेहतर तरीके से सामने रखा जिसे 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने सुना और सराहा भी। डॉ. एल सी शर्मा ने बताया कि मिशन रीव जन सेवा और सामाजिक विकास के ताने-बाने में सर्वथा उपयुक्त है जिसे हिमाचल प्रदेश के बाहर अन्य राज्यों और अब विदेशों में भी सराहना मिल रही है।

गौरतलब है कि विगत वर्ष भी मिशन रीव पर यूएन में प्रस्तुतिकरण हो चुका है जिसे खूब सराहना मिली थी। और यह दूसरा अवसर है जब रीव के प्रणेता डॉ. एल सी शर्मा ने मिशन रीव को विदेशी धरती पर इसको आकर्षण का विषय बना दिया है। विश्व भर से आए देशों के प्रतिनिधियों ने मिशन रीव को उनके देश में भी इस प्रकार के प्रयासों को लागू करने पर चर्चा की। प्रबंध निदेशक के अनुसार शीघ्र ही अफ्रीकन एवं अन्य देशों के प्रतिनिधियों से इस विषय पर वार्तालाप और प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाऐगा।

ज़ांबिया की मंत्री Hon. Sylvia Bambala Chalikosa के साथ अफ्रीकन देशों में मिशन रीव को ले जाने की चर्चा के बाद संयुक्त छायाचित्र

भारत के स्मार्ट गांव के लिए मिशन रीव हो सकता है मॉडल

दिल्ली के प्रगति मैदान में मिशन रीव पर प्रस्तुतिकरण

द रीव टाइम्स : हेम राज चौहान

दिल्ली के प्रगति मैदान में एग्जिबिशन ईंडिया ग्रुप की वार्षिक सम्मेलन में स्मार्ट विलेजिज पर मिशन रीव के मॉडल को प्रस्तुत किया गया। इस प्रस्तुतिकरण को रीव के प्रणेता डॉ. एल सी शर्मा ने देशभर से आए प्रतिभागियों के समक्ष रखा। स्मार्ट सिटी के बाद अब स्मार्ट गांव पर भारत सरकार प्रयास कर रही है। इसी पर चर्चा एवं उद्बोधन के लिए देश भर से विभिन्न संस्थाओं एवं एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने अपना प्रस्तुतिकरण किया। आईआईआरडी के प्रबंध निदेशक डॉ० एल सी शर्मा ने मिशन रीव के मॉडल को प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने उद्बोधन में बताया कि जब तक गांव स्मार्ट नहीं होंगे तब तक देश का विकास यर्थात् पर नहीं आ सकता है। स्मार्ट गांव के लिए लोगों को भी स्मार्ट होना पड़ेगा। मिशन रीव इसी मॉडल का नाम है। जो लोगों की दुःख तक़लीफ और उन्हें सहयोग देने की जीवंत पद्धति पर सेवाऐं दे रहा है। भारत को स्मार्ट गांव बनाने में सबसे अधिक कारगर मिशन रीव मॉडल ही हो सकता है । उन्होंने मिशन रीव में आवश्यकता आकलन को सबसे अधिक प्रभावी बताया और कहा कि आवश्यकता आकलन के माध्यम से गांव-गांव में घर-घर तक एक-एक आदमी की आवश्यकताओं का आकलन किया जाता है जिससे उनकी समस्याओं और प्राथमिकताओं को सामने लाया जाता है। उसी आधार पर मिशन रीव ऐसोसियेट अपनी सेवाऐं देते हैं। इसका मूल यही है कि गांव की बेहतरी और आम इंसान की जीवन शैली में बदलाव लाकर लोगों को उनकी समस्याओं से दूर कर उन्हें अपने राष्ट्र एवं व्यक्तिगत निर्माण में सहयोग देने के लिए उन्मुक्त भाव से स्वतंत्रता मिले ।

गौरतलब है कि मिशन रीव पर डॉ० एल सी शर्मा ने देश भर में इसकी सार्थकता को साबित किया है। इसके अलावा यूएन में भी मिशन रीव का डंका बज चुका है जहां इस मॉडल पर न केवल चर्चा हुई बल्कि इस मॉडल को कई अन्य देशों ने भी सराहा है ।

केन्द्रीय मंत्री और उनके मंत्रालयों की लिस्ट

नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री	
राजनाथ सिंह (कैबिनेट मंत्री) रक्षा मंत्री	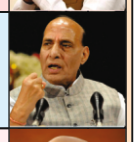
अमित शाह गृह मंत्री	
नितिन गडकरी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	

शेष पेज 2 पर

15 महीने कुछ नहीं कहा बस सुनता रहा : मुख्यमंत्री

कहा जीत से तंज कसने वालों को मिल गया जवाब

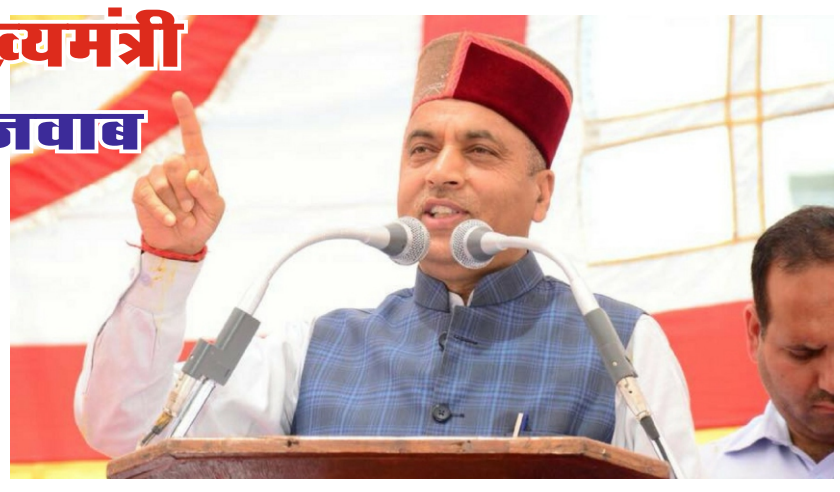

अंजना ठाकुर, शिमला

लोकसभा चुनावों की चारों सीटो पर मिली बड़ी जीत से गदगद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बीते 24 मई को शिमला में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान प्रदेश की जनता का धन्यवाद किया और जीत का सीधा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को दिया। मुख्यमंत्री के तौर पर उनके टेढ़ साल के कार्यकाल के दौरान उन पर तंज कसने वालों को जयराम ठाकुर ने आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कई ऐसे लोग हैं जो मुझे डेढ़ साल से कुछ न कुछ सुनाते रहे, कुछ ने कहा में नया हूं, अनुभव नही तो कुछ ने कहा मेरे बस की बात नहीं। लेकिन आज जिस तरह से लोगों ने भाजपा का साथ दिया है और लोकसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों को ऐतिहासिक जीत मिली है, उससे तंज कसने वालों को जवाब मिल गया है।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सुखराम और वीरभद्र सिंह का दौर खत्म हो गया है अब लोकसभा चुनाव में दिए जनादेश का सभी को सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरे देश में हिमाचल में भाजपा को सबसे अधिक 69 फीसद मत प्रतिशत मिला है, जबकि कांग्रेस को मात्र 27 फीसद वोट शेयर मिला।

उन्होंने कहा कि अपने डेढ़ वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने कम बोला और अधिक सुना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा को लीड मिली। मोदी ने पांच साल तक महिलाओं, गरीबों, पिछड़े वर्गों, किसानों व समाज के उपेक्षित वर्ग के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं लागू की। वहीं कांग्रेस पार्टी के करीब छह दशक के कार्यकाल में कुछ नहीं हो पाया।

तीस हलकों में तीस हजार की लीड मिली

सीएम ने कहा कि प्रदेश में 30 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर भाजपा को 30 हजार से अधिक मतों की लीड मिली है। रोहड़ू और रामपुर कांग्रेस के गढ़ रहे हैं और वहां से आजतक भाजपा को कभी बढ़त नहीं मिली, लेकिन इस बार भाजपा ने बाजी पलट दी। यह जीत केंद्र सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों पर लोगों की आस्था को दर्शाती है। भाजपा सरकार भविष्य में और अधिक निष्ठा व समर्पण की भावना से कार्य कर लोगों की अपेक्षाओं एवं आकांक्षाओं पर खरा उतरेगी।

जयराम ने कहा कि उनकी कैबिनेट में दो मंत्री पद खाली हो गए हैं। जब जरूरत होगी तब मंत्री पद भरे जाएंगे। अनिल शर्मा पर कार्रवाई को लेकर उन्होंने कहा कि अभी रिपोर्ट मांगी गई है उसके बाद ही आगामी निर्णय लिया जाएगा।

मैं ही काफी हूं राजनीति में–

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की पत्नी डाक्टर साधना राजनीति में आएंगी या नहीं, इस सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डाक्टर साधना अभी सरकारी नौकरी में हैं, वही सही है, राजनीति में अपने परिवार से मैं ही काफी हूं।

साल भर में तीन किलो हेरोइन और 115 किलो चरस पकड़ी: मरडी

द रीव टाइम्स ब्यूरो

सेंटर फॉर स्टडी डेवलपमेंट सर्वे के अनुसार पुलिस पर विश्वास में हिमाचल पुलिस प्रथम स्थान पर आई है। पुलिस उच्चाधिकारियों पर विश्वास में भी पुलिस को दूसरा स्थान मिला है। इस बात का खुलासा सचिवालय में डीजीपी एसआर मरडी ने बीते दिनों आपराधिक मामलों पर आयोजित बैठक के दौरान कही।

बैठक में पांच जिला सोलन, शिमला, किन्नौर, बद्दी, सिरमौर के एसपी, डीएसपी, एसएचओ सहित अन्य अधिकारियों ने हिस्सा लिया। डीजीपी मरडी ने कहा कि पूरे साल में तीन किलो हेरोइन और 115 किलो चरस को पकड़ने में सफलता मिली है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अपहरण के मामलों में कमी आई है। पांवटा साहिब से 45 हजार डेमाड्रोल के कैप्सूल पकड़े हैं।

पांच जिलों में पिछले वर्ष हत्या के 31 मामले थे जबकि 16 केस दर्ज हैं। वहीं हत्या के प्रयास के पिछले वर्ष 14 मामले थे। जो इस वर्ष बढ़कर 16 तक पहुंच चुके हैं। चोरी के मामलों में गिरावट आई है। बलात्कार के मामले भी कम हुए हैं।

उन्होंने बताया कि कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा है। उन्होंने बताया कि अब ई-चालान को शुरू करेगी जिसमें दो से अधिक बार चालान होने पर तीसरी बार लाइसेंस को रद्द किया जाएगा।

रोप-वे प्रणाली के अध्ययन के लिए राज्य के प्रतिनिधिमण्डल ने किया बोलीविया का दौरा

द रीव टाइम्स ब्यूरो

मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव संजय कुंडू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने बोलीविया, स्विटजरलैंड और ऑस्ट्रिया का दौरा किया। दौरे के दौरान प्रतिनिधिमण्डल ने शहरी और ग्रामीण परिवहन के समाधान के लिए रोप-वे प्रणाली का अध्ययन कर विश्व की श्रेष्ठ रोप-वे कम्पनी की विनिर्माण इकाईयों का दौरा किया।

संजय कुंडू ने कहा कि प्रतिनिधिमण्डल ने 16 मई को ऑल्टेन में स्विटजरलैंड के रोप-वे केबिन के निर्माता कैरोसेरी वर्के आरबर्ग (सीडब्ल्यूए) का दौरा किया। उन्होंने कहा कि इस कंपनी की स्थापना वर्ष 1939 में हुई थी और बाद में यह डॉप्लेमर गारावेंटा समूह का हिस्सा बन गई। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमण्डल ने विनिर्माण इकाई के दौरे के दौरान सामग्री और विनिर्माण प्रक्रिया की गुणवत्ता का अध्ययन किया तथा विभिन्न एप्लीकेशनों के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के केबल कार केबिनों के बारे में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमण्डल ने सीडब्ल्यूए की प्रबंधन समिति तथा इंजीनियरों के साथ बैठक की और यात्रियों की सुरक्षा की गुणवत्ता के प्रति विश्वास व्यक्त किया। अतिरिक्त प्रधान सचिव ने कहा कि प्रबंधन ने शहरी, ग्रामीण, दूरदराज तथा पर्यटन परिवहन के अनुकूल मोनोकेबल, बाईकेबल, ट्राईकेबल, स्काई लिफ्ट तथ केबल कार पर विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमण्डल ने रोप चालित परिवहन की विभिन्न एप्लीकेशनों के बारे में जाना और इसे हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में इसके प्रयोग पर परिचर्चा की गई। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमण्डल ने विनिर्माण इकाई का भी दौरा किया तथा रोप-वे के निर्माण की प्रत्येक प्रक्रिया को विस्तार से जाना।

प्रतिनिधिमण्डल ने बोलीविया के ला पाज में अध्ययन दौरे के उपरान्त स्विटजरलैंड तथा ऑस्ट्रिया में केबिन और रोप-वे निर्माण इकाईयों का दौरा किया।

प्रतिनिधिमण्डल के अन्य सदस्यों में प्रधान सचिव परिवहन जगदीश चन्द्र शर्मा, रोप-वे निगम के मुख्य महाप्रबन्धक अजय शर्मा, रोप-वे निगम के महाप्रबन्धक रोहित ठाकुर तथा वाटर एण्ड पावर कंस्लटेंसी सर्विसिज (वापकोस) के प्रबंधक प्रभाकर सती भी उपस्थित थे।

पेज 1 का शेष

केन्द्रीय मंत्री और उनके मंत्रालयों की सूची 2019

सदानंद गौड़ा	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
निर्मला सीतारमण	वित्त एवं कॉरपोरेट मामले का मंत्रालय
एस. जयशंकर	विदेश मंत्री
राम विलास पासवान	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
नरेंद्र सिंह तोमर	कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय
रविशंकर प्रसाद	कानून एवं न्याय, संचार और इलेक्ट्रानिक एवं सूचना मंत्रालय
हरसिमरत कौर बादल	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
रमेश पोखरियाल निशंक	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
थावर चंद गहलोत	सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय
अर्जुन मुंडा	आदिवासी मामलों का मंत्रालय
स्मृति ईरानी	महिला एवं बाल विकास और कपड़ा मंत्रालय
हर्षवर्धन	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विज्ञान और प्रोद्योगिकी, भूविज्ञान मंत्रालय
प्रकाश जावड़ेकर	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
पीयूष गोयल	रेलवे और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
धर्मेंद्र प्रधान	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्रालय
मुख्तार अब्बास नकवी	अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय
प्रह्लाद जोशी	संसदीय मामले, कोयला और खान मंत्रालय
महेंद्र नाथ पांडेय	कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
अरविंद सावंत	भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय
गिरिराज सिंह	पशुपालन, डेयरी और मतस्य पालन मंत्रालय
संतोष गंगवार	श्रम और रोजगार मंत्रालय
राव इंद्रजीत सिंह	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन और नियोजन मंत्रालय
श्रीपद नाईक	आयुष मंत्रालय (स्वतंत्र प्रभार), रक्षा मंत्रालय (राज्य मंत्री)
जितेंद्र सिंह	पूर्वोत्तर विकास (स्वतंत्र प्रभार), पीएमओ, कार्मिक, जनशिकायत और पेंशन, परमाणु उर्जा, अंतरिक्ष मंत्रालय (राज्य मंत्री)
किरण रिजिजू	युवा मामले एवं खेल (स्वतंत्र प्रभार), अल्पसंख्यक मामले (राज्य मंत्री)
प्रह्लाद सिंह पटेल	संस्कृति और पर्यटन (स्वतंत्र प्रभार)
आरके सिंह	बिजली, नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा (स्वतंत्र प्रभार), कौशल विकास एवं उद्यमिता (राज्य मंत्री)
हरदीप सिंह पुरी	शहरी विकास और नागरिक उड्डयन मंत्रालय (स्वतंत्र प्रभार), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (राज्य मंत्री)
मनसुख मंडाविया	जहाजरानी (स्वतंत्र प्रभार), रसायन एवं उर्वरक (राज्य मंत्री)
फगगन सिंह कुलस्ते	इस्पात राज्य मंत्री
अश्विनी चौबे	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री
जनरल (रिटायर) वीके सिंह	सड़क, परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री
कृष्ण पाल गुज्जर	सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण राज्य मंत्री
दानवे रावसाहेब	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
जी. किशन रेड्डी	गृह राज्य मंत्री
पुरुषोत्तम रुपाला	कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री
रामदास अठावले	सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण राज्य मंत्री
साध्वी निरंजन	ज्योति ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
बाबुल सुप्रियो	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
संजीव कुमार बलियान	पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन राज्य मंत्री
धोत्रे संजय शमराव	मानव संसाधन विकास, संचार और इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री
अनुराग सिंह ठाकुर	वित्त और कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री
सुरेश अंगादि	रेल राज्य मंत्री
नित्यानंद राय	गृह राज्य मंत्री
वी मुरलीधरन	विदेश, संसदीय कार्य राज्य मंत्री
रेणुका सिंह	आदिवासी मामलों की राज्य मंत्री
सोम प्रकाश	वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री
रामेश्वर तेली	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
प्रताप चंद्र सारंगी	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम और पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन राज्य मंत्री
कैलाश चौधरी	कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री
देबाश्री चौधरी	महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
अर्जुन राम मेघवाल	संसदीय कार्य, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम राज्य मंत्री
रतन लाल कटारिया	जलशक्ति और सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण राज्य मंत्री
गजेंद्र सिंह शेखावत	(कैबिनेट) जल शक्ति मंत्रालय

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

जिला के 331 नए किसान करेंगे प्राकृतिक खेती

द रीव टाइम्स ब्यूरो

जिला कृषि प्रौद्योगिकी विभाग ने प्राकृतिक खेती के लिए 331 नए किसानों का चयन किया है। विभाग प्राकृतिक खेती करने वाले इन नए किसानों को जीरो बजट खेती के विशेष टिप्स दिलवाएगा । शिमला से यह किसान सोलन में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण में जाएंगे । इस दौरान उन्हें पद्म श्री सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के टिप्स देंगे । वहीं, प्रशिक्षण लेने के बाद ये फार्मर्स दूसरे किसानों को प्राकृतिक खेती को लेकर प्रशिक्षित करेंगे । बता दें कि शिमला जिला में पहले से ही लगभग 500 किसान प्राकृतिक खेती के माध्यम से सब्जियों और सेब की अच्छी पैदावार कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती से एक साल में फायदा ले रहे किसानों की अच्छी पैदावार को देखते हुए अन्य किसानों के भी आवदेन जिला कृषि विभाग में आए हैं। यही वजह है कि कृषि विभाग अब सभी किसानों को प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। भले ही ट्रेनिंग के लिए विभाग ने 331 किसानों को ही सिलेक्ट किया हो, लेकिन कृषि विभाग का मानना है कि प्रशिक्षण लेने के बाद हर ब्लॉक में जाकर ये किसान जीरो बजट खेती के बारे में दूसरे लोगों को जागरूक करेंगे। जानकारी के अनुसार कृषि विभाग ने इस साल शिमला जिला के लगभग 3000 किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने का लक्ष्य तय किया है। हालांकि जानकारी के अनुसार जिला से प्राकृतिक खेती करने के लिए किसानों के कई आवेदन भी आ रहे हैं।

दौलत सिंह पार्क में सजी पेंटिंग प्रतियोगिता

द रीव टाइम्स ब्यूरो

पूर्व उपायुक्त शिमला राजेश्वर गोयल ने अंतरराष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव की कड़ी के रूप में दौलत सिंह पार्क में दो दिवसीय अंतरविद्यालय स्थलीय चित्रकला की कनिष्ठ वर्ग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया । राजेश्वर गोयल ने इस अवसर पर कहा कि अंतरराष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव का मुख्य उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना एवं देश और प्रदेश की समृद्ध संस्कृति को जन-जन तक पहुंचाना है। उपायुक्त ने कहा कि इस उत्सव के माध्यम से उभरती प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मंच भी प्रदान किया जाता है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित करवाने से समूचे क्षेत्र की प्रतिभाओं को स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है। उपायुक्त ने प्रतियोगिता के लिए उपस्थित छात्रों से आग्रह किया कि वे पढ़ाई के साथ-साथ विभिन्न रचनात्मक कार्यों में भाग लें। उन्होंने कहा कि सभी में कुछ न कुछ प्रतिभा होती है और उचित प्रोत्साहन एवं नियमित अभ्यास से प्रतिभा विश्व पटल पर अपनी पहचान बना सकती है। प्रतियोगिता के प्रथम दिवस शिमला एवं आसपास के 20 विद्यालयों के 7वीं से 9वीं कक्षा के 40 विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के दूसरे दिन 28 मई वरिष्ठ वर्ग में 20 विभिन्न विद्यालयों के 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थी भाग लेंगे। चित्रकला प्रतियोगिता में चित्रण के लिए पर्यावरण, स्वच्छ शिमला तथा अंतरराष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव विषय दिए गए थे। भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग के कॉमर्शियल आर्टिस्ट प्रीतम पाल शर्मा, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के सहायक प्राध्यापक बलविंद्र कांगड़ी और व्यावसायिक कलाकार दिनेश अत्री प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल के रूप में उपस्थित रहे। कनिष्ठ वर्ग में दयानंद पब्लिक स्कूल शिमला की वंशिका प्रथम, ताराहाल पब्लिक स्कूल की विशुधा सूद द्वितीय और डीएवी लक्कड़ बाजार की साक्षी शर्मा तृतीय स्थान पर रही। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला संजौली के सुनील कुमार को सांत्वना पुरस्कार के लिए चुना गया। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कानून एवं व्यवस्था प्रभा राजीव, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी प्रोटोकोल नरेश ठाकुर, जिला भाषा अधिकारी त्रिलोक सूर्यवंशी, जिला पर्यटन अधिकारी सुरेंद्र जस्टा, अध्यापक तथा प्रतिभागी उपस्थित रहे।

नए ओपीडी ब्लॉक को ट्रॉमा सेंटर के लिए करें इस्तेमाल: हाईकोर्ट

द रीव टाइम्स ब्यूरो

प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में ट्रॉमा सेंटर बनाने संबंधित मामले में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश व न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर की खंडपीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिए कि आईजीएमसी शिमला में जब तक ट्रॉमा सेंटर का निर्माण नहीं हो जाता तब तक नये ओपीडी ब्लॉक के धरातल व प्रथम मंजिल को ट्रॉमा सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। इसे सुचारु रूप से चलाने के लिए बचे हुए उपकरण इत्यादि जल्द से जल्द खरीद लिए जाएं।

कोर्ट ने आदेश दिए कि इंदिरा गांधी मेडिकल शिमला कॉलेज में 30 जून तक ट्रॉमा सेंटर को सभी उपकरणों व संसाधनों के साथ गतिशील कर दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि अगर कार्य को लेकर किसी भी तरह की अड़चन सामने आ रही है तो उस बाबत न्यायालय को सूचित किया जाए।

कोर्ट को बताया गया कि राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में ट्रॉमा सेंटर पहले ही अस्थाई तौर पर कैजुअल्टी ब्लॉक में स्थापित कर लिया गया है व ट्रॉमा सेंटर ने काम करना शुरू कर लिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार को आदेश जारी किए हैं कि राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज में ट्रॉमा सेंटर को लेवल 2 से लेवल 1 में तब्दील करने के लिए जल्द निर्णय लें। वहीं मंडी के नेरचौक में ट्रॉमा सेंटर खोलने संबंधित मामले पर कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश जारी किए कि वह शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट को बताएं कि उनके द्वारा स्वीकृत 81 लाख की राशि का उपयोग किस तरीके से किया गया।

हमीरपुर में ट्रॉमा सेंटर खोलने को लेकर न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश जारी किए हैं कि जब तक ट्रॉमा सेंटर का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो जाता है तब तक नए ब्लाक में ट्रॉमा सेंटर खोलने के लिए विचार करें। न्यायालय ने स्टेटस रिपोर्ट के माध्यम से न्यायालय को अवगत करवाने के आदेश जारी किए हैं लेवल 3 के ट्रॉमा सेंटर ऊना, रिकांगपिओ, कैलोग धर्मपुर, नूरपुर, नालागढ़, जोगिंदरनगर, पालमपुर व नाहन में स्थापित करने के लिए कदम उठाने के आदेश जारी किए हैं। न्यायालय ने केंद्र सरकार को आदेश दिये हैं कि वह नेशनल हेल्थ मिशन के तहत स्वीकृत 8.29 करोड़ की राशि को 4 सप्ताह के भीतर जारी कर दे व केंद्र सरकार को इस बाबत शपथ पत्र दाखिल करने के आदेश जारी किए हैं। न्यायालय ने अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य को अपना शपथपत्र दाखिल करने के आदेश जारी किए। मामले पर सुनवाई 15 जुलाई को होगी।

सुन्नी में पानी की क़िल्लत

द रीव टाइम्स ब्यूरो

शिमला ग्रामीण की नगर पंचायत सुन्नी में पेयजल किल्लत को देखते हुए सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य उपमंडल सुन्नी की ओर से उठाऊ पेयजल योजना हेतु तैयार की गई डीपीआर वांछित बजट उपलब्ध न होने के कारण ठन्डे बस्ते में पड़ी है। क्षेत्र में बने वर्षों पुराने पेयजल स्त्रोत से हजारों लोगों को उपलब्ध कराए जाने वाले पानी की मात्रा बढ़ाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा नई योजना तैयार की गई है। लगभग सात महीने पहले तैयार की गई उपरोक्त योजना फाइलों में ही दबकर रह गई है और इस बीच सुन्नी में पेयजल की स्थिति खराब हो चली है जिससे लोगों में हाहाकार मचा है। विभाग का दावा है कि 21करोड़ 11लाख रुपये की अनुमानित लागत से तैयार होने वाली उपरोक्त पेयजल योजना से पूरे नगर पंचायत के अलावा साथ लगती एक दो पंचायतों के लोगों को भी पेयजल की कमी पूरी हो जाएगी परंतु ऐसा कब होगा यह सोचने की बात है। क्षेत्र की मदरेच खड्ड पर बनने वाली उठाऊ पेयजल योजना के लिए सरकार द्वारा वांछित राशि उपलब्ध करवाने के बाद ही योजना मूर्त रूप लेगी। बता दें कि नगर पंचायत सुन्नी में पिछले कुछ वर्षों से पेयजल की काफी समस्या है। अकसर गर्मियों में लोगों को पीने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ता है। बेतहाशा गर्मी में लोगों को पानी के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। यही नहीं आवश्यक सेवाओं अस्पताल, शिक्षा संस्थानों में भी पानी की खासी दिक्कत रहती है।

अंबिका की पेंटिंग... रंग अनेक, संदेश एक

द रीव टाइम्स ब्यूरो

राजधानी शिमला के गेयटी थियेटर में महासू आर्ट कला संस्था द्वारा चित्रकला प्रदर्शनी चलाई जा रही है। इस चित्रकला प्रदर्शनी में हिमाचल प्रदेश सहित बाहरी राज्यों से भी कलाकार भाग ले रहे हैं। महासू कला संस्था एक ऐसी कला संस्था है जो हर आर्टिस्ट की कला के महत्व को समझती है। महासू आर्ट संस्था खास तौर पर युवाओं को चित्रकला करने के लिए प्रेरित करती है। इस संस्था से जुड़े चित्रकार न केवल हिमाचल प्रदेश अपितु बाहरी राज्यों में भी अपनी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। शिमला की अंबिका की चित्रकला गेयटी में खूब पंसद की जा रही है।

सांगला की पहाड़ियों से निकाले लापता सैलानी

द रीव टाइम्स ब्यूरो

सांगला के रोंटीगाड में लापता पांच ट्रैकर्ज को रेस्क्यू कर लिया गया है। सांगला में सुरक्षित पहुंचाया गया। इसके बाद स्थानीय अस्पताल में उपचार के बाद उन्हें टैक्सी के माध्यम से दिल्ली भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र व बंगाल के 14 ट्रैकर्ज का एक ग्रुप उत्तराखंड के दौला से सेवा, जिसगुन व जाखा होते हुए रोंटीगाड की प्राकृतिक सुंदरता को निहारते हुए सात दिनों बाद रूपिन पास पहुंचा था, जहां भारी बर्फबारी के बीच पांच ट्रैकर्ज फंस गए, जिनमें दो महाराष्ट्र व तीन बेस्ट बंगाल के थे। इसकी सूचना उनके दल में शामिल अन्य नौ सैलानियों ने कैंप ऑर्गेनाइजर सांगला निवासी ओंकार नेगी को दी। इस पर ओंकार नेगी ने पुलिस थाना सांगला को सूचित किया। पुलिस थाना सांगला से आरक्षी पंकज व मनोज कुमार की अगवाई में स्थानीय निवासी ओंकार नेगी, जितेंद, अप्पु पुजारी, राजदीप भंडारी, इवान नालंदा सहितस्थानीय लोगों की टीम ने तीन फुट बर्फबारी के बीच लापता ट्रैकर्ज की तलाश की। 10 घंटे बाद आखिर उन्हें रविवार देर शाम सुरक्षित निकाल लिया गया। लापता ट्रैकर्ज में एस्टन यूस्टर पुत्र मिस्किटा, देवा ज्योति पुत्र प्रदीप कुमार, प्राची नंद पुत्री नंद कुमार, सिद्धार्थ पुत्र समर कुमार व पियूष नाथ पुत्र देव देवव्रत शामिल थे। प्राथमिक उपचार के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सांगला में पहुंचाया गया, जहां से उन्हें टैक्सी के माध्यम से दिल्ली रवाना किया गया।

मज्याठ की जनता सड़क सुविधा से महरुम

द रीव टाइम्स ब्यूरो

नगर निगम शिमला के मज्याठ वार्ड में मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक पार्षद दिवाकर देव शर्मा की अध्यक्षता में हुई। इसमें मज्याठ वार्ड के करीब 200 लोगों ने भाग लिया। बैठक में वार्ड से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की गई। इसमें आजादी के 70 साल बाद भी सड़क सुविधा का न होना चर्चा का मुख्य विषय रहा। सड़क सुविधा न होने के कारण आपातकालीन स्थिति में मरीज, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों व बच्चों को अपने घर से सड़क तक पहुंचाने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार मरीज व गर्भवती महिलाओं को चार-चार लोगों द्वारा स्ट्रेक्चर पर ले जाया जाता है व कई बार समय पर स्वास्थ्य सुविधा न मिलने पर जान भी जा चुकी है। पार्षद दिवाकर देव ने कहा कि विगत वर्ष 2018 में गर्मियों के मौसम में जल संकट के दौरान विभिन्न वार्डों में टैंकर से पानी की आपूर्ति की गई थी, मगर सड़क सुविधा न होने के कारण भाग संख्या-7 मज्याठ में पानी की आपूर्ति नहीं की जा सकी, जिससे वार्ड के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

लोगों को रैडक्रास के कार्यों में भाग लेने तथा समाज के कल्याण के लिए निःस्वार्थ भाव व आपसी सहयोग से कार्य करने को कहा।

गुस्साए जेबीटी प्रशिक्षुओं ने निकाली रैली

द रीव टाइम्स ब्यूरो, किन्नौर

बीएड धारकों को भी जेबीटी भर्ती के लिए मान्यता देने के फैसले का विरोध करते हुए 28 मई को किन्नौर जिला जेबीटी बेरोजगार प्रशिक्षुओं व जिला शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थान रिकांगपिओ संघ ने रैली निकाल कर विरोध प्रदर्शन किया। रैली के बाद सहायक आयुक्त सलीम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। जेबीटी प्रशिक्षु इस बात का विरोध कर रहे थे कि बीएड करने वाले जेबीटी के पाठ्यक्रम में काफी अंतर है। इसी तरह बीएड प्रशिक्षु अभी तक जेबीटी टेट पास नहीं हैं। और न ही जेबीटी टेट के लिए बीएड कोई योग्यता है। ऐसे में जेबीटी कमीशन में भाग लेने का मौका दिया जाता है तो टेट पास जेबीटी अभियर्थियों के साथ अन्याय होगा। जिला शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थान रिकांगपिओ के जेबीटी संघ उपाध्यक्ष पूर्ण चंद, सचिव प्रकाश आंनद व मीडिया प्रभारी सुभाग नेगी ने कहा कि बीएड को जेबीटी भर्ती में शामिल नहीं किया चाहिए। ऐसा करने से उन के साथ सरासर बेइनसाफी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में बीस हजार से ज्यादा जेबीटी डिप्लोमा धारक हैं। बीएड को भर्ती के लिए मान्य करने से इनका भविष्य खतरे में पड़ गया है। उन्होंने मांग किया कि जेबीटी कमीशन के लिए जो परीक्षा ली थी, उस मे 36 हजार अभ्यर्थीयों ने भाग लिया है। बीएड डिग्री धारगो को पात्र न मान कर उन्हें उक्त परिक्षा के परिणाम में शामिल ना किया जाए।

निगम कर्मचारियों की बढ़ी तनख्वाह, पार्किंग प्लान को भी मंजूरी

द रीव टाइम्स ब्यूरो

दो माह बाद हुई नगर निगम की वित्त संविदा एवं योजना समिति की मासिक बैठक में कई राहत भरे फैसले लिए गए। 28 मई को महापौर कुसुम सदरेट की अध्यक्षता में हुई बैठक में नगर निगम के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों और डाटा एंट्री ऑपरेटरों की तनख्वाह बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। निगम में तैनात जिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने 20 साल नियमित सेवाकाल पूरा कर लिया है, उन्हें प्रदेश सरकार की तर्ज पर एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि मिलेगी। इसी तरह डाटा एंट्री ऑपरेटरों का दैनिक वेतन 267 से बढ़ाकर 292 रुपये, दैनिक भोगी कर्मचारियों का दैनिक वेतन 225 से बढ़ाकर 250 रुपये प्रतिदिन किया है। इससे 18 डाटा एंट्री आपरेटरों समेत कुल 24 कर्मचारियों को फायदा होगा। यह वेतन अप्रैल से देय होगा। बैठक में दो सुपरवाइजरों को मार्च से सितंबर 2018 तक लंबित वेतन देने को भी मंजूरी दी गई। कमेटी ने नगर निगम के सदन की प्रक्रिया को पेपरलेस करने के लिए ई-विधान साफ्टवेयर तैयार करने का भी फैसला लिया है। इस पर 14.39 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। एफसीपीसी के फैसलों पर बुधवार को होने वाली नगर निगम की मासिक बैठक में अंतिम मुहर लगाई जाएगी।

एफसीपीसी में 19.34 लाख रुपये से कच्चीघाटी के चक्कर कोर्ट रोड से संदल धर के लिए एंबुलेंस रोड बनाने को भी मंजूरी दी है। इसी वार्ड में 20 लाख रुपये से नाले का चौनलाइजेशन किया जाएगा। फागली में आरसीसी नाला बनाने, ढींगूधार 11 लाख रुपये से रास्ते पर रेड स्टोन लगाने, नगर निगम के लिए दो नए हैंड रोलर खरीदने, छोटा शिमला से कसुम्पटी रोड वाया ब्रॉकहास्ट निगम से लोनिवि को सौंपने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

सोलन शहर में सक्रिय लुटेरा गिरोह का पर्दाफाश

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सोलन

शहर में सक्रिय ठगों के गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। कई टोलियों में विभाजित यह गिरोह परिवार समेत सोलन शहर में लोगों को ठग रहा था। इस गिरोह में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इनमें कई परिवारों का समूह है, जो शहर में लोगों को मूर्ख बनाकर उनसे पैसे ऐंठ रहा था। बीते दिनों पुराने बस स्टैंड पर जब गिरोह के कुछ लोग पैसे की उगाही कर रहे थे तो स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत बस स्टैंड में बने पुलिस बूथ में कर दी। इस पर पुलिस ने दो महिलाओं और दो पुरुषों को काबू कर लिया और उनसे पूछताछ की तो वे सही जवाब नहीं दे पाए। इस पर बूथ में तैनात पुलिस कर्मियों ने शहरी चौकी में इस घटना की सूचना दे दी। इसके बाद वहां से मौके पर आए पुलिस कर्मचारियों ने सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया और पूछताछ के लिए चौकी ले गए। ये सभी आरोपी काफी समय से सोलन शहर में घूम रहे थे और हर शहरवासी से धोखे से यहां बुलाए जाने या ट्रेन में जेब कटने की बात कहकर पैसे ऐंठ रहे थे। इस गिरोह ने शहर के कई लोगों को बेवकूफ बनाकर हजारों रुपये ऐंठ लिए थे, लेकिन कुछ लोगों ने मामला पुलिस के पास उजागर कर दिया। इसके बाद इन सबके कारनामे का खुलासा हो गया। पूछताछ में पता चला है कि 20 से 25 लोगों का समूह शहर में सक्रिय है। जिनमें बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। यह लोग जेब कटने या मजदूरी के लिए बुलाने और काम न देने की बात करते हैं। जो लोग इनके झांसे में आते हैं वे उनसे बड़ा परिवार होने का बहाना बनाकर खाने और रहने के नाम पर पैसे मांगते हैं। उधर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार का कहना है कि मामले की जांच की जाएगी। उन्होंने लोगों को ठगी से सजग रहने की सलाह दी है। साथ ही आह्वान किया है कि ऐसी शिकायत पुलिस में जरूर करें।

प्राथमिक स्कूलों में 68 शिक्षकों के पद खाली

द रीव टाइम्स ब्यूरो, ऊना

एक तरफ सरकार प्राथमिक स्कूलों में नई से नई योजनाओं को सफल बनाकर शिक्षा का स्तर उठाने के लिए नीतियां बना रही है दूसरी ओर सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकार स्कूलों में शिक्षकों के पद भरे बिना ही मात्र योजनाओं के दम पर ही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना चाह रही है। अगर स्कूलों में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए गुरुजी ही नहीं होंगे तो सरकार कैसे सरकारी स्कूलों में शिक्षा की दशा सुधार पाएगी। विभागीय आंकड़ों के अनुसार जिले के 499 प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 68 पद खाली चल रहे हैं। जिला में 56 स्कूल ऐसे हैं जो एक शिक्षक के सहारे चल रहे हैं तो वहीं, 17 स्कूलों में जेबीटी शिक्षकों के पद खाली पड़े है और 20 प्राथमिक स्कूल ऐसे हैं, जिनमें स्कूल हेड टीचर ही नहीं है। गौरतलब है कि जिले तीन प्राथमिक स्कूल सनोह, डीहर व झोड़ोवाल में साढ़े तीन वर्ष से कोई भी शिक्षक नहीं है। हैरानी है कि जिले में एक शिक्षकों पर दो-दो स्कूलों की भी जिम्मेदारी डाली गई है। लेकिन सरकार की ओर से शिक्षकों की भर्ती पर जोर कम और नई से नई योजनाओं को शुरू करने के लिए ज्यादा जोर दिया जा रहा है।

एकल अध्यापक वाले प्राथमिक स्कूल

एकल अध्यापक वाले प्राथमिक स्कूलों में कन्यारी, गंगोटी, घगोह, सपौरी, खरोटा, बीहड़ी, नलोह, भरोबड़, पौलियां पुरोहितां, कुच्चां, मंझार, बडोह बरोरा, सूरी, जबेहड़, तलवाल, सलूरी, भलोला, वडसाला, टकोली, नदंग्रा, बडूहा, कुंड, पंजावर बाल स्कूल, जोहवह, भरमौत, मंझियानी, बल्ह, कोठी, बूसल, घरवासड़ा, ढोल माझर, लोअर कुठारवीत, बढ़वार, सलोह बैरी अप्पर, नंगल कलां, नंगल बट्ट, लोअर नंगल खुर्द, लोअर ललहड़ी, बढेड़ा लोअर, ईसपुर लवाणा, गुगलैहड़, मवा सिंधियां, टटेहड़ा, कलोह, बहडाला, बसाल, बासड़ा, खरोह, बधमाणा, अमोलका प्रीतम, गुरेट, काशीपुर, खरियाली, बडबक्शी टकोली, अरडोह, दलोह आदि शामिल है।

बिना जेबीटी व एचटी वाले स्कूल

जेबीटी के खाली पदों वाले स्कूलों में रपोह, बल्ह, घरवासड़ा, गुगलैहड़, बढेड़ा राजपूतां, मवा सिंधियां, टटेहड़ा, रक्कड़, बुधान, लठियाणी, बंगाणा, थानाकलां, मंदली, रायपुर, बोहरन, ओयल और पिरथीपुर स्कूल शामिल हैं। मुख्याध्यापक के खाली पदों वाले स्कूलों में घगोह, नलोह, सूरी, सलूरी, बडसाला, टकोली, धर्मशाला महंता केंद्र, कुनेरन, गिंडपुर मलोण, घरवासड़ा, नलबाड़ी, झोड़ोवाल, बासड़ा, बढेहर, खबाजा, पंजावर अप्पर, जोहवह, बुबलू, चलेट अपर और सलोह बैरी अपर स्कूल शामिल हैं।

शिक्षा विभाग का कारनामा, दो स्कूलों में पढ़ा रहा एक शिक्षक

द रीव टाइम्स ब्यूरो, ऊना

सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर उठाने के लिए जहां सरकार लगातार प्रयास कर रही है तो वहीं शिक्षा विभाग ने एक शिक्षक पर दो-दो स्कूलों की जिम्मेदारी सौंपी दी है। उपमंडल अंब क्षेत्र के तहत दो सरकारी स्कूलों की जिम्मेदारी एक शिक्षक के सिर पर डाली गई है। प्राथमिक स्कूल नलोह में एकमात्र शिक्षक है। सनोह स्कूल को कम विद्यार्थी होने के कारण सरकार ने बंद कर दिया था, लेकिन बाद में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने पर लोगों के विरोध को देखते हुए शिक्षा विभाग ने सनोह स्कूल को नलोह स्कूल की एक शाखा बना दिया। इससे अब नलोह स्कूल का एकमात्र शिक्षक दोनों स्कूलों को संभाल रहा है। इससे एक साथ दो स्कूलों के विद्यार्थियों की पढ़ाई खराब हो रही है। नलोह स्कूल के शिक्षक दिनेश कुमार ने कहा कि उन्हें नलोह स्कूल के साथ सनोह स्कूल का भी इंचार्ज बनाया गया है। इससे दोनों स्कूलों के विद्यार्थियों की पढ़ाई खराब हो रही है। क्योंकि एक स्थायी शिक्षक विद्यार्थियों को जो शिक्षा देता है वह शिक्षा डेपुटेशन पर विद्यार्थियों को नहीं मिल सकती। 10 दिन एक स्कूल में तो 10 दिन दूसरे स्कूल में विद्यार्थियों को पढ़ाना पड़ रहा है। साथ ही सनोह स्कूल में पढ़ाई के साथ-साथ कार्यालय का कार्य, मिड-डे मील सहित अन्य कार्य भी शिक्षक को ही करने पड़ रहे हैं। इसलिए सनोह स्कूल में विद्यार्थियों की पढ़ाई का उचित प्रबंधन होना चाहिए। नलोह स्कूल पिछले करीब तीन वर्षों से डेपुटेशन शिक्षकों के सहारे ही चल रहा है। वहीं, प्राथमिक शिक्षक संघ अंब के अध्यक्ष जगदेव सिंह जगी ने शिक्षा विभाग से इस समस्या का जल्द समाधान निकालने की मांग की है। वहीं, प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक संदीप कुमार गुप्ता ने कहा कि इस संबंध में उन्हें जानकारी नहीं थी। लेकिन अब जल्द ही सनोह स्कूल का कार्यभार दो या इससे अधिक शिक्षक वाले स्कूल को दिया जाएगा। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो।

सिरमौर में हांफ गई थी ईवीएम, वीपीपैट मशीनें

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सिरमौर

बीते 19 मई को हुए विभिन्न स्थानों पर ईवीएम हांफ गई थी। इसी दौरान सिरमौर जिले में कई मतदान केंद्रों में समय पर मतदान शुरू नहीं हो पाया। ईवीएम व वीवीपेट मशीनों में तकनीकी खराबी आने की वजह से यह समस्या पेश आई। हालांकि, निर्वाचन विभाग की ओर से पोलिंग स्टेशनों पर अतिरिक्त ईवीएम व वीवीपेट मशीनों का प्रबंध किया गया था। कई केंद्रों में एक तो कहीं दो घंटा देरी से मतदान शुरू हुआ। इसके कारण सुबह छह बजे से मतदान केंद्र पहुंचे लोगों को घंटों तक इंतजार करना पड़ा। बताया जा रहा है कि जिले के कई दुर्गम पोलिंग स्टेशनों में भी मतदाता सुबह से ही अपने मत के प्रयोग के लिए पहुंचे थे। लेकिन, मशीनों में खराबी के चलते देरी से मतदान करना पड़ा। कई जगह मतदाताओं को दो घंटे से अधिक समय तक मशीन के बदलने का इंतजार करना पड़ा। नाहन विधानसभा क्षेत्रों में भी करीब एक दर्जन स्थानों पर समय पर मतदान शुरू नहीं हुआ। मतदान केंद्र ढाबों मोहल्ला, डाइट स्थित पोलिंग स्टेशन में करीब एक घंटा देरी से मतदान शुरू हुआ। पच्छाद निर्वाचन क्षेत्र में दस मतदान केंद्रों में वीवीपेट मशीनें बदलनी पड़ीं। जबकि एक मतदान केंद्र पर पूरा सिस्टम ही बदला गया। पच्छाद निर्वाचन क्षेत्र के क्लयों पाब, जदोल टपरोली, करगाणु, पबियाना, कुलथ, कालाघाट, जेहर, सराहां-1 व श्यामपुर में वीवीपैट बदली गईं। जबकि सादनाघाट में भी वीवीपैट बदलनी पड़ी। संगड़ाह बूथ नंबर एक में वीवीपैट के खराब होने पर करीब 50 मिनट, बूथ 2 पर 1 घंटा 45 मिनट मतदान शुरू नहीं हो सका। सेंज बूथ पर में तीन घंटे वीपीपैट मशीनें बंद रहीं। इसके अला लगनू और सियूं में भी देरी से मतदान शुरू हुआ। कमरऊ में मतदाताओं की लगी लंबी कतारें लगी रहीं। यहां भी मशीनों में तकनीकी खराबी के कारण समय पर मतदान शुरू नहीं हो सका। पांवटा के नघेता में भी कई घंटे बाद मतदान शुरू हो सका। नौहराधार तहसील के देवामानल बूथ पर ईवीएम खराब होने पर एक घंटे देरी से वोटिंग शुरू हुई।

दवा उद्योग में लगी आग, लाखों का नुकसान

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सोलन

बरोटीवाला के समीप झाड़माजरी औद्योगिक निर्यात प्रोत्साहन पार्क फेस वन में एक दवा उद्योग में आग लग गई। इससे लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। आग लगने का कारण शहर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग लगने की सूचना स्थानीय लोगों ने उद्योग के मालिक को दी। इसके बाद इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग की टीम के मौके पर पहुंचने से पहले ही लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मिली जानकारी के अनुसार झाड़माजरी के समीप एक दवा उद्योग में अचानक आग लग गई। जैसे ही इसका पता उद्योग में मौजूद कामगारों को लगा तो वे तुरंत बाहर निकल गए। इसके बाद इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई। वहीं स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। उधर, उद्योग के संचालक सुरेश पाठक ने बताया कि अचानक आग लग गई। कुछ मशीनें, कच्चा माल व तैयार माल जलकर राख हो गया। कंपनी मालिक ने तुरंत इसकी सूचना फायर विभाग को दी। सुरेश पाठक ने बताया कि जिस कमरे में आग लगी थी उसमें इंजेक्शन बनाने के लिए प्रयोग होने वाला कच्चा माल रखा हुआ था। उन्होंने कहा कि कच्चा माल, तैयार माल व मशीनरी नष्ट हुई है। उन्होंने बताया कि आग से लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। फायर ऑफिसर ने बताया कि टीम के पहुंचने से पहले ही आग पर काबू पा लिया गया था।

सुनियोजित तरीके से फरार हुआ कैदी

द रीव टाइम्स ब्यूरो, ऊना

कस्बा मैहतपुर में बीते दिनों एचआरटीसी बस से फरार हुए हत्या मामले के सजायाफ्ता कैदी के फरार होने का प्लान पहले ही बन चुका था। इसका खुलासा तेजी से वायरल हो रही मैहतपुर बाजार में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से हुआ है।

मैहतपुर में कैदी राजीव कौशल के साथी उसे भगाने के लिए पहले से तैयार थे। इतना ही नहीं अपने साथी को भगाने के लिए वे बाइक पर बस का पीछा भी कर रहे थे। जैसे ही बस मैहतपुर में सवारियां चढ़ाने के लिए रुकी, कैदी के शातिर साथियों ने भी बाइक को ठीक बस के पीछे खड़ा कर दिया। पहले से तैयार राजीव कौशल ने बस में से फौरन छलांग लगाई और बाइक पर साथियों के साथ बैठकर फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई घटना को देखकर लगता है कि राजीव का फरार होने होने का प्लान पहले ही बन चुका था। हालांकि बस से उतरे पुलिस कर्मी ने भी राजीव को पकड़ने का भरसक प्रयास किया, लेकिन कुछ ही दूरी से वह बाइक पर भागने में सफल रहा। बाइक सवार राजीव को मैहतपुर मेन बजार से रेलवे रोड की ओर ले गए।

राजीव ने दूसरी बार खाकी को चकमा दिया है। राजीव को बाइक पर भगाने वाले दो युवक कौन हैं, इसका अभी कोई पुख्ता सुराग नहीं लग पाया है। हालांकि पुलिस ने हर पहलू की जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि फरवरी 2013 में मैहतपुर में हुए उद्योगपति हत्याकांड में राजीव मुख्य आरोपी बनाया गया था।

71 वर्ष बाद भी नहीं बनाई सड़क

द रीव टाइम्स ब्यूरो, ऊना

उपतहसील जोल की ग्राम पंचायत टकोली के बनाडी (उपली बेहलां) गांव की हरिजन आबादी, जट्टा आबादी, राजपूत बस्ती के लोगों को आजादी के 71 साल बाद भी सड़क नहीं मिल पाई है। लोगों के लिए घर द्वार तक सुविधा पहुंचना अब भी सपने जैसा है। ग्रामीणों को घर-द्वार तक पहुंचने के लिए खड्ड के रास्ते से तीन किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। ग्रामीणों का आरोप है कि चुनावी दिनों में नेता सड़क बनाने के वायदे तो करते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद सब भूल जाते हैं। ग्रामीण लंबे समय से सड़क सुविधा को जोड़ने की मांग कर रहे हैं। आज दिन तक लोगों की मांग पूरी नहीं हो सकी। उपली बेहलां सड़क सुविधा से न जुड़ने के कारण रोजमर्रा का सामान सिर पर उठाकर पैदल जाना पड़ता है। विद्यार्थियों को पैदल खड्ड के रास्ते से स्कूल जाना पड़ता है। बरसात में तो हर समय अनहोनी घटना की शंका बनी रहती है। इस कारण बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ता है। अगर कोई ग्रामीण बीमार हो जाता है, तो उसे पीठ पर उठाकर मुख सड़क तक पहुंचाना पड़ता है। बनाडी (उपली बेहलां) निवासी हरनाम सिंह, केवल कुमार, जगतार सिंह, जुल्फी राम, ब्यासा देवी, बारू राम, जोगिंद्र सिंह, महेंद्र सिंह, राज कुमार, पुष्पा देवी, कमला देवी, रोशन लाल, हंसराज, जीत सिंह, बिट्टू, पवन कुमार का कहना है कि प्रदेश के कई सरकारें आईं लेकिन मात्र भरोसा देकर वोट हथियाए। टकोली पंचायत प्रधान मंगल सिंह ने कहा कि जल्द ही इस समस्या को सरकार के पक्ष में रखा जाएगा। टकोली-चोली बीडीसी सदस्य राधा रानी ने कहा कि कई बार इस समस्या को विधायक और सांसद को इस समस्या के बारे में अवगत करवाया, लेकिन आज तक कोई हल नहीं हुआ। ग्रामीणों ने गांव की अनदेखी पर चुनावों का बहिष्कार करने तक की चेतावनी दे डाली है।

पानी का दुरुपयोग किया तो कटेगा कनेक्शन

द रीव टाइम्स, सिरमौर

गर्मियों के मौसम में पानी के कनेक्शन से टुल्लू पंप लगाना उपभोक्ताओं को भारी पड़ सकता है। आईपीएच विभाग ने ऐसा करने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने की चेतावनी जारी की है। विभाग का कहना है कि ऐसे उपभोक्ताओं के पानी के कनेक्शन बिना किसी पूर्व सूचना के काट दिए जाएंगे। साथ ही उनके टुल्लू पंप भी जब्त कर लिए जाएंगे। विभाग ने गर्मियों के मौसम में होने वाली पानी की किल्लत से निपटने के लिए कमर कस ली है। एक ओर विभाग ने जहां सभी विभागीय कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं, उपभोक्ताओं से भी पानी का उपयोग सोच समझकर करने की अपील की है। आईपीएच विभाग सिरमौर के अधिशासी अभियंता डॉ. मनदीप गुप्ता ने बताया कि विभाग सभी उपभोक्ताओं को बराबर पानी मुहैया करवाने को प्रयासरत है। यदि कोई भी उपभोक्ता पानी के कनेक्शन में टुल्लू पंप लगाता हुआ पाया जाएगा, उसका कनेक्शन बिना किसी पूर्व सूचना के अविलंब काट दिया जाएगा। साथ ही उसका टुल्लू पंप भी विभाग जब्त कर लेगा। उन्होंने कहा कि घरों की टंकियों से व्यर्थ पानी बहाने वालों के खिलाफ आईपीएच कार्रवाई करेगा। अगर कहीं पानी व्यर्थ बहता पाया गया तो विभाग बिना नोटिस पानी का कनेक्शन काट देगा। घर के कनेक्शन से गाड़ियां धोने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा। लोगों को चाहिए कि वे गर्मियों के दिनों में गाड़ी धोने में पानी व्यर्थ न गवाएं। पानी का उपयोग आवश्यकता अनुसार ही करें। यदि कहीं भी पानी की पाइप में रिसाव हो रहा हो या पाइप टूटी हो तो इसकी सूचना विभाग को दें।

अवैध खनन पर ठोका 65 हजार रुपये जुर्माना

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सरमौर

वन परिक्षेत्र भगानी के तहत खनन माफिया पर शिकंजा कसते हुए वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग की कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। बीते दिनों विभागीय टीम ने अवैध खनन करने पर ट्रक संचालकों पर 65 हजार रुपये का जुर्माना ठोका। जानकारी के अनुसार वन विभाग की टीम को सूचना मिली कि उत्तराखंड राज्य के दो ट्रक हिमाचल की सीमा में खोदरी माजरी पंचायत के निकट यमुना नदी में अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं। पिछले कुछ दिन से हिमाचल-उत्तराखंड की सीमा पर यमुना नदी में अवैध खनन माफिया वन व पुलिस प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर रेत-बजरी की तस्करी को अंजाम दे रहे थे। धरपकड़ के लिए वन विभाग की टीम सतर्क हो गई। टीम ने पुरुवाला-किल्लौड़ मार्ग पर माजरी वन बीट के गोजर गांव के पास यमुना नदी के समीप दबिश दी और रेत-बजरी ले जाते दोनों ट्रकों को दबोच लिया। ट्रक संचालक अवैध रेत-बजरी को भगानी के रास्ते उत्तराखंड ले जाने की फिराक में थे। वन परिक्षेत्र अधिकारी भगानी तरसेम सिंह की टीम में शामिल मोहन सिंह बीओ माजरी, वन रक्षक वीरेंद्र शर्मा, बलबीर सिंह, ज्योति, सचिन, वीरेंद्र चौहान व वन कर्मी किशन, सुंदर व बहादुर सिंह ने दबिश दी। टीम ने ट्रक यूके 16 सीए 0712 और यूके16 सीए 0908 को रोका तो उसमें रेत-बजरी थी, जो अवैध रूप से ले जाई जा रही थी। वन विभाग ने 65 हजार रुपये का जुर्माना ठोका। मामले की पुष्टि वन परिक्षेत्र अधिकारी भगानी तरसेम सिंह ने की है। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

पत्नी के हत्यारे पति को आजीवन कारावास, 10 हजार रुपये जुर्माना

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कांगड़ा

पत्नी की निर्मम हत्या करने के आरोपी पति को धर्मशाला कोर्ट ने आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। अगर आरोपी जुर्माना अदा नहीं कर पाएगा तो दो माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। जिला न्यायवादी स्टेट विजिलेंस भुवनेश मिन्हास ने कहा कि रत्न लाल निवासी गांव बगण तहसील बलौर जिला कठुआ, जम्मू अपनी पत्नी श्रेष्ठा देवी और दो बच्चों के साथ इंदौरा पंचायत के वार्ड नंबर दो में तरसेम लाल के घर में किराये पर कमरा लेकर रहता था। रत्न लाल अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था, जिसके चलते दोनों के बीच इसी मामले को लेकर लड़ाई-झगड़े होते रहते थे। रत्न लाल अपनी पत्नी व बच्चों को छोड़ दूसरी जगह रहने लगा था। 9 नवंबर 2016 रात लगभग साढ़े 11 बजे रत्न लाल कमरे की खिड़की की जाली तोड़कर अंदर घुसा, अंदर उनकी पत्नी व दो बच्चे सो रहे थे। इस दौरान पहले दोनों के बीच लड़ाई-झगड़ा हुआ और बाद में रत्न लाल ने चाकू निकालकर श्रेष्ठा की छाती पर वार कर दिए। घायल श्रेष्ठा बाहर निकली और मकान मालिक तरसेम के पास पहुंची। इसी बीच रत्न लाल फरार हो गया। घायल श्रेष्ठा को मकान मालिक ने पहले पीएचसी इंदौरा पहुंचाया, जहां से उसे पठानकोट रेफर कर दिया। वहीं, रत्न लाल के खिलाफ पुलिस थाना इंदौरा के शिकायत दर्ज करवाई।

पठानकोट में 10 नवंबर को पुलिस ने श्रेष्ठा देवी के बयान दर्ज किए और 11 नवंबर को उसकी मौत हो गई। रत्न लाल की गिरफ्तारी के बाद न्यायालय में पहुंचे केस में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 24 गवाह पेश किए गए। गवाहों के बयानों के आधार पर दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने दोषी रत्न लाल को उम्र कैद और जुर्माना की सजा सुनाई है।

ठगी को अंजाम देने से पहले पुलिस ने पकड़ा गिरोह

द रीव टाइम्स ब्यूरो, बिलासपुर

जिले में सोने के नाम पर नकली जेवरात का धंधा करने वाले लोगों का एक गिरोह सक्रिय है। इसके सदस्य लोगों को जेवरात चमकाने और सस्ता सोना देने के लालच देकर चुना लगाने की फिराक में थे, लेकिन इससे पहले कि उक्त लोग किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे पाते पुलिस ने विभिन्न क्षेत्रों से मिल रही सूचनाओं के आधार पर तीन लोगों को हिरासत में लिया। इसमें एक महिला भी शामिल है। ये सभी दिल्ली के रहने वाले हैं। इनके पास से पुलिस को संदिग्ध सामग्री मिली है जिसमें नकली जेवरात भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ये लोग पहले एक छोटा सा सोने का असली टुकड़ा लोगों को दिखाते थे। इसके बाद अपनी बातों में फंसा कर लोगों को पीतल के जेवरात थमा देते थे। पुलिस ने आरोपियों को उनकी फोन लोकेशन के आधार पर गिरफ्तार किया है। उल्लेखनीय है कि पुलिस को बरठीं, आवारी और कुठेड़ा क्षेत्र से लोगों की शिकायतें आ रही थीं कि कुछ लोग सोने के जेवरात के नाम पर लोगों को ठगने की फिराक में हैं। पकड़े गए लोगों ने क्षेत्र के कुछ लोगों को फोन नंबर भी दे रखे थे। इसके लोकेशन के आधार पर पुलिस ने तीनों को पकड़ा है। एसएचओ घुमारवीं राकेश रॉय ने बताया कि लोगों से मिल रही सूचनाओं के आधार पर पुलिस ने तीन लोगों को पूछताछ के लिए लाया है। इसमें एक महिला भी है। इन लोगों के पास कुछ पीतल के जेवरात भी मिले हैं। ये सभी लोग दिल्ली निवासी हैं।

नगर परिषद ने बढ़ाया अपनी 135 दुकानों का किराया

द रीव टाइम्स ब्यूरो, बिलासपुर

नगर परिषद बिलासपुर ने अपने अधीन आने वाली सभी 135 दुकानों का किराया बढ़ाने का निर्णय लिया है। आने वाले दिनों मे होने वाली हाउस की बैठक में बढ़े हुए किराये का प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके बाद दुकानदारों से बढ़ा हुआ किराया वसूल होना शुरू हो जाएगा। किराया 500 से लेकर 1200 रुपये तक बढ़ाया गया है। गौरतलब है कि बिलासपुर नगर परिषद के दायरे में 135 दुकानें आती हैं जिनसे नगर परिषद किराया वसूल करती है। यह दुकानें पूरे शहर में फैली हुई हैं। नगर परिषद इनसे 30 रुपये से लेकर 100 रुपये किराया वसूलता है जोकि कई सालों से एक जैसा ही है लेकिन अब नगर परिषद अपनी आमदन बढ़ाने के लिए किराया बढ़ाने जा रही है। नगर परिषद ने क्षेत्र के हिसाब से दुकानों का किराया भी निर्धारित कर दिया है जिसमें 500, 700, 800 व 1200 रुपये तक का किराया लेना दुकानदारों से तय किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि आज के समय में निजी दुकान मालिक इससे भी ज्यादा किराया लोगों से वसूलते हैं, ऐसे में नगर परिषद ने लोगों पर ज्यादा बोझ न डालते हुए किराये में मामूली वृद्धि की है। चुनावों के बाद इस बढ़े हुए किराये को हाउस की होने वाली बैठक में ले जाया जाएगा, जहां पर प्रस्ताव पारित करके बढ़ा हुआ किराया वसूलना शुरू कर दिया जाएगा।

कई दुकानदारों ने नहीं दिया है सालों से किराया

नगर परिषद के तहत आने वाले कई दुकानदारों ने पिछले कई सालों से किराया नहीं दिया है। किराया केवल 30 रुपये है जिसे देने में भी दुकानदार आनाकानी कर रहे हैं। दुकानदारों का हजारों रुपये किराया देने को रह गया है। नगर परिषद के अधिकारियों का कहना है कि कुछ दुकानों के मामले हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। जैसा वहां से निर्णय आएगा उस हिसाब से नगर परिषद उन दुकानदारों पर कार्रवाई करेगा।

नादौन अस्पताल में थायराइड टेस्ट व जनरेटर की सुविधा नहीं

द रीव टाइम्स ब्यूरो, हमीरपुर

सिविल अस्पताल नादौन में थायराइड टेस्ट और जनरेटर की सुविधा न होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां पर लोगों ने इन सुविधाओं को जल्द उपलब्ध करवाने की मांग मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से की है। क्षेत्र के मुकेश, विनय, राजेश, विवेक, किशोरी लाल, चमन लाल, रजनीश, विनोद, राकेश, जीवन, मनोज आदि ने कहा कि गलोड़ अस्पताल में यह सुविधा उपलब्ध है लेकिन, नादौन अस्पताल में रोगियों की संख्या अधिक होने पर भी लोगों को यह सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। नादौन अस्पताल में विधानसभा क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्रों से भी काफी संख्या में लोग अपना उपचार करवाने के लिए पहुंचते हैं।

उन्होंने कहा कि थायराइड से पीड़ित रोगियों को निजी प्रयोगशालाओं में अधिक पैसे खर्च करके यह टेस्ट करवाना पड़ रहा है। नादौन अस्पताल में जनरेटर की सुविधा भी नहीं है। अस्पताल परिसर में बिजली आपूर्ति बाधित होने पर मोमबत्तियों और मोबाइल की टॉर्च का प्रयोग करके रोगियों का उपचार करने के लिए कर्मचारियों को मजबूर होना पड़ता है। सबसे अधिक परेशानी उस समय होती है जब बिजली चले जाने पर किसी दुर्घटना में घायल पीड़ित का उपचार करना होता है। उस समय केवल मोमबत्तियों और मोबाइल टॉर्च का ही सहारा कर्मचारियों और चिकित्सकों को लेना पड़ता है।

पंचायत के सूचना बोर्ड पर अंकित नहीं हो पाई मुफ्त दवाइयों की सूची

द रीव टाइम्स ब्यूरो, हमीरपुर

पंचायत के सूचना बोर्डों पर सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली मुफ्त दवाइयों की सूची अंकित नहीं हो पाई है। जागरूकता की कमी के कारण गरीब लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य विभाग को गरीब मरीजों को मुफ्त में दी जाने वाली दवाइयों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाने के आदेश पारित किए हैं। लेकिन, स्वास्थ्य विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों को जागरूक करने में अभी तक कामयाब नहीं हो सका है।

लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से उच्च न्यायालय ने प्रदेश के पंचायत सचिवों को पंचायत घरों के नोटिस बोर्ड पर गरीब मरीजों को मुफ्त में दी जाने वाली दवाइयों की जानकारी संलग्न करने के आदेश जारी किए थे लेकिन, अभी ग्राम पंचायतों के नोटिस बोर्ड पर इन दवाइयों की सूची नहीं लग पाई है। क्षेत्र के लोगों में सुनील शर्मा, विनोद कुमार, राहुल शर्मा, प्रदीप कुमार और अशोक ठाकुर ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि इस बारे में स्वास्थ्य विभाग को सख्ती से आदेश जारी किए जाएं ताकि, लोगों को इसका लाभ मिले। इस संबंध में बीएमओ बड़सर डॉ. हेमराज कालिया ने कहा कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता लोगों को घर-घर जाकर जागरूक करते हैं। पंचायत सूचना बोर्ड पर मुफ्त दवाइयों की सूची अंकित करवाई जाएगी।

आग से बरनोट जंगल को भारी नुकसान

द रीव टाइम्स ब्यूरो, बिलासपुर

उपमंडल कार्यालय झंडूता के साथ लगते जंगल बरनोट में बीते दिनों आग लगने से कई जीव जन्तु आग की भेंट चढ़ गए। आग इतनी जल्दी फैल गई कि उसे बुझाने में लोग भी असमर्थ हो गए। आग के साथ हवा भी बहुत तेज चल रही थी। आग से करीब छह हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो गया।

आग लगने का पता चलते ही वन विभाग आग बुझाने में जुट गया और बरनोट में वन विभाग के विश्राम गृह को आग से बचा लिया गया है। आग से करीब ६ हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो गया। आग से जंगल में कई जीव जन्तु जल गए हैं। हालांकि मौके पर दमकल विभाग के अधिकारी भी पहुंच गई थे लेकिन तबतक वन विभाग के कर्मचारियों ने आग को काबू कर लिया था।

वन परिक्षेत्र अधिकारी झंडूता अशोक कुमार ने बताया कि विभाग ने विश्राम गृह को आग से बचा लिया है। उन्होंने बताया कि विभाग आग लगने के कारणों की जांच कर रहा है।

20 वर्ष में सिर्फ दो किलोमीटर ही बनी विनायकघाट-मार्कंडेय सड़क

द रीव टाइम्स ब्यूरो, बिलासपुर

लोक निर्माण विभाग के अधीन आने वाले मंडल-एक के अधीन आने वाली विनायकघाट-मार्कंडेय सड़क पिछले 20 वर्षों में मात्र 2 किलोमीटर ही बन पाई है। इस दौरान कई सरकारें आई और गईं पर इस सड़क के लिए किसी भी पार्टी के नेता ने न तो बजट का प्रावधान करवाया और न ही किसी पंचायत प्रतिनिधि ने इस मांग को उठाया। अनदेखी के कारण पंचायत के लोगों में भारी रोष है। स्याहोला पंचायत के पूर्व उपप्रधान गोपाल शर्मा, बाबू राम, डह. पीसी शर्मा, सुरेंद्र कुमार ने बताया कि इस सड़क का निर्माण 1998 में शुरू हुआ था। इसको विनायकघाट से मंझोत तक एक किलोमीटर पक्का किया हुआ था जो आज उखड़ कर गड्ढों में तबदील हो चुकी है। इसके आगे मित्रमा तक लोकनिर्माण विभाग ने करीब 10 वर्ष पहले टेंडर करके बनवा दिया था। उसके बाद लोकनिर्माण विभाग ने इस कि सुध नहीं ली। यह सड़क नयना देवी विधानसभा क्षेत्र व सदर क्षेत्र में आधी-आधी बननी है। इस सड़क के मार्कंडेय से जुड़ने से ऋषि मार्कंडेय में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलना था। इससे क्षेत्र का विकास भी होना था लेकिन राजनेताओं के बेरुखी के कारण इस क्षेत्र के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क को बनाने की सहमति सभी ग्रामीणों ने 1998 में विभाग के पास दे दी थी लेकिन अब विभाग बनी हुई सड़क की भी गिफ्ट डीड मांग रहा है। ग्रामीणों ने इस सड़क को पक्का करने व मार्कंडेय तक निर्माण के लिए बजट का प्रावधान करने की गुहार लगाई है। इसके बारे में लोक निर्माण विभाग उपमंडल बिलासपुर के सहायक अभियंता कृष्णकांत ने बताया कि जो सड़क पक्की की गई है उसकी मरम्मत जल्द कर दी जाएगी और जो सड़क कच्ची है उसको पक्का तभी किया जा सकेगा, जब ग्रामीण उस जमीन की गिफ्ट डीड लोकनिर्माण विभाग के नाम करें।

निहारखंड बासला स्कूल में तपती धूप में बैठ कर होती है पढ़ाई

द रीव टाइम्स ब्यूरो, बिलासपुर

जिला के निहारखंड-बासला प्राथमिक स्कूल में पांच कक्षाओं के बच्चों को कड़कती धूप में बैठक कर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ रही है। अगर कभी मौसम खराब हो जाए तो पांच कक्षाओं के 50 बच्चों को एक कमरे में भर दिया जाता है या फिर घर भेज दिया जाता है। जबकि दोपहर का भोजन बच्चों को पेड़ के नीचे या फिर कड़कती धूप में बैठ कर करना पड़ता है। कहने को तो स्कूल के पास तीन कमरे हैं लेकिन उसमें से एक आंगनबाड़ी को दे दिया गया है। जबकि एक कमरे का स्टोर बना है। वहीं एक कमरे में पांच कक्षाएं एक साथ चल रही हैं। हालांकि अभिभावकों ने इस संबंध में शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन से लेकर राज्य सरकार तक समस्या के समाधान की गुहार लगाई लेकिन लोगों की सुनने को कोई तैयार नहीं। करीब सात लाख का प्राक्कलन तैयार जरूर किया गया लेकिन प्राक्कलन से आगे कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। स्कूल प्रबंधन समिति के प्रधान बुद्धिराम ठाकुर, हरिकृष्ण, हिमालयन परमार्थ संस्था के प्रधान शैलेंद्र भड़ोल, अभिभावक रोशनी, कांता, रश्मी, सुमिता के मुताबिक एक कमरे में आंगनबाड़ी केंद्र है और दूसरे में स्कूल के बच्चों को 10 डेस्क लगे हैं। अन्य कमरों में अह्फिस व पाठशाला का टूटा-फूटा सामान रखा गया है। इस कारण अन्य बच्चों को बाहर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। उन्होंने बताया कि इस स्कूल के भवन का निर्माण 1988-89 में हुआ था। तबसे अब तक स्कूल का ढांचा ऐसा ही है। मिली जानकारी के अनुसार स्कूल भवन के 6.90 लाख रुपये का प्राक्कलन बनाया हुआ है परंतु कई वर्ष बीत जाने पर भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस संदर्भ में अभिभावक उपायुक्त से भी मिल चुके हैं लेकिन उन्हें हमेशा आश्वासन ही मिला है।

नौनिहाल अब आंगनबाड़ी केंद्र में ही सीख रहे हैं राष्ट्रगान

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कांगड़ा

स्कूलों की तर्ज पर अब आंगनबाड़ी केंद्रों में भी सुबह पहले प्रार्थना सभा होगी। जिसमें नौनिहाल प्रार्थना के अलावा राष्ट्रगान भी गाएंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के तहत पूर्व शाला शिक्षा पाठ्यक्रम 'पहला प्रयास' तैयार किया है। इसके तहत हर महीने आंगनबाड़ी केंद्र में होने वाली गतिविधियों का एक बुकलेट बनाया गया है। इसके अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन किया जाएगा। बुकलेट में हर महीने का एक मासिक विषय निर्धारित किया गया है, जिसके अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों की प्रार्थना और खानपान का खाका तैयार किया है। लगभग 58 पेज की बुकलेट में हर प्रकार की गतिविधियों को विस्तारपूर्वक लिखा गया है, जिन्हें आंगनबाड़ी केंद्र में लागू किया जाएगा। उधर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कांगड़ा के जिला परियोजना अधिकारी रणजीत सिंह ने कहा कि 'पहला प्रयास' कार्यक्रम के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में विभिन्न गतिविधियों को संचालन किया जाएगा।

हर महीने अलग-अलग विषय निर्धारित

'पहला प्रयास' कार्यक्रम के तहत हर महीने अलग-अलग विषय निर्धारित किए गए हैं। प्रार्थना में भी हर माह बदलाव किया है। इसके अलावा नौनिहालों से दैनिक वार्तालाप के विषय भी तय किए गए हैं।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

जैविक कूड़े से खाद बनाएगी नगर परिषद

द रीव टाइम्स ब्यूरो, मंडी

शहर में घरों से निकलने वाले जैविक कूड़े की खाद बनाने की कवायद तेज हो गई है। डंपिंग साइट बिंद्रावणी में खाद निर्माण के लिए जैविक कूड़े को एकत्रित करने के लिए गड्ढे का निर्माण शुरू हो गया है। नगर परिषद यहां 15 गड्ढे बनाएगी। इसमें शहर के जैविक कूड़े को दबाया जाएगा। इससे डंपिंग साइट में कूड़े-कचरे के ढेर नहीं लगेंगे।

जैविक कूड़े से खाद तैयार की जाएगी। प्लास्टिक और अन्य कूड़े से ईंटें बनाई जाएंगी। इसके अलावा नगर परिषद मंडी शहर के अन्य स्थानों में भी कंपोस्ट तैयार करने की मुहिम शुरू कर रही है। सरकारी स्कूलों में भी मिड-डे मील के कचरे से कंपोस्ट खाद बनाने का निर्णय लिया गया है। आईटीआई, कॉलेज, अस्पताल और अन्य सरकारी शिक्षण संस्थानों में भी पिट (एक प्रकार का गड्ढा) बनाने की योजना तैयार की जा रही है। संस्थानों से निकलने वाले गीला कूड़ा, फूलों की क्यारियों से निकलने वाली पत्तियां और अन्य खाद्य पदार्थों को इन पिटों में डालकर खाद तैयार की जाएगी। इससे संस्थानों में लगे फूलों व पौधों को लाभ मिलेगा। नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि डंपिंग साइट में पिट का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। इस स्थान पर 15 पिट बनाए जाएंगे। शहर से डंपिंग साइट जाने वाला गीला कचरा इन पिटों में डाला जाएगा और खाद तैयार की जाएगी।

नगर परिषद मंडी की ओर से टारना मंदिर के पार्क में भी पत्तियों और वेस्ट मैटीरियल के लिए पिट तैयार किया जाएगा। इसमें पार्क में पेड़ पौधों की पत्तियों व अन्य अवशिष्ट को इकट्ठा कर खाद तैयार होगी। नगर परिषद की ओर से इंदिरा मार्केट में दो पिट बनाए जा चुके हैं।

डीपीआर के फेर में फंसी 4.2 किमी जलोड़ी टनल

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कुल्लू

10,280 फीट ऊंचे जलोड़ी दर्रा को भेदकर बनने वाली 4.2 किलोमीटर लंबी टनल डीपीआर की फेर में फंस गई है। अस्सी के दशक से उठ रही टनल बनाने की मांग आज तक पूरी नहीं हो सकी है। फरवरी 2014 को किए टनल के सर्वे के बाद भी इसकी डीपीआर को मंजूरी नहीं मिली है। जलोड़ी टनल और 97 किलोमीटर औट-आनी-सैंज हाईवे-305 पर करीब 1200 करोड़ खर्च किए जाने हैं। लेकिन टनल के साथ हाईवे की फाइल पांच सालों से धूल फांक रही है और अब इसे बाह्य सराज की 58 पंचायतों की सवा एक लाख आबादी ने लोस चुनाव में मुद्दा बना दिया है। 1980 से टनल की मांग उठाई जा रही और हर चुनाव में इस मुद्दे को राजनीतिक दलों की ओर से प्रमुखता से उठाया गया है। टनल और हाईवे निर्माण के वादे व आश्वासन आए दिन नेताओं की ओर से सार्वजनिक मचों पर दिए गए। इसके बाद भी आज तक कोई पहल नहीं हो सकी है। ऐसे में लोगों में राजनीतिक पार्टियों के प्रति निराशा है। ग्रामीण रमेश ठाकुर, लीला प्रसाद, तेज राम, श्याम लाल, गोविंद सिंह, पदम राठौर, कर्म चंद ठाकुर तथा ओम प्रकाश ने कहा कि सर्दियों में भारी बर्फबारी होने से जलोड़ी दर्रा दिसंबर से लेकर अप्रैल माह तक वाहनों की आवाजाही के लिए पूरी तरह से बंद हो जाता है। ऐसे में बाह्य सराज के लोगों के साथ करसोग, किन्नौर, स्पीति, रामपुर तथा कुमारसैन के लोगों को मंडी जिले के करसोग होकर आना जाना पड़ता है। इससे लंबे रूट से न केवल लोगों के समय की बरबादी होती है, बल्कि उन्हें भारी भरकम धन भी खर्च करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि टनल के बिना आनी-निरमंड की जनता को जिला मुख्यालय पहुंचना किसी खतरे से खाली नहीं।

कई सालों से निजी भवनों में चल रहे सरकारी कार्यालय

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कुल्लू

जिला कुल्लू के सैंज में मिनी सचिवालय बनवाने की मांग उठ रही है। लोगों ने सैंज घाटी में सरकारी कार्यालयों को एक छत के नीचे लाने की पैरवी की है। जनता का कहना है कि सैंज उप तहसील मुख्यालय में अधिकतर कार्यालय किराये के भवन में चल रहे हैं। लेकिन इन कार्यालयों को कई सालों से अपना भवन नहीं मिल सका। लोकसभा चुनाव में अब यह मुद्दा सियासी रंग ले चुका है। सैंज घाटी में तीन बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण हो चुका है। इन परियोजनाओं से अब बिजली का उत्पादन भी शुरू हो गया है। इससे परियोजना प्रबंधन को करोड़ों रुपये की आमदनी हो रही है। घाटी के लोगों का कहना है कि परियोजनाओं के निर्माण के दौरान घाटी की जनता ने कंपनियों का भरपूर सहयोग किया है। अब सरकार को चाहिए कि वह जल्द जल्द मिनी सचिवालय का निर्माण करे। प्रीतम चंद, राम कृष्ण, लाल दास, मनोहर लाल, रोहित कुमार, मालती देवी ने कहा कि सैंज उप तहसील मुख्यालय में कई सरकारी कार्यालय हैं। अधिकतर विभागों के पास अपने भवन नहीं है। किराये के भवनों में चल रहे सरकारी कार्यालयों को तलाशने में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घाटी की जनता चाहती है कि सभी विभागों के दफ्तर एक ही छत के नीचे हो। जनता ने प्रत्याशियों के समक्ष सैंज में मिनी सचिवालय बनवाने की मांग रखी है।

आश्वासन के बाद साहो गांव में डेढ़ बजे शुरु हुआ मतदान

द रीव टाइम्स ब्यूरो, चंबा

उपमंडल चुराह के तहत ग्राम पंचायत आयल के साहो गांव में मतदान बहिष्कार का मन बनाए ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार के आश्वासन के बाद 19 मई को डेढ़ बजे मतदान शुरू किया। इससे पहले ग्रामीण मतदान केंद्र नहीं पहुंचे। सुबह से चुनाव ड्यूटी दे रहे अधिकारी और कर्मचारी मतदाताओं के आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन दोपहर तक कोई भी मतदाता मतदान करने नहीं पहुंचा। ग्रामीण सड़क के अभाव में चुनावों का बहिष्कार करने की तैयारी में थे। सूचना मिलते ही एसडीएम तीसा हेमचंद वर्मा ने नायब तहसीलदार को मौके पर भेजा। नायब तहसीलदार ने ग्रामीणों से बातचीत की और आश्वासन दिया कि चुनावों के बाद उनकी मांग को पूरा करने के प्रयास किए जाएंगे। इसके बाद ग्रामीण 19 मई को मतदान करने के लिए पहुंचे। गौरतलब है कि उक्त गांव सड़क सुविधा से वंचित है।

इसके चलते ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय पंचायत प्रधान गुलशन बेगम ने बताया कि गांव सड़क सुविधा से महरूम है और पानी की भी समस्या है। समस्याओं को लेकर ग्रामीण चुनाव का बहिष्कार कर रहे थे। लेकिन नायब तहसीलदार ने आश्वासन दिया है कि उनकी

पांच माह बाद 13 हजार फीट ऊंचा रोहतांग दर्रा बहाल, लोगों को मिली बड़ी राहत

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कुल्लू

पांच माह बाद रोहतांग दर्रा बहाल हो गया है। फिलहाल छोटे वाहनों के लिए इसे बहाल कर दिया गया है।देश व दुनिया भर के पर्यटकों को बर्फ के दीदार करवाने वाला 13050 फीट ऊंचा रोहतांग दर्रा बीआरओ ने बहाल कर लिया है। दर्रे के बहाल होते ही छोटे वाहन आर-पार होना शुरू हो गए हैं। रोहतांग बहाल हो गया है, लेकिन सैलानियों को इसके दीदार करने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। दर्रे में बर्फ हटाने से सड़क किनारे दोनों ओर बर्फ की उंची दीवारें खड़ी हो गई हैं। हालांकि अभी मढ़ी क्षेत्र के ब्यासनाला और सागु फाल में पर्याप्त बर्फ जमा है।

लंबे समय तक बर्फ के दीदार कर सकेंगे सैलानी

रोहतांग दर्रे में बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है, जो लंबे समय तक सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बनेगी। बर्फ हटाने के बाद राहनीनाला से रोहतांग तक व रोहतांग से ग्रांफु तक दोनों और 6 से 10 फीट तक बर्फ की दीवार खड़ी हो गई है। सर्दियों में भारी बर्फबारी हुई है।इस साल मई में भी रोहतांग में बर्फबारी जारी है, इस कारण इन दिनों अभी भी 6 से 10 फीट तक बर्फ के ढेर लगे हुए हैं। सैलनियो को रोहतांग दर्रे के दीदार करने को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। रोहतांग दर्रा 19 मई को बहाल हो गया था, लेकिन व्यवस्था करने में अभी समय लगेगा। रोहतांग दर्रे में बर्फ के ढेर के बीच पार्किंग, शौचालय और ट्रैफिक व्यवस्था प्रशासन के लिए चुनौती से कम नहीं है। रोहतांग दर्रा जून के पहले सप्ताह तक सैलानियों के लिए बहाल होने की उम्मीद है।

हर मंगलवार को बंद रहेगा रोहतांग दर्रा

समर सीजन में हर मंगलवार को रोहतांग दर्रा सैलानियों के लिए बंद रहेगा। इस दिन बीआरओ सड़क की मरमत करेगा। हालांकि लाहुल जाने वाले वाहन समय अनुसार चलते रहेंगे। लेकिन सैलानी मंगलवार को रोहतांग दर्रे के दीदार नहीं कर सकेंगे।

हर साल सड़क, बिजली की आस में डालते हैं वोट, नहीं मिली सुविधाएं

द रीव टाइम्स, कुल्लू

जिला कुल्लू की सैंज घाटी की गाड़ापारली पंचायत के शाक्टी-मरोड़ गांव के पिछड़ेपन की अजब कहानी है। बिजली परियोजनाओं की नगरी सैंज घाटी में बसे इस गांव में सरकारी सुविधा के नाम पर मात्र एक प्राथमिक पाठशाला है।

आठवीं कक्षा की पढ़ाई के लिए बच्चे हर रोज 16 किमी पैदल चलकर स्कूल पहुंचते हैं। जिला की सबसे उम्रदराज 110 वर्षीय मतदाता शाढ़ी देवी के कारण इस बार लोस चुनाव में यह गांव सुर्खियों में है।

पत्थरीली डगर, खूंखार जंगली जानवर और मौसम का मिजाज यहां विकास की राह में रोड़ा बने हुए हैं। विश्व धरोहर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के सख्त नियम गांव के आसपास के जंगलों से छेड़छाड़ की कतई छूट नही देते।

शाढ़ी देवी की आंखें भी गांव तक सड़क और बिजली देखने को पत्थरा गई है। एक संस्था ने गांव में सोलर लाइट का प्रबंध कर दिया है। इससे पहले ग्रामीण शोली जलाकर ही उजाला करते थे। लोग देवता के दरबार में होने वाले हर छोटे-बड़े फैसले को अंतिम फैसला मानते हैं। गांव के नौनिहाल सुबह-शाम आठ-आठ किमी सफर तय कर शिक्षा ग्रहण करते हैं। उच्च शिक्षा के लिए 20 किमी और कॉलेज के लिए 35 किमी की दूरी पैदल तय करनी पड़ती है। शाढ़ी देवी के एक दैनिक में छपे बयान के मुताबिक वह हर बार इस उम्मीद से मतदान करती है कि गांव तक सड़क का निर्माण होगा।

फिलहाल सड़क का अंतिम छोर 35 किमी की दूरी पर है। हालांकि मरोड़ गांव को आठ वर्ष पहले प्राथमिक पाठशाला के रूप में बड़ा तोहफा मिला था। मूलभूत सुविधा के नाम पर गांव के हाथ अब तक खाली रहने से वह खासी दुखी है। मरोड़ गांव के पंद्रह परिवारों को अपने बच्चे घने जंगल की पहाड़ी के ऊपर बने रास्तों से आठ किमी दूर शाक्टी भेजने पड़ते है।

खुले में कूड़ा फेंकने पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लगाया 17 हजार जुर्माना

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कुल्लू

स्वच्छता को लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अभियान तेज कर दिया है। पहले चरण में विभाग ने गंदगी फैलाने वालों को महज चेतावनी देकर भविष्य से सुधर जाने की हिदायत दी थी। लेकिन अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सीधी कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी कार्रवाई के तहत मनाली उपमंडल के पतलीकूहल में खुलेआम कूड़ा फेंकने वालों पर 17 हजार जुर्माना ठोका गया है।

जिसमें तीन दुकानदारों को 5-5 हजार और दो से एक-एक हजार जुर्माना वसूला गया। दुकानदारों पर खुलेआम कूड़ा फेंकने पर इसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। बोर्ड के सख्त रुख से दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। पतलीकूहल बाजार में इस दौरान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्राम पंचायत प्रधान सहित बीडीओ कार्यालय के लोग भी उपस्थित रहे। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अभियंता ने जुर्माने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पतलीकूहल की कूहल के पानी का भी सैंपल भरा गया है और जांच के लिए लेब भेजा गया है। कहा कि जांच में अगर कोई खामियां पाई गईं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। कूहल में कई घरों और ढाबों की नालियों का गंदा पानी बह रहा था। उन नालियों को भी हटाकर उनके मालिकों को चेतावनी दी गई है। उन्होंने कहा कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।

जनजातीय क्षेत्र पांगी में मिंधल माता यात्रा एक जून से शुरु

द रीव टाइम्स ब्यूरो, चंबा

जनजातीय क्षेत्र पांगी में एक जून से मिंधल माता यात्रा शुरू हुई यात्रा तीस जून तक चलेगी। इस दौरान पांगी घाटी के अलावा चुराह और जम्मू-कश्मीर के श्रद्धालु मिंधल माता के मंदिर में पहुंचेंगे। इस दौरान पांगी में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रहेगी। मिंधल माता यात्रा के आयोजन को लेकर स्थानीय प्रशासन ने अपनी ओर से तैयारियां पूरी कर ली है। यात्रियों की सुविधा के लिए मंदिर में टेंट लगाए जाएंगे। जहां पर यात्री रात्रि ठहराव कर पाएंगे।

इसके अलावा मंदिर तक रास्ते के बीच-बीच में पेयजल की टंकियां रखी जाएंगी। जिससे यात्रियों को पेयजल किल्लत का सामना न करना पड़े। हर वर्ष हजारों की संख्या में श्रद्धालु मिंधल माता यात्रा को आते हैं। मिंधल माता मंदिर की जीर्णोद्धार कमेटी ने स्थानीय प्रशासन से मांग की कि अझल नाला में बने ग्लेशियर को जल्द हटाया जाए। जिससे यात्रियों को नाले के रास्ते से आवाजाही करने में कोई परेशानी पेश न आए। कमेटी के प्रधान मान सिंह ठकुरवान ने बताया कि इस बार श्रद्धालुओं की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में दोगुनी होगी। क्योंकि मिंधल माता मंदिर का नया भवन बनाया गया है। इसको देखने के लिए भी श्रद्धालुओं में काफी उत्साहित है। उन्होंने जिले के लोगों से आग्रह किया है कि वे मिंधल माता यात्रा में पधारकर यात्रा की शोभा बढ़ाएं। एसडीएम पांगी विश्रुत भारती ने बताया कि मिंधल माता यात्रा के लिए प्रशासन की ओर से सुरक्षा और यातायात के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। इसको लेकर जगह-जगह पुलिस कर्मी तैनात किए जाएंगे। जिससे यात्रा में किसी प्रकार का खलल न पड़े।

ठग गिरोह के निशाने पर रहती थीं ग्रामीण महिलाएं

द रीव टाइम्स ब्यूरो, मंडी

एटीएम से छेड़छाड़ करने वाले ठग गिरोह के कुछ और सदस्य भी पुलिस की रडार में आए हैं। गिरफ्तार तीनों आरोपियों से पुलिस को पूरे गैंग की लीड मिली है। गिरोह के सक्रिय सदस्यों की तसदीक अब ऐसे बैंक एटीएम से होगी जहां कार्ड बदलने के मामले सामने आए हैं। पुलिस की जांच में पाया गया है कि इनके निशाने में अधिकांश ग्रामीण महिलाएं ही रही हैं। प्रदेश में तीन वर्षों से अधिक समय से ये सक्रिय थे, अब तक लाखों की चोरी को ये अंजाम दे चुके हैं।

जोगिंद्रनगर शहर के पठानकोट चौक, चौंतड़ा और बैजनाथ, पपरोला स्थित एटीएम में छेड़छाड़ के दौरान आरोपी सीसीटीवी में कैद हुए हैं। पुलिस ने सभी एटीएम की फुटेज एकत्रित कर जांच आगे बढ़ा दी है। रविवार को आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां पर पुलिस को रिमांड हासिल हुआ है। अब आरोपियों की निशानदेही पर छेड़छाड़ वाले एटीएम से भी पुलिस साक्ष्य जुटाएगी। कुछ एटीएम में आरोपियों की सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस ने हासिल कर ली है। थाना प्रभारी ने कहा कि एटीएम से छेड़छाड़ कर एटीएम उपभोक्ताओं से ठगी करने वाले आरोपियों से पूछताछ कर अन्य सदस्यों की संलिप्तता की बात भी उजागर हुई है। जल्द ही गिरोह के अन्य सदस्य भी पुलिस की हिरासत में होंगे।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

जिम्मेदार और सजग नागरिक बनने के लिए जानें कानून

ऐसा हमारे साथ अक्सर होता है कि हमें सड़क चलते कोई पुलिस वाला डांट-फटकार देता है और हम अपना सा मुंह लेकर किनारे हट जाते हैं। हालांकि, होना तो यह चाहिए कि हम अपने कानूनी अधिकारों को जानते हों और उस पुलिस वाले को यह बतला दें कि आपका इस तरह व्यवहार उचित नहीं।

ऐसे में हम आपको अवगत करवाते रहते हैं कुछ ऐसे ही कानूनों से जिन्हें जानना बेहद जरूरी है। इनको जान लेने के बाद आप कानूनी तौर पर गलत और सही का अंतर समझ पाएंगे और अपने साथ दूसरे नागरिकों को सुरक्षा और जागरूकता देंगे।

गर्भवती महिलाओं को सुरक्षा...

भारतीय कानून के मुताबिक, देश में कोई भी कंपनी गर्भावस्था के दौरान किसी महिला कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाल सकती। ऐसा करने पर कार्रवाई का प्रावधान है।

टॉयलेट में पानी मुहैया कराना...

भारतीय कानून के मुताबिक देश में सारे होटलों को बिना किसी शुल्क के टॉयलेट में पानी मुहैयया कराना होगा। ऐसा न करना कानूनन अपराध है।

गिरफ्तारी के दौरान अपराध जानने का अधिकार...

किसी भी शख्स को गिरफ्तारी से पहले यह जानने का अधिकार है कि उस पर क्या आरोप लगे हैं। साथ ही यह भी कि किस आधार पर उसे गिरफ्तार किया जा रहा है।

महिला कांस्टेबल है जरुरी...

पुलिस किसी भी महिला को बिना महिला पुलिस कांस्टेबल के हिरासत में नहीं ले सकती। यहां तक कि घर में दबिश देने के दौरान भी महिला कांस्टेबल होनी जरूरी है।

महिला को कभी भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता...

पुलिस किसी भी महिला को सुबह होने से पहले और सूर्यास्त के बाद कानूनन गिरफ्तार नहीं कर सकती है।

बेटा-बेटी का हक बराबर है...

पैतृक संपत्ति में बेटों के साथ-साथ बेटियों का भी बराबर का हक होता है। बेटियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता।

बलात्कार पीड़िता को आजादी...

बलात्कार और यौन हिंसा की शिकार महिला को स्वतंत्रता है कि वो पुलिस स्टेशन जाने के बजाय घर पर ही अपना बयान दर्ज करा सकती है।

गाड़ी चलाते वक्त सारे कागजातों की जरुरत नहीं...

ऐसा जरूरी नहीं है कि आप गाड़ी या दोपहिया चलाते वक्त सभी असली कागजात साथ रखें। ड्राइविंग करते वक्त लाइसेंस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट असली होने चाहिए। इंश्योरेंस और कार के **RC** की फोटो कॉपी भी चल जाएगी। इसके लिए आपका चालान नहीं काटा जा सकता।

पुलिस एक ही चीज के लिए एक दिन में दो बार आपका चालान नहीं काट सकती है।

मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कानून के अनुसार कोई अकेला व्यक्ति किसी लड़की को गोद नहीं ले सकता है। हालाँकि वह किसी लड़के को गोद ले सकता है।

'डेंटिस्ट एक्ट 1948' के अनुसार सड़क किनारे दांत निकालना और कान का मैल साफ करना गैरकानूनी माना जाता है। ऐसा करने वाले को सजा हो सकती है।

एडवोकेट प्रदीप वर्मा
कानूनी सलाहकार, आईआईआरडी, 94180 25649

पाठकों के प्रश्न एवं कानूनी समस्याऐं सादर आमंत्रित है। आपके प्रश्नों के उत्तर हमारे कानून विशेषज्ञ ऐडवोकेट प्रदीप वर्मा अगले अंक में देंगे। प्रश्न हमारी मेल आई डी पर पूछे जा सकते है।

कोलेस्ट्रॉल : क्या और उसका उपचार

- कोलेस्ट्रॉल रक्त में पाया जानेवाला वसा (फैट) है। स्वस्थ जीवन के लिए यह बहुत जरूरी है, परंतु जब रक्त में इसकी मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है, तो रक्त में थक्के जम जाते हैं, जो हृदय के लिए घातक होता है। डॉक्टर्स के अनुसार, किसी भी उम्र के स्त्री-पुरुष में कोलेस्ट्रॉल का स्तर 200 एमजी/ डीएल से कम ही रहना चाहिए।

कोलेस्ट्रॉल के रिस्क फैक्टर्स

- हाई कोलेस्ट्रॉल से ग्रस्त लोगों में कोई लक्षण तब तक दिखाई नहीं देते, जब तक कोलेस्ट्रॉल दिल व दिमाग की तरफ जानेवाली धमनियों को काफी संकरा नहीं कर देता है। इसके परिणामस्वरूप सीने में दर्द होता है।
- रक्त में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने से पथरी रोग, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और गुर्दे की बीमारी हो सकती है।
- हाई कोलेस्ट्रॉल होने पर ये बढ़ते-बढ़ते नसों में उतर आता है, जिससे चलना-फिरना कठिन हो जाता है।
- हार्ट अटैक, किडनी डिसऑर्डर, थायरॉयड, लकवा जैसे रोग कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से हो सकते हैं। इनसे बचने के लिए दवा के साथ-साथ अपने खानपान पर ध्यान देना भी जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करके हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक जैसी बीमारियों की वजह से होनेवाली अकाल मृत्यु को रोका जा सकता है।

कोलेस्ट्रॉल के कारण और लक्षण

- रक्त में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारणों को तीन भागों में बांटा गया है।
- कोलेस्ट्रॉल बढ़ानेवाले आहार यानी वसायुक्त खाद्य पदार्थ का अधिक मात्रा में लगातार सेवन करना।
- मेटाबॉलिक सिस्टम जब एलडीएल की मात्रा को पर्याप्त रूप में रक्त से बाहर नहीं कर पाता, तो रक्त में एलडीएल का स्तर बढ़ जाता है।
- तीसरी स्थिति वह होती है, जब लिवर कोलेस्ट्रॉल को अधिक मात्रा में बनाने लगता है।
- उपरोक्त कारणों को यदि नियंत्रण में रखा जाए, तो हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या उत्पन्न ही नहीं होगी।
- जहां तक लक्षणों की बात है, तो थकान, कमजोरी, सांस लेने में तकलीफ, अधिक पसीना आना, सीने में दर्द, बेचैनी-सी महसूस होना आदि इसके प्रमुख लक्षण हैं।

कोलेस्ट्रॉल की जांच

- 20 साल की उम्र से अधिक आयुवालों को हर 5 साल में कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट जरूर करवाना चाहिए।
- टेस्ट में लिपोप्रोटीन टेस्ट करवाना जरूरी होता है, जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल पता चलता है।
- यह भी देखा गया है कि मेनोपॉज से पहले एक ही उम्र के स्त्री-पुरुषों में कोलेस्ट्रॉल का स्तर अलग-अलग होता है। स्त्रियों में पुरुषों के मुकाबले कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है।
- लेकिन मेनोपॉज के बाद स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा कोलेस्ट्रॉल का स्तर काफी ज्यादा पाया जाता है।
- ऐसे में मेनोपॉज के बाद महिलाओं को अपने कोलेस्ट्रॉल स्तर पर खास ध्यान देना चाहिए।
- कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखने के लिए क्या खाएं?
- अपने खानपान में अधिकाधिक मौसमी फल व सब्जियों को शामिल करें।
- इनमें संतरे का जूस प्रमुख है, जिसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है।
- जीरो कोलेस्ट्रॉल वाले पदार्थ, जैसे- ताजा फल, सब्जियां और फाइबरयुक्त पदार्थ अपने भोजन में शामिल करें।
- सुबह नाश्ते में कॉर्नफ्लैक्स जैसे आहार फायदेमंद रहते हैं।

ये न खाएं

- रेड मीट का सेवन न करें।
- दूध, बटर, घी, क्रीम यहां तक कि आइस्क्रीम जैसे पदार्थ, जिनमें भारी मात्रा में कोलेस्ट्रॉल होता है, खाने से बचें।
- मावा से बनी मिठाइयां स्लो पॉइजन का काम करती हैं, इनसे दूर ही रहें।
- सिगरेट-शराब का सेवन कम करें।

डॉ0 के आर शांडिल
द रीव क्लिनिक, शिमला
अधिक जानकारी के लिए लिखें: therievtime@iirdshimla.org

खाने से जुड़ी रोचक और अनोखी बातें

द रीव टाइम्स

केला खाने से मानसिक तनाव कम होता है।

इंसान हर एक सेकंड में 1797 जानवरों को मार देता है वो सिर्फ अपने शौक को पूरा करने के लिए।

अमेरिका में 49% लोग हर रोज एक सैंडविच खाते है।

2013 के नाथन हॉट डॉग Competition में Winner ने सिर्फ दस मिनिट में 69 Hot dogs खाए थे।

McDonalds हर सेकंड लगभग 75 हैमबर्गर बेचता हैं।

कैलिफोर्निया दुनिया का पाँचवा सबसे पहला फूड सप्लायर है।

खीरा खाना Dehydration से बचने का सबसे आसान उपाय है। और इसमें लगभग 96% पानी होता है।

क्या आप जानते है की डायनामाइट मूंगफली के दानो से बनता है।

लगभग आज से 40–45 साल पहले बनाये गए चिकन में 266% ज्यादा वसा होती थी।

आज हम जो खाना खाते है उसकी खोज 5000 साल पहले हुई थी।

हमारे भारतीय खाने में 6 तरह के स्वाद होते है, मीठा, नमकीन, खट्टा, तीखा, कसैला और कड़वा।

आप पूरा अंडा खा सकते हो क्योकि अंडे के छिलके में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है।

इंसान जन्म से ही मीठा खाने का आदि होता है।

क्या आप जानते है की दुनिया में एक समय ऐसा भी था जब चोकलेट का इस्तेमाल पैसे की जगह होता था।

जानते हो की आलू से wifi की स्पीड बढ़ाई जा सकती है, इसका प्रयोग एयरक्राफ्ट के रेडियो सिग्नल को जांचने के लिए भी किया जाता है।

हवाई जहाज का खाना कुछ लोगो को स्वादिष्ट नहीं लगता, क्योकि इतनी ऊंचाई पर जा कर हमारे स्वाद और सूंघने की क्षमता में 20% से 60% तक कम हो जाती है।

निम्बू पूरी दुनिया में सबसे healthy food में से एक है।

सबसे ज्यादा कैलोरी मिल्क शेक में पायी जाती है।

क्या आप जानते है की 3 करोड़ से ज्यादा अमरीकी लोग सुबह का नाश्ता नहीं करते।

हररोज फास्टफूड खाना आपके लीवर पर ऐसा बुरा प्रभाव डालता है जैसे हेपेटाइटिस अपना प्रभाव डालता है।

ताजा ब्रेड दुनिया में सबसे ज्यादा खरीदा जाने वाला फूड है।

10 अगस्त 2015 को नासा के अंतरिक्ष यात्रियों ने पहली बार अंतरिक्ष ने बनाया हुआ 3D पिज्जा खाया था।

क्या आप जानते है की एक मात्र शहद ही ऐसा फूड है जो 300 साल से भी अधिक तक खराब नहीं होता।

सेब असल में रोज फेमिली से है जैसे की नाशपती है।

हर साल दुनिया का लगभग आधा खाना बेकार फेंक दिया जाता है।

भारत में सबसे पहले टमाटर, आलू, और मिर्च एक पुर्तगाली लाया था।

क्या आपको पता है की गाजर असल में बैंगनी रंग के होते है।

क्या आपको पता है की शहद को हम अमृत बोलते है पर असल में वो मधुमक्खी की उल्टी से बनता है।

क्या आप जानते है की जो आइसक्रीम टेलीविजन में यूज की जाती है वो असल में पिसे हुए आलू होते है ताकि वो शूटिंग के दौरान पिघले ना।

एक साल में इतने Nutella Jar बेचे जाते है, जिनसे चीन की दीवार को आठ बार ढंका जा सके।

दुनिया के सबसे महंगे पिज्जा की किंमत करीब 12000 डॉलर है, जिसको बनाने में 72 घंटे से भी ज्यादा समय लग सकता है।

पूरी दुनिया में सबसे कम मिट खाने वाले लोग भारत में है।

क्या आप जानते है की पनीर एक ऐसा फूड है जो सबसे ज्यादा चोरी होता है।

पौष्टिक भोजन जंक फूड से 10 गुना तक महंगा होता है।

चिकन टिक्का मसाला असल में भारत की नहीं बल्कि स्कॉटलैंड की डिश है।

माँ के दूध में इतनी ताकत होती है की इनमे से आपको सभी पोषकतत्व मिल जाते है।

दुनिया में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला मिट 70% लाल मिल बकरे का होता है।

शहद सिर्फ 20 मिनिट के अंदर ही खून तक पहुच जाता है क्योंकि मधुमख्खी इसे पहले ही पचा देती है।

अगर आप सुबह के समय चाय या कॉफी की जगह पे एक सेब खाए तो आपको ज्यादा तरोताजा महसूस होगा।

MANDATE FOR NEW GOVERNMENT

With the absolute majority in parliament, this tenure of Central Government can become ever memorable in the history of independent India if the government prioritises the settlement of long pending issues with permanent solutions. Hopefully, the present government will not leave any stone unturned this time because the situation may not remain the same in future for the reasons like 1) People start losing interest in the long period ruling party and the young people expect speedy change; 2) There may be rigorous change in the leadership and style of the AIC which may give space for emergence of the new and honest faces including siblings from the existing dynasties still continuing gaining faith of people as customary morality; 3) There are possibilities of deformity in the characters of the existing representatives serving for long period which automatically comes with the power if not digested with care; etc. Keeping the above in mind, this and only this period has to be treated as the golden period of Complete Cleanliness and Rebuilding the Nation. Following are some of the priorities for which the Nation is eagerly waiting for taking cognizance on:

- 1. **Population Control Measures:** Majority of the problems in the country is due to uncontrolled population. World's 18% population is struggling to survive on 2.5% land of the world. The first and foremost action, which no political party talks of now, is to stop being excelling Chine in population growth which is likely to happen by 2025 as per studies. The principle of 'We two-Our two' has to be – effectively. This will help in maintaining ecological balance with quality of life to the people living on this sub-continent.
- 2. **National Citizen Register:** we are a country with inadequate record to ascertain the number of families and their members living here. There is need of establishing National Citizen Register with authenticated information for at least last 3 generations with land ownership details to enroll citizen with National Unique ID. The basis of Aadhar Number generation has been full of loopholes; hence cannot be treated for the purpose until Aadhar Number re-authentication exercise is carried out based on last three generations record alongwith land ownership status detail or in some other way.
- 3. **Farmers' Security and Food Storage:** In the country, where around 20 percent population is victim of malnutrition due to insufficient food, wastage of food grains because of improper storage is a curse on governance. Instead of paying Rs-6000/- to farmers, the need of the hour is to intervene in buying back the farmers' produce at double price of their input cost to prevent farmer-suicides. FCI's Management needs to be given to non-government and dynamic individuals to create more warehouses, with 'state of the art' technologies in states to ensure that the farmer produce is timely procured without any loss with instant payment practices. The land for such warehouses should be brought under National Priority Projects to prevent unnecessary delay in land procurement.
- 4. **National Policy on Safe Food:** The excessive use of chemicals in the farming needs to be stopped immediately and organic farming practices need to be stringently adopted in phased manner. Strong punitive actions are needed on food adulteration with tough stand. This area should be treated one of the uncompromisable areas.
- 5. **National Forest Policy:** The green felling in the name of developmental projects is taking place and the financial compensation deposited with the respective Forest Department for afforestation has been a big failure. The process of according green felling permission needs to be reversed. No such permission should be accorded until the requisite number of plants planted by the department / agency concerned and the basis of such permission should be only the proportion of new plantation completed and confirmed auditable commitment of the agency to take care of the plants.
- 6. **Abolition of Article 35(A) and 370-** As these Articles were inserted through backdoor entry, in the similar way, these articles should be abolished through an ordinance without any parliamentary debate and debacles. Only silent action is required here.
- 7. **Induction of Uniform Civil Code:** 'One country, one rule' is an urgent need of the hour. This act has to be passed without any delay. There is no need to hear the logics and arguments of the Fundamentalists on this. The Secularism of the Constitution needs to be redefined to the extent that it does not infringe in the laws of the land. This act will pave passage to solve many of the internal problems.
- 8. **Ancient Properties and Heritage Protection Bill:** All the properties captured, seized, and converted by the invaders in different shapes, styles, purposes and usage during last 500 years are needed to be provisioned for returning to their original status. However, this may not be applicable on the newly creation assets atleast 5 kilometres away from the ancient structure.
- **9. Right to Recall:** The legislators and parliamentarians who do not perform well should be kept at public disposal for calling them back and electing new one. There has been cases where the MP's could not spend even small amount of their discretionary grant in 365 days. People elect representatives to legislative as per their expectations and assurances given by the contestants but the effectiveness is known only after having given them the chance to perform. Such MPs and all those whose overall performance is below the desired level should not be imposed on public for long period of five years.
- **10. Public Office Accountability Bill:** The veins of our bureaucratic system also needs to be checked. There should be timeline for each and every action to be taken by the Govt. agencies on the matters of the public affairs. There should be an IT enable online tracking system for all such matters. The performance rating of the agencies through public can be experimented.
- 11. **Strengthening Currency Value:** Strategy should be devised to strengthen the value of rupee in the international market. There is huge gap in the value which enables the majority of the expatriates to buy things almost for free in India and whereas the hard earned income of Indians gets lost even in buying a cup of tea abroad especially in developed countries. All economic measures need to be taken up to strengthen the values of our currency including making export procedures simpler and easily accessible, etc.
- 12.**Transportation and Communication in Hilly and Bordering States:** Special attention needs to be given to improve roads, railways and air routes in the hilly and bordering states. This area has been the neglected one for decades and significant thrust needs to be given.

However, there are a number of equally important areas in each sector including education, health, water, sanitation, industries, etc. One specific intervention that needs immediate attention is providing shelters to everyone. There are thousands of shelterless people sleeping on footpaths even today. 'Housing for All' schemes by the government may take long to provide shelter/roof to all; meanwhile, an adhoc sheltering arrangement needs to be thought about and implemented for the people sleeping under the sky. The program like Mission RIEV needs to be taken to the nooks and corners of the country to give ease to the people in getting things done through a systematic way besides creating abundant opportunities and economic growth. Implementing the above-mentioned aspects will make the country more progressive than China

Dr. L.C. Sharma
Editor in Chief
Mob.94180 14761, md@iirdshimla.org

बिन पानी सब सून.....

जल संकट में भविष्य...तड़प-तड़प कर निकलेंगे प्राण

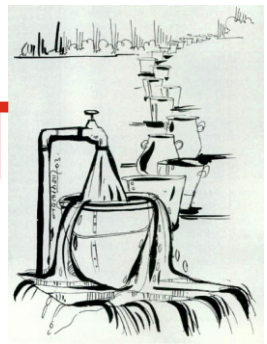

न कारगर सरकारी योजना, न ही परिपक्कव इंसानी समझ

भारत की अमृतदायी नदियां आईसीयू में वेंटीलेटर पर

बहुत कठिन डगर पनघट की...ये तो बहुत पहले से कहा जाता रहा है। लेकिन अब तो पनघट की डगर लगभग असंभव सी होती जा रही है। इसमें कोई शंका ही नहीं कि जल से जीवन है और जल ही जीवन है। तो क्या हम अपने जीवन को इतना ही प्यार करते हैं जितना अपने प्राणों को करते हैं ? नहीं, यह दिखावा होता गया और आज यह प्राणतत्व जल हमारे भविष्य को घोर संकट में डाल चुका है। अब संभलने का समय भी कम ही है और देश में शुद्ध जल का अभाव लगातार होता जा रहा है। देश में पानी के स्रोत लगातार खाली होते जा रहे हैं। भूमिगत जनस्तर घटता जा रहा है। यह संकट दक्षिण भारत के तमिलनाडु से लेकर आज उत्तर भारत तक को चपेट में ले चुका है। जल हवा की तरह इस ब्रह्मांड में अति आवश्यक तत्वों में समाहित है जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इतना ही नहीं, हमारे जीवन की प्रत्येक गतिविधि में जल का समावेश हुए बिना आगे की बात संभव ही नहीं हैं।

भारत में पीने के पानी अथवा शुद्ध जल की मात्रा अब बहुत कम रह गई है। मानव ने अपनी आवश्यकताओं और करतूतों से जलस्रोतों, नदियों और नालों को गंदगी के अवशेषों से दूषित करने में कोई कोर-कसर नहीं रखी है। विकसित देश जब दूसरे ग्रहों पर घर बनाने और तकनीक को वहां ले जाने पर प्रयासरत है, हम भारतवासी अभी यह सीख रहे हैं कि टॉफी का कागज़ का निदान कैसे और कहां करें। विकसित होने की प्रक्रिया बहुत से बलिदानों और दूरगामी योजनाओं की सान पर पूरी की जाती है। लेकिन हमारे देश में इस बात की समझ को अभी अपनाने में एक लंबा अरसा लग जाएगा।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय के एक निर्णय में गंगा और जमुना नदियों और उसकी जलधाराओं को जीवन व्यक्ति का वैधानिक दर्ज़ा दिया गया है। इसके मायने ये कि अब इन नदियों और उनकी जलधाराओं को किसी व्यक्ति के समान ही अधिकार प्रदान किए गए हैं। अब यदि कोई इन नदियों को गंदा करता है, किसी भी प्रकार से दूषित करता है तो उस पर किसी व्यक्ति के साथ किए जाने वाले अपराध की तरह कानून द्वारा कार्यवाही की जाएगी। क्या ऐसा वास्तविकता में हो भी पा रहा है क्योंकि पानी तो अभी भी दूषित किया ही जा रहा है लेकिन कार्यवाही के नाम पर कुछ हुआ तो नहीं है। न्यायालय का यह निर्णय बेहद संवेदनशील है क्योंकि यदि इस पर अमल होता है तो जल समस्या पर कुछ तो हल निकाला ही जा सकता है।

आंकड़ों का आकलन हो तो 180 करोड़ लोग दुनिया में दूषित पानी पीते हैं। वर्ष में पूरी दुनिया में 8 लाख 42 हज़ार मौतें हो जाती है। हम इस बात को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते कि किसानों की आत्महत्या के पीछे जल संकट की भूमिका अति विशेष हैं। किसानों की ज़मीन वर्षा की कमी के कारण दरक रही है। ज़मीन में फटी दरारें किसानों के हृदय को भी तार-तार कर रही है। कुछ किसानों की सामुहिक आत्महत्या के बाद किसानों ने हाल ही में दिल्ली के जंतर-मंतर पर उन किसानों की खोपड़ियों को रखकर धरना प्रदर्शन किया। किसान स्वयं ही परेशान है कि खेतों से उगाए तो क्या...पानी का ज़मीनी स्तर भी कम से कम होता जा रहा है। भारत के 18 राज्यों में सीधे तौर वर भूजल स्तर में भारी गिरावट आ चुकी है। इसमें भी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक सबसे अधिक प्रभावित है। भूजलस्तर का सीधा लिंक जलाशयों से होता है। लगभग 95 बड़े जलाशयों में क्षमता के मुकाबले सिर्फ 41 प्रतिशत पानी ही शेष बचा है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था वॉटर एड् के अनुसार ग्रामीण भारत में लगभग 6 करोड़ 30 लाख लोगों के पास स्वच्छ पेय जल नहीं हैं। इसका कोई समुचित हल भी अभी नहीं है। हम इज़राइल जैसे देश के समान भी कुशल प्रबंधक नहीं हैं जो समुद्र के खारे पानी को तुरंत स्वच्छ और मीठा कर पीने के लिए गिलास में भर कर दे देते हैं।

विभिन्न वर्षो एवं विभिन्न क्षेत्रों में भारत में जल की मांग
(बिलियन क्यूबिक मीटर)

क्षेत्र	वर्ष		
	2000	2025	2050
घरेलू उपयोग	42	73	102
सिंचाई	541	910	1072
उद्योग	08	22	63
ऊर्जा	02	15	130
अन्य	41	72	80
कुल	634	1092	1447

स्त्रोतः सेंट्रल वाटर कमीशन बेसिन प्लानिगं, डारेक्टोरेट, भारत सरकार 1999

एक आंकड़े के अनुसार वर्ष 2050 में पूरी दुनिया की 40 प्रतिशत आबादी पानी की क़िल्लत वाली जगहों पर रहेगा। इतना घोर संकट हो जाएगा कि लोग त्राहि-त्राहि करने लगेंगे। इतना ही नहीं एक दिलचस्प आंकड़ा ये भी है कि पुरी दुनिया की महिलाऐं पानी लाने के लिए प्रत्येक दिन 20 करोड़ घंटे मेहनत करती है। यानि 20 करोड़ घंटों को यदि वर्ष में बदल दिया जाए तो 23 हज़ार वर्ष होता है। अब अनुमान लगाया जाए कि कितना समय मात्र पानी लाने में महिलाओं का समाप्त हो जाता है, यह एक अचंभित करने वाला आंकड़ा है।

जनसंख्या पूरी दुनिया के लिए समस्या का मुद्दा बनता जा रहा है। भारत की स्थिति कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। इस समय दुनिया की आबादी 750 करोड़ के आसपास है। 2030 में यह आबादी 850 करोड़ हो जाएगी। 2050 में

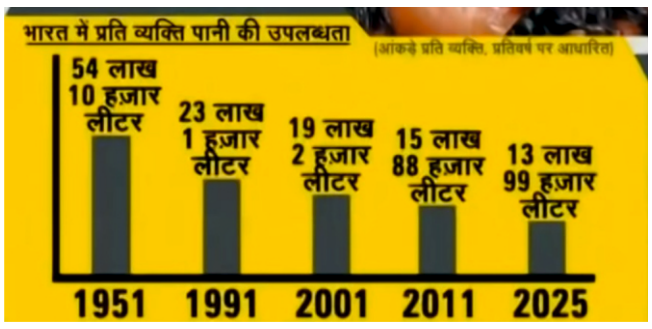

यह आंकड़ा 970 करोड़ को पार कर जाएगा। भारत 2022 तक दुनिया का आबादी में पहले पायदान पर अपनी उपस्थिति दर्ज़ करवाने के लिए आतुर है। उस समय तक भारत की आबादी 150 करोड़ तक पंहुच जाएगी। ऐसी स्थिति में पानी के स्रोत अपनी बेबसी दिखा चुके होंगे और घोर जल संकट का ख़तरा मानव जाति के लिए वीभत्स हो जाएगा। 2050 तक भारत में कृषि क्षेत्र में पानी की 80 प्रतिशत मांग होगी जिसे पूरा करना बहुत मुश्किल सा हो जाएगा।

जिस प्रकार उत्तराखंड उच्च न्यायालय का निर्णय आया ठीक उसी प्रकार न्यूज़ीलैंड में भी एक नदी वैंगनुई को भी जीवित प्राणी का दर्ज़ा दिया गया है। अब देखना ये है कि कानून को बनाने के बाद क्या दशा बदलेगी ? इस बात को नहीं नकारा जा सकता है कि हमारी सभ्यता का उद्भव और पोषण नदियों के किनारों पर ही हुआ है। यानि पानी के आसपास ही सारी सभ्यताऐं पनपी है। क्योंकि जल मूलभूत आवश्यकताओं के साथ-साथ हमारी परंपराओं और संस्कृति का भी अग्रदूत है। जल को देवता मानकर पूजा जाता है। क्योंकि इसके बिना न अन्न है न ही जीवन। धीरे-धीरे आधुनिकता की अंधी दौड़ ने रहने और बरतने की परंपरा और धारा ही बदल दी। लोग नदियों के किनारे छोड़ पहाड़ और चोटियों पर रहने के लिए आतुर हुए तो पानी और भूजलस्तर का भी हश्र दिनोंदिन बिगड़ता गया। और आज आलम ये है कि पानी की किल्लत भयंकर मुद्दा बन गया है।

पानी को पीने से लेकर शौचालय तक के उपयोग में हमारी लापरवाही भी हम पर भारी पड़ रही है। एक गिलास में पानी भर कर उससे दो घूंट पी कर फिर उसे हम फेंक देते हैं। ऐसा करना यानि पेयजल की बर्बादी और उसकी कीमत को न समझना ही है। बर्तन-कपड़ों को धोने में भी हमारी समझ जवाब दे देती है। ये बात अभी तो बहुत ही सामान्य सी लग रही हो किंतु आने वाले समय में एक बूंद का ज़िक्र करते हुए भी चिंता हो जाएगी। पानी के स्रोतों को हम लगातार गंदे करते जा रहे हैं। यही गंदगी न केवल पानी को दूषित और ख़त्म कर रही है बल्कि प्राकृतिक स्रोतों को हम सीमेंट आदि से निर्माण करने की ज़िद्द में उसको नष्ट करते जा रहे हैं। ग्रामीण भारत अपने इन्ही प्राकृतिक जल स्रोतों की अनुकंपा पर अपनी आवश्यकताओं को पूरी करता है। लेकिन विकास के मुहानों पर कहीं न कंही ये प्राकृतिक जल स्रोत धीरे-धीरे लुप्त से होते जा रहे हैं। पानी को बचाने की कवायद दस्तावेज़ी कब्रख़ानों की तह में है। ये दस्तावेज़ जिस दिन वास्तविकता में ही हम धरातल पर लाने के लिए प्रयासरत होंगे तभी हम भविष्य को इस संकट से बचाने में सहयोग दे पाएंगे।

भारत में तो यह नियम है कि निजी स्वामित्व में जो ज़मीन है उसमें जल स्रोत भी उसी के मालिकाना हक में आता है। अब इसका दोहन मनमुताबिक किया जाता है। या ये कहें कि अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है। बोरवेल करके पानी का उपयोग इतनी मात्रा में किया जाता है कि भूजलस्तर बहुत ही नीचे जा चुका है। तालाबों और कुओं की स्थिति तो दोनों ओर से ही दयनीय होती जा रही है। एक तो इन स्रोतों से पानी का उपयोग इसकी क्षमता से अधिक हो रहा है वहीं इसमें दूषित जल और कूड़ा-करकट मिला देने से इनको गंदा किया जा रहा है। बोरवेल, हैंडपंप से पानी की मात्रा का उपयोग भी अधिक मात्रा में होने से पानी की भारी कमी होती जा रही है। किसानों के खेतों से नमी गायब होते ही वो खेत दरकने लगते हैं। यानि किसान बेबस होकर फसलों की बर्बादी पर मूक बन जाता है। उसके आंसु उस खेत को नमी में नहीं ला सकते। इसलिए किसान मजबूरन आत्महत्याऐं करने पर मज़बूर हो रहे हैं।

इस धरती पर कुल उपलब्ध जल लगभग 1 अरब 36 करोड़ 60 लाख घन कि.मी. है। लेकिन इसमें 96.5 प्रतिशत जल समुद्री खारा जल है। इस जल का उपयोग समुद्री जीवों और वनस्पतियों के अतिरिक्त मनुष्य और अन्य जीव-जंतुओं के लिए उपयोग करने योग्य नहीं है। शेष 3.5 प्रतिशत जल मीठा है जिसका 24 लाख कि.मी. हिस्सा 600 मीटर गहराई में भूमिगत जल के रुप में विद्यमान है। लगभग 5 लाख कि.मी. जल गंदा और प्रदूषित हो चुका है। इस तरह से देखा जाए तो कुल 1 प्रतिशत जल ही पीने योग्य है। विश्व के कुल उपलब्ध जल का 2.5 प्रतिशत जल ही मानव उपयोग के लिए माना गया है। इसमें एक प्रतिशत भाग हिम यानि बर्फ के रुप में और 0.5 प्रतिशत भाग नमी के रुप में ही मौजूद है। अब इसे हैरानी की तरह देखा जाना चाहिए कि 1 प्रतिशत जल पर पूरी मानव जाति की आवश्यकताओं को पूरा करने का दबाव है। सिंचाई, उद्योग और कृषि कार्य आदि की निर्भरता भी इसी 1 प्रतिशत पर निर्भर है।

यहां विडंबना यह है विश्व की कुल आबादी के प्रतिशत आबादी के पास स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं है। विश्व के सभी देशों में जल संकट एक विकट समस्या के रुप में सामने है। भविष्य में एक रिपोर्ट के अनुसार एक बड़ी आबादी को विस्थापन का दंश झेलना पड़ेगा। पानी की क़िल्लत में जीना दुभर हो जाएगा। सारे देश आपस में जल के लिए युद्ध की स्थिति में खड़ें हो जाऐंगे। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि अगला विश्व युद्ध यदि होता है तो उसके मूल में जल ही मूल समस्या होगा। दुनिया का सबसे संवेदनशील एवं समस्याग्रस्त पश्चिम ऐशिया का ही क्षेत्र हैं जहां इस प्रकार की स्थिति हो जाऐगी।

संयुक्त राष्ट्र के जल मानकों को देखा जाए तो प्रतिदिन एक व्यक्ति को 50 लीटर जल उपलब्ध होना चाहिए। क्या यह वर्तमान में संभव है ? नहीं, कतई भी नहीं। ऐसे भी देश है जहां लोगों को एक महीने में 100 लीटर जल भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। क्या भारत ऐसी स्थिति को संभाल पाऐगा। वो भी तब जबकि न तो अभी की पीढ़ी न ही नई पीढ़ी इस संकट के लिए तैयार है। जल का उपयोग नवाबी शौक से पूरा करने की चाहत एक दिन आंखों का पानी भी सुखा देगा...इस बात के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। अथवा सुधरने के लिए हमें आगे आना होगा और जल का उपयोग बहुत ही सावधानी से करना होगा। हमें कुछ ठोस क़दम उठाने की आवश्यकता है ताकि सूखे और निर्जिव भविष्य के घोर संकट से बचा जा सके।

- सरकार एक ठोस जलप्रबंधन नीति को अपनाए।
- जल के दुरुपयोग के लिए कानून सख़्त किए जाएं तथा कार्यवाही की प्रक्रिया भी सख़्त ही हो।
- वर्षा के जल को प्रबन्धित करने के लिए कारगर योजना बनाने की आवश्यकता है।
- जलागम प्रबंधन जैसी परियोजनाओं को पारदर्शी और व्यापक तरीके से लागु करने की आवश्यकता है।
- जंगल और पहाड़ियों पर टैंच/गड्ढे आदि खोद कर वर्षा के जल को बहने से रोका जा सकता है। इससे भूजलस्तर में वृद्धि होगी।
- नदी-नालों के बहते जल को प्रबंधन किया जाना चाहिए तथा इस जल को रोककर उपयोग के लिए लाया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में न केवल ज़मीन में नमी आती है बल्कि भूजलस्तर में वृद्धि के कारण पानी का उचित उपयोग किया जा सकता है।
- वर्षा के जल को न केवल घरों में अपितु सभी इमारतों, मकानों और कार्यालयों में एकत्रित किये जाने की व्यवस्था इस संकट पर सबसे गहरा प्रभाव डालेगी।
- प्राकृतिक जल स्रोतों का रखरखाव एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
- जहां प्राकृतिक जल स्रोत हैं वहां पर वृक्षों एवं हरियाली को काटने पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए चाहे वो ज़मीन निजी स्वामित्व की ही क्यों न हो।
- जल प्रबंधन एवं संरक्षण विषय आरंभिक कक्षाओं का आधारभूत विषय होना चाहिए ताकि बच्चों से ही इस प्रवृति को मन-मस्तिष्क में डाला जा सके।

जल संरक्षण के प्रति संजीदा डॉ० एल सी शर्मा ने एक नायाब तरीक़ा सुझाया कि हर इमारत और मकान आदि के साथ ही 2 फुट के दायरे में दीवारों के साथ ही वर्षा जल को संरक्षित किया जा सकता है। क्योंकि सभी के पास मकान के आगे या पीछे ज़मीन का अभाव है इसलिए यह एक कारगर तरीक़ा साबित होगा। इसी प्रकार इस विषय पर कुछ संजीदा पर्यावरण प्रेमी भी बड़ी चिंता के साथ आने वाले समय को विकट ही देखते हैं। जल से जीवन तो है पर रहेगा भी...इसमें उनको शंका है।

अब समय है कि पानी के साथ बलात्कार और दुष्कर्म करना मानव बंद कर दें। ऐसा न हो कि त्राहि का वो मंज़र देखना पड़े कि ज़मीन फट जाए... मानव, पशु और अन्य जीव सड़कों और रास्तों पर ही बिखरें मिले। यह कड़वा तो लगेगा पढ़ने और सुनने में लेकिन यहां बिल्ली को देखकर तीतर का आंखे बंद कर ये सोचना कि अब अंधेरा हो गया है और बिल्ली नहीं देख पाऐगी, स्वयं को ही गुमराह करने जैसा होगा। जल संकट का भविष्य दूर नहीं है। इसका आरम्भ हो चुका है। स्वयं से सरकार तक वृहद और व्यापक पैमाने पर मंथन करने के साथ ही योजनाबद्ध होने की समय की मांग है। आज़ाद भारत में सुभाष बोस की ये पंक्तियां ' तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा' अब शायद इस प्रकार कहनी होगी कि **'तुम मुझे जल दो मैं तुम्हें जीवन दूंगा'..... क्योंकि अपने प्राणों से अधिक अनमोल है जल की एक-एक बूंद ....**

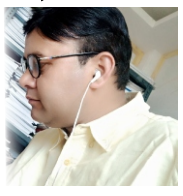

हेम राज चौहान
संपादक, द रीव टाइम्स
Chauhan.hemraj09@gmail.com,94184 04334

शिमला में जलापूर्ति एवं गुणवत्ता की निगरानी कर रही है सरकार : मुख्य सचिव

द रीव टाइम्स ब्यूरो

मुख्य सचिव बी. के. अग्रवाल ने शमला में जलापूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मई, 2018 के दृष्टिगत सरकार शिमला में जलापूर्ति एवं गुणवत्ता की निगरानी कर रही है, जिसके फलस्वरूप सम्बद्ध विभागों के साथ जलापूर्ति के लिए समन्वय स्थापित किया गया है।

उन्होंने कहा कि शिमला शहर के निवासियों को पहली बार प्रतिदिन पानी की आपूर्ति की जा रही है तथा नगर निगम के सभी वार्डों को समय सारिणी के अनुसार 48 मिलियन लीटर से अधिक पानी की प्रतिदिन आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है ।

उन्होंने कहा कि जलापूर्ति में वृद्धि गुम्मा पम्पिंग स्टेशन एवं जाखू, ढिंगूधार, कामना देवी और नॉर्थओक के पुराने पंपों को बदले जाने के कारण हुई है । शिमला जल प्रबन्धन निगम लिमिटेड (एसजेपीएनएल) ने 14 किलोमीटर लम्बी रिसाव वाली पुरानी पाईप लाईन को बदल पानी की बर्बादी को रोका है। इस वर्ष नए पानी के कनैक्शन पर रोक नहीं है तथा 1489 नए पानी के कनैक्शन दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि समयबद्ध जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इस वर्ष पुराने 154 कंट्रोल वाल्वस बदले गए हैं। उन्होंने कहा कि गुम्मा, गिरी तथा कोटी बरांडी स्थित फिल्टरेशन प्रणालियों को स्तरोन्नत किया गया है जिसके कारण स्वच्छ जल की आपूर्ति में तेजी सुनिश्चित हुई है। जल की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुसार करने के लिए की 20 स्थानों से जल के नमूने एकत्रित कर उनकी जांच आईजीएमसी में की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष शिमला में पीलिया रोग का एक भी मामला प्रकाश में नहीं आया है। उन्होंने कहा कि सभी जल भण्डारण टैंकों की सुरक्षा एवं सफाई के लिए उनकी तालाबंदी तथा पार्षदों और आमजनता की उपस्थिति में वर्ष में दो बार टैंकों की सफाई की जा रही है। एसजेपीएनएल द्वारा उठाए गए प्रभावी कदमों के फलस्वरूप स्थापित 54 एमएलडी क्षमता के साथ अब 60 एमएलडी तक पानी उठाने में सक्षम है।

घंडल के पास ऑल्टो को गलत ओवरटेक करती हुई बाइक खाई में गिरी, चौपाल के मुनीष की मौत

द रीव टाइम्स ब्यूरो

घणाहट्टी के साथ लगते घंडल में बीती शनिवार रात को एक बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें चौपाल निवासी मुनीष रिक्टा की मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक घंडल के पास एक बाइक ने पहले तो ऑल्टो कार से ओवरटेक किया, इसके बाद वह बेकाबू होते हुए खाई में गिर गया। प्रत्यक्षदर्शी शशिपाल ने पुलिस को बताया की वह घंडल के पास वह रोड क्रॉस कर रहा था। इसी बीच एक बाइक तेज रफ्तार में आया और ऑल्टो से ओवरटेक करते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से को आईजीएमसी ले जाया गया। यहां पर डॉक्टरों से मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

नौकरी की तलाश में मोहाली पहुंची हिमाचल की युवती से चंडीगढ़ में सामूहिक दुष्कर्म

द रीव टाइम्स ब्यूरो

नौकरी की तलाश में मोहाली पहुंची हिमाचल प्रदेश की एक युवती से सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। थाना फेज-11 की पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है । दो आरोपियों अनमोल व राजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरे आरोपी पूनिया की तलाश में पुलिस टीमें छापामारी कर रही हैं।

पीड़िता हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन की रहने वाली है । पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया कि वह इंडस्ट्रियल एरिया में एक ऑटो मोबाइल कंपनी में काम करती थी । कुछ समय पहले उसका एक्सिडेंट हो गया था, जिसके चलते उसे नौकरी छोड़नी पड़ी। पीड़िता ने बताया कि हादसे के बाद उसने अपने एक सहकर्मी को कहा कि उसके लिए नौकरी की तलाश करे।

13 मई को वह नौकरी के संबंध में इंटरव्यू देने के लिए मोहाली आई थी। जहां पर उसकी मुलाकात गुड्डू से हुई। उसके बाद वह इंटरव्यू के लिए गई। उसने बताया कि सेक्टर-67 में इंटरव्यू के बाद उसे देरी हो गई थी। ऐसे में उसका साथी गुड्डू उसे अपने दोस्त के चंडीगढ़ स्थित कमरे में ले गया ।

हिमाचल में इन विधानसभा क्षेत्रों में हुआ सबसे ज्यादा और सबसे कम मतदान

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए हुए मतदान में लोगों में खासा उत्साह दिखा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सिराज विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। यहां 81.47 फीसदी मतदान हुआ है। वहीं लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम मतदान हुआ है। यहां 61.79 फीसदी मतदान हुआ है। आईपीएच मंत्री महेंद्र सिंह के विधानसभा क्षेत्र धर्मपुर में 2014 के मुकाबले कम मतदान हुआ है। 2014 में यहां 63.32 फीसदी मतदान हुआ था वहीं इस बार 2019 के चुनावों में यहां 62.71 फीसदी मतदान हुआ है। लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र में भी 2014 के मुकाबले कम मतदान हुआ है। 2014 में यहां 62.25 फीसदी मतदान हुआ था वहीं इस बार 2019 के चुनावों में यहां 61.79 फीसदी मतदान हुआ है। देवभूमि हिमाचल में मतदान के तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए हैं। मतदाताओं ने लोकसभा चुनाव के लिए इस बार रिकॉर्ड 71 फीसदी मतदान कर इतिहास रच दिया है। सूबे में यह अब तक सबसे ज्यादा मतदान है। इससे पहले 1998 के लोकसभा चुनाव में ही 65.32 प्रतिशत मतदान का सर्वाधिक रिकॉर्ड था।

शिक्षा का उद्देश्य बच्चों का समग्र विकास हो: राज्यपाल

संजय गांधी ओम प्रकाश गर्ग मैमोरियल पब्लिक स्कूल के नये भवन का किया शुभारम्भ

द रीव टाइम्स ब्यूरो

राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को केवल अक्षर ज्ञान ही नहीं, बल्कि उनका समग्र विकास होना चाहिए। उन्होंने बच्चों में संस्कार की शिक्षा पर बल देते हुए कहा कि विद्यालयों में ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए, जो राष्ट्र निर्माण में सहायक हो।

राज्यपाल कुरुक्षेत्र के सुजरा-बाबैन में संजय गांधी ओम प्रकाश गर्ग मैमोरियल पब्लिक स्कूल के नये भवन के शुभारम्भ अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी भी शिक्षण संस्थान का मूल उद्देश्य बच्चों को सुशिक्षित बनाना है, जिनमें विज्ञान और तकनीकी की पूर्ण जानकारी हो, शारीरिक रूप से स्वस्थ हों और वे संस्कारित बनें। जिस शिक्षा में यह उद्देश्य नहीं है वह अधूरी है और इसके बिना हम अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते।

आध्यात्मवाद संस्कृति की देन है आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति : राज्यपाल

आयुर्वेद में अधिक अनुसंधान की आवश्यकता पर दिया बल

द रीव टाइम्स ब्यूरो

राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति आध्यात्मवाद संस्कृति की देन है, जिस पर आज अधिक अनुसंधान की आवश्यकता है ताकि इसका लाभ व्यापक स्तर पर मिल सके।

राज्यपाल कुरुक्षेत्र के मल्टी आर्ट सेंटर में अखिल भारतीय आयुर्वेद विशेष (स्नातकोत्तर) संगठन के हरियाणा चौप्टर द्वारा ''मस्क्युस्कैलेटल डिस्ऑर्डर'' पर 41वें राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। इस सम्मेलन में करीब 1000 प्रतिभागियों ने भाग लिया और विभिन्न संस्थानों के स्नातकोत्तर शोधार्थियों ने 185 शोधपत्र प्रस्तुत किए।

उन्होंने कहा कि भारतीय ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले मानव के स्वास्थ्य के दृष्टिगत चिकित्सा पद्धति की रचना की, जो जीवन शैली का एक हिस्सा थी। जीवन का मूल उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम को करते हुए मुक्ति को प्राप्त करना है, जिसका पहला आधार ही स्वस्थ शरीर का होना है। अस्वस्थ व्यक्ति बुद्धिमान होते हुए भी समाज में योगदान नहीं कर पाता है। स्वस्थ शरीर ही सकारात्मक सोच से विश्व का मार्गदर्शन कर सकता है। अखिल भारतीय आयुर्वेद विशेष (स्नातकोत्तर) संगठन इस चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

आचार्य देवव्रत ने कहा कि आयुर्वेद का जन्म भारत की धरती पर हुआ और यह विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है। लेकिन, एलोपैथी की तरह इस पर व्यापक अनुसंधान नहीं हुआ। संपूर्ण मानव को जो लाभ इस चिकित्सा पद्धति से मिलना था, वह उससे वंचित रह गया। उन्होंने युवा चिकित्सकों से इस पर गहन अनुसंधान की आवश्यकता पर बल दिया।

बिजली गुल होने से ठप नहीं होगा इंटरनेट, सरकार ने बनाया ये प्लान

द रीव टाइम्स ब्यूरो

बिजली जाने से जनजातीय क्षेत्रों में फोन और इंटरनेट ठप नहीं होगा। इसके लिए हर टावर पर सोलर पैनल लगाने की तैयारी है । पिछले साल जनजातीय इलाकों में बर्फ में पर्यटकों और आम लोगों के फंसने तथा इस बीच उनके फोन में सिग्नल नहीं होने के चलते उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। इसी के दृष्टिगत सरकार गंभीर हो गई है। मुख्य सचिव बीके अग्रवाल की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में हुई बैठक में इसके लिए विचार-विमर्श हुआ। अग्रवाल ने आईटी निदेशक के नेतृत्व में इसके लिए एक सब कमेटी बना दी है।

इस कमेटी के सदस्य बीएसएनएल, रिलायंस, भारत नेट के प्रतिनिधि होंगे। यह कमेटी इसका समाधान खोजेगी। दूसरी ओर बीएसएनएल ने इसके समाधान के लिए हिमाचल सरकार से एक करोड़ रुपये की मांग करते हुए अपने सभी 40 टॉवरों पर सोलर पैनल लगाने की भी पेशकश की है।

वहीं रिलायंस ने भी अपने सिग्नल को दुरुस्त करने का आश्वासन दिया है। सीएस बीके अग्रवाल ने बताया कि बिजली की कनेक्टिविटी नहीं रहने पर इन क्षेत्रों में बर्फबारी के दौरान जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है।

इसके लिए भी डीजल खत्म होने की स्थिति में कोई चारा नहीं रहता है। पिछले साल के अनुभव को देखते हुए सरकार इस बारे में बहुत गंभीर है। इसीलिए सब कमेटी का गठन किया है।

चट्टान तोड़ने के लिए 13 घंटे बंद रखा कालका शिमला एनएच, जाम में फंसे रहे हजारों वाहन

द रीव टाइम्स ब्यूरो

कालका-शिमला नेशनल हाईवे पर सनवारा के समीप हवा में लटक रही चट्टान को तोड़ने के लिए प्रशासन ने 13 घंटे तक मार्ग वाहनों के लिए बंद कर दिया। शनिवार देर रात करीब साढ़े आठ बजे प्रशासन ने अचानक एनएच बंद करने का फरमान जारी किया। व्हाट्सएप पर भी प्रशासन ने मार्ग बंद करने से मात्र आधा घंटा पहले इसका अलर्ट डाला। अलर्ट सात घंटे एनएच बंद करने का था, लेकिन शनिवार रात करीब नौ बजे बंद हुआ हाईवे रविवार सुबह 10 बजे तक बमुश्किल बहाल हो पाया।

दोपहर लगभग 12 बजे तक हाईवे के दोनों और ही नहीं, बल्कि तंग संपर्क मार्गों पर भी वाहनों का लंबा-चौड़ा जाम लगा रहा। वीकएंड पर शिमला आ रहे पर्यटकों के अलावा अन्य मुसाफिरों की पूरी रात संपर्क मार्गों पर भूखे-प्यासे भटकते ही गुजर गई। हाईवे के यातायात को अलग-अलग संपर्क रूटों पर परिवर्तित कर दिया गया था। देर शाम जब हाईवे बंद करने का फरमान जारी हुआ, तब तक सोलन से परवाणू तक सैकड़ों गाड़ियां अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थीं।

भेड़ों को कुचलकर जीप चालक मौके से फरार, 9 भेड़ों की मौत

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला मुख्यालय के साथ लगते वॉशिंग में मंडी जिला के एक भेड़ पालक की भेड़ों को कुचलकर जीप चालक मौके से फरार हो गया। नौ भेड़ों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि चार भेड़ें गंभीर घायल हो गई हैं। भेड़ों का पोस्टमॉर्टम किया गया है। पुलिस फरार जीप चालक की तलाश में जुट गई है। भेड़पालक लाहौल स्पीति जा रहा था। हादसे के तुरंत बाद घायल भेड़ों को ढालपुर स्थित पशुपालन विभाग के अस्पताल लाया गया जहां उनका उपचार किया गया।

तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने को लेकर हुए हादसे में भेड़ पालकों में डर का माहौल है। गर्मी आने पर भेड़ पालक लाहौल की जोतों पर लेकर जाते हैं।

हिमाचल में एनडीआरएफ बटालियन तैनाती के गृह मंत्रालय ने दिए आदेश

द रीव टाइम्स ब्यूरो

केंद्र सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से बेहद संवेदनशील माने जाने वाले हिमाचल प्रदेश के लिए नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स (एनडीआरएफ) की एक बटालियन की तैनाती के आदेश दिए हैं। आपदा की स्थिति में तत्काल राहत अभियान चलाने वाली एनडीआरएफ की इस बटालियन में आईटीबीपी के जवान तैनात होंगे। हिमाचल में प्राकृतिक आपदा आने पर पड़ोसी राज्यों पंजाब से बटालियन आती है। यहां की भौगोलिक स्थिति से पार पाना इतना आसान नहीं होता है। इसलिए सूबे के लिए एनडीआरएफ बटालियन की पिछले लंबे समय से प्रदेश सरकार केंद्र से मांग कर रही थी। हिमाचल के अलावा जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में भी बटालियनें तैनात होंगी।

मुख्य सचिव ने पौंग बांध विस्थापितों के मामलों को शीघ्र निपटाने का किया आग्रह

द रीव टाइम्स ब्यूरो

मुख्य सचिव बी.के. अग्रवाल ने नई दिल्ली में भारत सरकार के जल संसाधन सचिव यू. पी. सिंह के साथ पौंग बांध विस्थापितों के मामलों को शीघ्र निपटाने को लेकर बैठक की। यूपी सिंह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पौंग बांध विस्थापितों के मामलों को निपटाने के लिए गठित की गई उच्चाधिकार समिति के अध्यक्ष हैं । मुख्य सचिव ने उनसे अनुरोध किया कि लम्बे समय से पौंग बांध विस्थापितों के लम्बित मुद्दों को लेकर शीघ्रातिशीघ्र समिति की अगली बैठक आयोजित की जाए ताकि मामलों का शीघ्र निपटारा किया जा सके। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों के मध्य हुई सहमति के आधार पर जिला गंगा नगर में विस्थापितों को भूमि पहले चरण में जल्द से जल्द आवंटित की जाए ।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

भारतीय नौसेना ने MRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारतीय नौसेना द्वारा मध्यम दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल (MRSAM) का सफल परीक्षण किया गया है। रक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में यह जानकारी सार्वजनिक की गई है। एमआरएसएएम के सफल परीक्षण से भारतीय नौसेना की युद्ध प्रतिरोधक क्षमता में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होगी।

भारतीय नौसेना के पोत 'कोच्चि' और 'चेन्नई' ने पश्चिमी समुद्र तट पर यह परीक्षण किया गया। इस मिसाइल का परीक्षण भारतीय नौसेना, डीआरडीओ और इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। भारतीय नौसेना द्वारा किये गये परीक्षण के दौरान दो वॉर शिप की मिसाइलों को एक शिप से ऑपरेट किया गया।

आरोही पंडित अटलांटिक महासागर पार करने वाली विश्व की पहली महिला बनी

द रीव टाइम्स ब्यूरो

आरोही पंडित अटलांटिक महासागर के ऊपर लाइट स्पोर्ट एयरक्राफ्ट (एलएसए) में अकेली उड़ान भरने वाली विश्व की पहली महिला पायलट बन गई हैं। उन्होंने केवल सात महीने के प्रशिक्षण के बाद एलएसए से अटलांटिक महासागर के ऊपर अकेले ही उड़ान भरी। उन्होंने 3000 किलोमीटर की दूरी तय कर अपने छोटे से एयरक्राफ्ट के साथ कनाडा के नुनावुट में इकालुइट हवाईअड्डे पर उतरीं. वह इस दौरान ग्रीनलैंड और आइसलैंड में भी रुकी थीं। इसके लिए आरोही पंडित ने सात महीने की कड़ी ट्रेनिंग ली थी।

150 फुट सिकुड़ गया है चांद: नासा अध्ययन

द रीव टाइम्स ब्यूरो

नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) द्वारा किये गये हालिया अध्ययन के अनुसार चांद का आकार लगातार सिकुड़ रहा है। नासा के लूनर रीकॉनिसेंस ऑर्बिटर (LRO) द्वारा ली गईं 12,000 से अधिक तस्वीरों के विश्लेषण से यह जानकारी सामने आई है। इस अध्ययन में यह पाया गया है कि चंद्रमा का आकार विभिन्न कारणों से लगातार सिकुड़ रहा है। लूनर रीकॉनिसेंस ऑर्बिटर द्वारा चंद्रमा की 3डी तस्वीरें ली गई हैं। इन तस्वीरों में चंद्रमा में हुए परिवर्तनों को देखा जा सकता है। वैज्ञानिकों ने इन तस्वीरों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया तथा चंद्रमा की सतह पर हो रहे बदलावों का अध्ययन करके यह रिपोर्ट जारी की।

पाकिस्तान ने आईएमएफ के साथ समझौता राशि पर हस्ताक्षर किये

द रीव टाइम्स ब्यूरो

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) पाकिस्तान को तीन साल में छह अरब डॉलर (करीब 42 हजार करोड़ रुपये) की सहायता देने जा रहा है। दोनों के बीच इस संबंध में 12 मई 2019 को एक समझौता हुआ है। पाकिस्तान फिलहाल आर्थिक संकट से जूझ रहा है। आइएमएफ के अनुसार इस समझौते का मुख्य उद्देश्य घरेलू और बाहरी असंतुलन को कम करने के साथ ही विकास में रुकावट को दूर करना, पारदर्शिता को बढ़ाना और सामाजिक खर्चे में वृद्धि करके मजबूत और अधिक समावेशी विकास हेतु पाकिस्तान को तैयार करना है।

भावना कंठ ने रचा इतिहास, देश की पहली महिला ऑपरेशनल फाइटर पाइलट बनीं

द रीव टाइम्स ब्यूरो

23 मई 2019 को फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ भारतीय वायुसेना की पहली ऑपरेशनल फाइटर पायलट बन गई हैं। फाइटर एयरक्राफ्ट में उन्होंने दिन में उड़ान भरने की ट्रेनिंग पूरी कर ली है। इसका मतलब है कि अब फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत किसी हवाई युद्ध में शामिल हो सकती हैं। फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाली महिलाओं के पहले बैच की सदस्य हैं। फिलहाल भावना कंठ राजस्थान में पाकिस्तान से लगने वाली सीमा पर तैनात हैं। भारतीय वायुसेना में करीब 94 महिला पायलट हैं। ये महिला पायलट मिग, मिराज, जेगुआर या सुखोई जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं उड़ातीं। महिला पायलट हेलीकॉप्टर और परिवहन एयरक्राफ्ट पर ही तैनात की जाती हैं। लेकिन भारतीय वायुसेना महिला फाइटर पायलटों को मौका देकर देश की पहली ऐसी सशस्त्र सेना बन गई, जिसने महिलाओं को सीधे मोर्चे पर उतार दिया।

आरबीआई : बैंकों, एनबीएफसी पर नजर रखने हेतु विशेष काडर बनाएगा

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वाणिज्यिक बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) पर निगरानी रखने हेतु एक विशेषीकृत निगरानी एवं नियामकीय कॉडर बनाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय आरबीआई के बोर्ड की 21 मई 2019 को चेन्नई में हुई बैठक में लिया गया। आरबीआई के बोर्ड ने मौजूदा आर्थिक हालात, वैश्विक एवं घरेलू चुनौतियों तथा रिजर्व बैंक के विभिन्न क्षेत्र के कारोबार की समीक्षा की। आरबीआई ने एक बयान में कहा है कि बोर्ड ने बढ़ती विविधता, जटिलता और भारतीय वित्तीय क्षेत्र के अंदर बढ़ते अंतर संबंधों के संदर्भ में आरबीआई में निगरानी के मौजूदा ढाचे की भी समीक्षा की है।

लोकसभा चुनाव-2019 में दर्ज हुआ इतिहास में सर्वाधिक मतदान प्रतिशत

द रीव टाइम्स ब्यूरो

चुनाव आयोग ने बताया है कि साल 2019 लोकसभा चुनाव में 67.10: (अंतरिम) मतदान हुआ है, जो लोकसभा चुनाव के इतिहास में सर्वाधिक है। इससे पिछला सर्वाधिक मतदान प्रतिशत 66.44 था, जो 2014 लोकसभा चुनाव में दर्ज हुआ था। गौरतलब है कि साल 2019 लोकसभा चुनाव 11 अप्रैल और 19 मई के बीच सात चरणों में हुआ जबकि गणना 23 मई 2019 को होगी।

विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस-2019

द रीव टाइम्स ब्यूरो

विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस अर्थात वर्ल्ड टेलीकम्युनिशेन एंड इन्फॉर्मेशन सोसाइटी डे प्रत्येक वर्ष 17 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य इंटरनेट और नई प्रौद्योगिकियों द्वारा समाज में आये सामाजिक परिवर्तनों से लोगों को परिचित कराना है। वर्ष 2019 का विषय है - मानकीकरण की खाई को पाटना (Bridging the standardization gap)। इस दिन लोगों के मूलभूत मानव अधिकारों के प्रति लोगों का ध्यान केन्द्रित करना तथा समाज के बेहतर विकास के लिए प्रस्तुत की गई सूचना को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। इसी के चलते वर्ष 1973 में मैलेगा-टोर्रीमोलिनोन्स में एक सम्मेलन में 17 मई को यह दिवस मनाये जाने की घोषणा की गई थी।

नासा का पेलोड लेकर जाएगा चंद्रयान-2

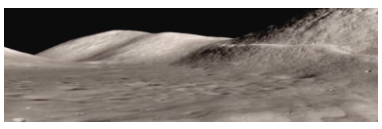

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने 15 मई 2019 को कहा कि जुलाई में भेजे जाने वाले भारत के दूसरे चंद्र अभियान में 13 पेलोड होंगे और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का भी एक उपकरण होगा। इस अंतरिक्ष यान का वजन 3.8 टन है. इस यान में तीन मोड्यूल (विशिष्ट हिस्से) ऑर्बिटर, लैंडर (विक्रम) और रोवर (प्रज्ञान) हैं। नासा इस मॉड्यूल के जरिए धरती और चांद की दूरी को नापने का कार्य करेगी। इसरो ने चंद्र मिशन के बारे में कहा कि 13 भारतीय पेलोड (ओर्बिटर पर आठ, लैंडर पर तीन और रोवर पर दो पेलोड तथा नासा का एक पैसिव एक्सपेरीमेंट (उपरकण) होगा।

गृह मंत्रालय ने इंफोसिस फाउंडेशन का पंजीकरण रद्द किया

द रीव टाइम्स ब्यूरो

गृह मंत्रालय ने 13 मई 2019 को गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) इंफोसिस फांउडेशन का पंजीकरण रद्द करने की घोषणा की है। इंफोसिस के खिलाफ नियमों के खिलाफ जाकर विदेशी चंदा प्राप्त करने का आरोप लगाया गया है। गृह मंत्रालय के अनुसार नियमों का कथित रूप से उल्लंघन किया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा इंफोसिस फाउंडेशन को वर्ष 2018 में कारण बताओ नोटिस जारी किया था। गृह मंत्रालय द्वारा कहा गया है कि संगठन ने विदेशी धन की प्राप्ति और व्यय का पिछले कुछ वर्षों से वार्षिक ब्योरा प्रस्तुत नहीं किया था। बार-बार पत्र जारी किए जाने पर भी यह कदम उठाना पड़ा है।

फीफा ने 2022 विश्व कप में 48 टीमों को शामिल करने की योजना को किया रद्द

द रीव टाइम्स ब्यूरो

फीफा ने कतर में 2022 में होने वाले विश्व कप में 48 टीमों को शामिल करने के प्रस्ताव को रद्द कर दिया है। इस खाड़ी देश में 2022 के टूर्नामेंट अब पहले की तरह 32 देश ही भाग लेंगे। फीफा ने कहा कि उसने इस योजना को विस्तार से देखने और व्यापक परामर्श प्रक्रिया के बाद रद्द कर दिया। फीफा ने एक बयान में कहा की टूर्नामेंट को अब इसके मूल रूप से यानी 32 टीमों के साथ खेला जाएगा और पांच जून को फीफा की अगली कांग्रेस में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

कमाई के मामले में देश की सबसे बड़ी कंपनी बनी रिलायंस इंडस्ट्रीज

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हाल ही में मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) कमाई के मामले में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी) को पछाड़कर देश की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है. साल 2018-19 में आरआईएल की कमाई 6.23 लाख करोड़ रुपये रही जबकि आईओसी ने 6.17 लाख करोड़ रुपये कमाए। इस उपलब्धि के साथ आरआईएल रेवेन्यू, मुनाफे और मार्केट कैप सभी तीनों मानकों पर देश की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। लगभग एक दशक पहले इंडियन ऑयल के मुकाबले आईओसी का कारोबार आधा था, लेकिन कंपनी द्वारा दूरसंचार, खुदरा और डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में विस्तार करने से उसके कारोबार में तेजी से वृद्धि हुई। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, साल 2018-19 के दौरान आरआईएल का रेवेन्यू 44.8 प्रतिशत की बढ़त के साथ 5.67 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया, वहीं आईओसी का रेवेन्यू 28.03 प्रतिशत बढ़कर 5.28 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया।

आरबीआई जारी करेगा 10 के नए नोट

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने हाल ही में 10 रुपये का नया नोट जारी करने की घोषणा की। इस नए नोट पर गवर्नर शक्तिकान्त दास के हस्ताक्षर होंगे। इस नोट का डिजाइन महात्मा गांधी (नयी) श्रृंखला के 10 रुपये के बैंक नोट के समान होगा। आरबीआई ने कहा कि पूर्व में जारी 10 रुपये के सभी नोट चलन में बने रहेंगे। आरबीआई गर्वनर शक्तिकांत दास के हस्ताक्षर वाले महात्मा गांधी न्यू सीरीज में 200 और 500 रुपये के नए नोटों को जारी करने की भारतीय रिजर्व बैंक ने गवर्नर घोषणा की थी. वहीं

आरबीआई 20 रुपये के नए नोट जारी करने की भी बात कह चुका है। लेकिन आरबीआई के अनुसार पुराने 20 के नोट भी चलते रहेंगे।

बांग्लादेश ने पाक नागरिकों के वीजा पर लगाई रोक

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हाल ही में पाकिस्तान के साथ राजनयिक गतिरोध के बीच इस्लामाबाद स्थित बांग्लादेश उच्चायोग ने एक सप्ताह के लिए पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा देने पर रोक लगा दी है। यह जानकारी बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने दी। बांग्लादेश ने साल 1971 के मुक्ति संग्राम के कई युद्ध बंदियों को फांसी देने का 2013 में फैसला किया था, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। पाकिस्तानी उच्चायुक्त को वीजा देने से इनकार करने के बाद दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध बीते एक साल के काफी बिगड़े हुए हैं। मार्च 2018 में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने सकलैन सयैदह को ढाका में नए उच्चायुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए प्रस्तावित किया था लेकिन बांग्लादेश ने दस्तावजों को स्वीकार करने से इंकार कर दिया था।

रक्षा मंत्रालय ने मिलिट्री नर्सिंग स्टाफ को एक्स-सर्विसमैन दर्जा देने हेतु मंजूरी दी

द रीव टाइम्स ब्यूरो

रक्षा मंत्रालय द्वारा चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की मीटिंग में चर्चा उपरांत तथा सैद्धांतिक सहमति के बाद मिलिट्री नर्सिंग स्टाफ (एमएनएस) को भी एक्स-सर्विसमैन का दर्जा दिए जाने को मंजूरी दी गई। रक्षा मंत्रालय का मानना है कि इसमें तकनीकी तौर पर एमएनएस अधिकारी एक्स-सर्विसमैन की दी गई परिभाषा में नहीं आते हैं, इसलिए सरकारी दस्तावेजों में इस परिभाषा का संशोधन किया जायेगा। थल, जल और वायु सेना में अहम भूमिका निभाने वाली 'फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स' अर्थात मिलिट्री नर्सिंग सर्विस (एमएनएस) की महिला अधिकारियों को जल्द ही दूसरे फौजियों की तरह एक्स सर्विसमैन का दर्जा प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त सेवानिवृत्त अधिकारियों के बच्चों को कॉलेज में दाखिले में भी सुविधा मिलेगी।

समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला एशिया का पहला देश ताइवान बना

द रीव टाइम्स ब्यूरो

ताइवान की संसद ने हाल ही में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाले बिल को मंजूरी दे दी है। ताइवान ऐसा करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। विश्वभर के लाखों समलैंगिकों में ताइवान की संसद के फैसले से खुशी की माहौल है।

ताइवान की संसद में समलैंगिक विवाह को लेकर यह वोटिंग यहां की संवैधानिक कोर्ट के उस आदेश के दो साल बाद हुई है, जिसमें अदालत ने विवाह से संबंधित मौजूदा कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। यह कानून एक महिला और पुरुष के बीच शादी को ही वैधानिक मानता था।

डीआरडीओ ने अभ्यास ड्रोन का सफल परीक्षण किया

द रीव टाइम्स ब्यूरो

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने 13 मई 2019 को ओडिशा के चांदीपुर में 'अभ्यास' ड्रोन का सफल परीक्षण किया। परीक्षण के समय अभ्यास ड्रोन को विभिन्न राडार और इलेक्ट्रो अहृप्टिक सिस्टम द्वारा ट्रैक किया गया था और सही तरीके से नेविगेशन मोड में रखा गया था। अभ्यास ड्रोन को एक अहृटोपायलट की मदद से स्वतंत्र उड़ान हेतु डिजाइन किया गया है। इसके नेविगेशन के लिए देश में ही विकसित माइक्रो - इलेक्ट्रोमेकैनिकल सिस्टम (एमईएमएस) आधारित नेविगेशन प्रणाली का उपयोग किया गया है।

मानव शव से खाद बनाने की मंजूरी

द रीव टाइम्स ब्यूरो

वॉशिंगटन अमेरिका का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने मानव शव से खाद बनाने वाले बिल को मंजूरी दे दी है। मई 2020 से लागू होने वाले इस नियम के तहत लोगों के पास अपने शव को कम्पोस्टिंग के लिए देने का विकल्प होगा। इस बिल का मकसद अंतिम संस्कार से होने वाले कार्बन उत्सर्जन में कटौती करना है। नया नियम अगले साल मई में लागू होगा। इसके तहत लोगों के पास यह विकल्प होगा कि वे खुद के शव को खाद बनाने के लिए दे सकें।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

बिल गेट्स ने पीएम को दी बधाई, कहा– मोदी की जीत से लोगों के जीवन स्तर में होगा सुधार

द रीव टाइम्स ब्यूरो

अमेरिकी व्यवसायी और माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीत की बधाई दी है। गेट्स ने भरोसा जताया है कि स्वास्थ्य, पोषण और विकास के प्रति मोदी की प्रतिबद्धता से लोगों की जिंदगी में उल्लेखनीय सुधार आएगा।

अमेरिकी कंपनी सिस्को के चेयरमैन जॉन टी चौंबर्स समेत कई उद्यमियों ने भी पीएम मोदी को जीत की बधाई दी है। चौंबर्स ने ट्वीट किया है, 'चुनावी जीत के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई। मुझे यकीन है कि अगले पांच में उनके नेतृत्व में भारत आर्थिक और समेकित विकास में दुनिया में अग्रणी बना रहेगा। फिर एक बार मोदी सरकार।'

गौरतलब है कि इसके पहले पीएम मोदी के नेतृत्व में मिली जीत के बाद कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मोदी को बधाई संदेश मिले हैं। विदेशों से मिले बधाई संदेश की बात करें तो अमेरिका, चीन, जापान, इजरायल, पाकिस्तान समेत कई देशों ने मोदी को इस ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी है। इजरायल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी को करीबी दोस्त बताते हुए हिंदी में ट्वीट कर उन्हें इस प्रचंड जीत की बधाई दी थी।

फिर से धुआं और राख उगल रहा बाली का माउंट आगुंग

द रीव टाइम्स ब्यूरो

इंडोनेशिया के बाली स्थित माउंट आगुंग हमेशा की तरह फिर से धुआं और राख उगल रहा है। इसके कारण बाली आने-जाने वाली सभी उड़ानों को रद कर दिया गया है। इस महीने आगुंग में तीसरी बार ज्वालामुखी फटने की घटना हुई है इससे पहले 21 और 18 मई को आगुंग के ज्वालामुखी से धुएं और राख का गुबार निकला था।

बाली के माउंट आगुंग में ज्वालामुखी फटने की घटना हुई थी जो 4 मिनट 30 सेकेंड तक हुई। इसके बाद द्वीप पर हर ओर राख बिखरी हुई है। सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड के अनुसार, राख की बारिश के कारण आस-पास के कारांगासेम और बांगली क्षेत्र के गांव प्रभावित हैं। लेकिन अब तक गांवों को खाली कराने का आदेश नहीं आया है। वर्ष 2017 में आगुंग दोबारा से सक्रिय हुआ था।

इंडोनेशिया का वोलकैनोलॉजी सेंटर और जियोलॉजिकल डिजास्टर मिटीगेशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा, राख कहां से निकल रहा है यह अभी देखना मुश्किल है लेकिन लावा फटने की तेज आवाजें सुनी जा सकती हैं।

भारतीय दवा कंपनी पर खतरा, अमेरिका में लग सकता है 6 हजार करोड़ से ज्यादा का जुर्माना

द रीव टाइम्स ब्यूरो

अमेरिका के 44 राज्यों ने 20 जेनरिक दवा कंपनियों के खिलाफ मुकद्मा किया है। इनमें सात भारतीय कंपनियां भी हैं। इनमें से 5 भारतीय कंपनियों को राज्यों के अटॉर्नी जनरल्स की नोटिस मिली है, जबकि बाकी को न्याय विभाग की जांच का सामना करना पड़ेगा। इस मुकदमे के तहत सबसे ज्यादा 87.3 करोड़ डॉलर (करीब 6110 करोड़ रुपये) का जुर्माना भारतीय कंपनी ग्लेनमार्क पर लगाया जा सकता है।

इन सभी दवा कंपनियों पर आरोप है कि उन्होंने 2013 से 2015 के बीच 112 दवाओं की कीमतें कृत्रिम तरीके से बढ़ाने के लिए गोलबंदी की है। इस मुकदमे में जिन सात भारतीय दवा कंपनियों का नाम है उनमें वॉकहार्ड्ट, डॉ. रेड्डीज लेबोरेटरीज, अरबिंदो फार्मा, ग्लेनमार्क फार्मा, ल्यूपिन, जाइडस फार्मा और टारो फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं।

भारत से दोस्ती की चाह रखने वाले पाकिस्तान को रास नहीं आई पीएम मोदी की वापसी!

द रीव टाइम्स ब्यूरो

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भले ही पीएम मोदी को लोकसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत की बधाई दी हो लेकिन वहां की मीडिया की मानसिकता अब भी बदलती दिखाई नहीं दे रही है। पाकिस्तान के नामी अखबार द डॉन ने अपने संपादकीय में इस जीत पर चिंता जताई है। इसके मुताबिक इन परिणामों ने चुनावी पंडितों की उस भविष्यवाणियों को दरकिनार कर दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था पीएम मोदी के वोट बैंक पर भारी पड़ेगी। लेकिन अब रिजल्ट सभी के सामने हैं और अति राष्ट्रवादी पार्टी भाजपा लोकसभा चुनाव में मिली एक तरफा जीत के बाद एक बार फिर से पांच वर्षों के लिए भारत में सरकार बनाने जा रही है।

अखबार ने लोकसभा चुनाव के इन परिणामों को आश्चर्यजनक बताया है। संपादकीय के मुताबिक इससे यह बात साफ हो गई है कि चुनाव में जीत पाने या मतदाताओं को लुभाने के लिए धार्मिक घृणा और सांप्रदायिक राजनीति को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है।

निगल गया कोकीन का एक-दो नहीं कुल 246 पैकेट, विमान में ही मौत

द रीव टाइम्स ब्यूरो

कोलंबिया से जापान जा रहे विमान में शुक्रवार को एक जापानी शख्स की मौत हो गई। मौत का कारण हैरान कर देने वाला है क्योंकि मृतक के ऑटोप्सी रिपोर्ट में बताया गया है कि उसके पेट में एक-दो नहीं बल्कि कुल 246 पैकेट कोकीन के थे।

एयरोमेक्सिको विमान को उत्तरी मेक्सिको के हर्मोसिल्लो में आधे रास्ते में ही इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी क्योंकि एक यात्री को अचानक दौरे पड़ने लगे। लैंडिंग के बाद वहां डॉक्टरों की टीम आयी और उन्होंने उसे मृत करार दिया। यात्री की पहचान जापानी नागरिक यूदो एन के तौर पर हुई।

कोलंबिया से जापान जा रहे विमान में एक जापानी शख्स की मौत हो गई। मौत का कारण हैरान कर देने वाला है क्योंकि मृतक के ऑटोप्सी रिपोर्ट में बताया गया है कि उसके पेट में एक-दो नहीं बलकि कुल 246 पैकेट कोकीन के थे।

नासा की इस तकनीक से भविष्य में हजारों छोटे मानवरहित एयरक्राफ्ट एक ही समय में उड़ाए जा सकेंगे

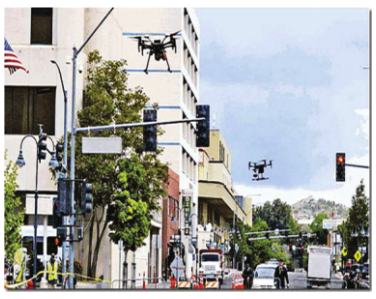

द रीव टाइम्स ब्यूरो

नासा ने शहरों में ड्रोन के लिए नेशनल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के अपने चार साल के प्रयासों का अंतिम चरण शुरू किया है। इसके तहत नासा पहली बार शहरों में ड्रोन का परीक्षण कर रहा है। शहरों की बड़ी बिल्डिंगों और व्यस्त सड़कों में ड्रोन चलाने के लिए एक कुशल और प्रभावी तंत्र की जरूरत है। साथ ही यह भविष्य में नए व्यवसाय का भी निर्माण करेगा।

सिमुलेशन टेस्टिंग के दौरान नासा ने इस सप्ताह अमेरिका के नेवादा राज्य के एक शहर रेनो के ऊपर एक साथ एक ही समय में कई ड्रोन उड़ाए। नासा की इस उभरती हुई तकनीक के इस्तेमाल से भविष्य में हजारों छोटे मानवरहित एयरक्राफ्ट एक ही समय में उड़ाए जा सकेंगे। जिनके माध्यम से खाद्य सामाग्री, दवाओं आदि की डिलीवरी आसानी से की जा सकेगी। कैलिफोर्निया में नासा के रिसर्च सेंटर में रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी विभाग के निदेशक डेविड कोर्सेमर ने बताया कि एक साथ कई ड्रोन को एक समय पर उड़ाना इस मिशन की सबसे बड़ी चुनौती थी। नासा ने इस तरह के परीक्षण दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में भी किए हैं।

नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिकीविद मुरे गेल-मैन का निधन

द रीव टाइम्स ब्यूरो

सब-एटॉमिक (एटम से भी छोटे) कणों की खोज करने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिकीविद मुरे गेल-मैन का निधन हो गया। 89 वर्षीय गेल-मैन ने न्यू मैक्सिको के सांता फे स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। सांता फे इंस्टीट्यूट और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूटी ऑफ टेक्नोलॉजी ने उनके निधन की पुष्टि की है। मृत्यु के कारण की जानकारी नहीं दी गयी है। गेल-मैन ने सब-एटॉमिक कणों को आठ के समूह में बांटकर भौतिकी की दिशा बदल दी थी।

नेपाल में तीन बम धमाके 4 की मौत, 9 घायल

द रीव टाइम्स ब्यूरो

नेपाल में अलग-अलग तीन जगहों पर हुए बम धमाके में 4 व्यक्तियों की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। नेपाल के स्थानीय मीडिया के मुताबिक ये बम धमाके सुखेधरा, घट्टेकुलो और नगधुंगा इलाके में हुए। बम धमाके के बाद 9 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है।

धमाकों के बाद से ही पुलिस ने इलाके की घेरा बंदी बढ़ा दी थी और लोगों की आवाजाही रोक दी थी। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है जहां इलाज जारी है।

चीन ने बनाई 600 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाली मैग्लेव ट्रेन, जानिये उसकी खासियत

द रीव टाइम्स ब्यूरो

चीन ने 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली मैग्नेटिक लेविटेशन (मैग्लेव) ट्रेन का प्रोटोटाइप लांच किया है। चुंबकीय क्षमता से चलने वाली इस ट्रेन का डिजाइन सरकारी कंपनी सीआरआरसी क्विंगदाओ सिफांग ने तैयार किया है। कंपनी ने गुरुवार को शानदोंग प्रांत के क्विंगदाओ शहर में इस ट्रेन का पहला महृडल लांच किया। चीन की अगले दो साल के भीतर इस ट्रेन के परीक्षण शुरू करने की योजना है।

चीन के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 2016 में 13वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था। हाई स्पीड मैग्लेव ट्रेन को हवाई यात्रा के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। चीन में अभी सबसे तेज ट्रेन की रफ्तार 350 किलोमीटर प्रति घंटा है।

पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल पर क्या कह रही है चीन की मीडिया, जरा आप भी जान लें

द रीव टाइम्स ब्यूरो

लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को मिली प्रचंड जीत और उनके दोबारा पीएम बनने के बीच अब बस कुछ ही फासला है। इस बीच भारत के पड़ोसी देशों की सरकार और वहां की मीडिया इसको अपने ही तरीके से ले रही है। पाकिस्तान के बाद अब चीन की सरकारी मीडिया ने भी पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल को लेकर कयास लगाए हैं।

चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के एक लेख में कहा गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी के सामने दूसरे कार्यकाल उनके समक्ष सबसे बड़ी चुनौती अर्थव्यवस्था को सही करने की है। लेख में यहां तक कहा गया है कि पीएम मोदी के लिए कई बड़ी समस्याएं उनका इंतजार कर रही हैं। लिहाजा उनके लिए यह दूसरा कार्यकाल आसान नहीं रहने वाला है। इसमें कहा गया है कि बीते दो माह से चल रहे चुनावी माहौल के बीच भारत की अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है। इसके अलावा वहां पर बेरोजगारी का मुद्दा भी अपने चरम पर है।

इमरान खान ने नरेंद्र मोदी को दी बधाई साथ काम करने की इच्छा जताई

द रीव टाइम्स ब्यूरो

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत में बड़ी चुनावी जीत पर नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। आशा जताई है कि उनके साथ क्षेत्रीय शांति, स्थिरता, तरक्की और संपन्नता के लिए कार्य करने का मौका मिलेगा।

इमरान खान ने ट्वीट कर कहा- भाजपा की चुनावी जीत के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देता हूं। उनके साथ दक्षिण एशिया की शांति और तरक्की के लिए काम करना चाहता हूं। उल्लेखनीय है कि भारत के चुनाव परिणाम का पाकिस्तान में बड़ी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। पाकिस्तान सरकार ने कई मसलों पर चुनाव परिणाम आने के बाद भारत से वार्ता शुरू करने की बात कही थी। इनमें दोनों देशों के बीच शांति वार्ता, वायु सीमा खोले जाने, करतारपुर कॉरीडोर निर्माण के मसले शामिल हैं। इमरान ने आशा जताई थी कि चुनाव में अगर भाजपा को जीत हासिल होती है तो कश्मीर मसले पर भारत के साथ वार्ता करके उसे सुलझाने की स्थितियां बनेंगी।

स्विस बैंकों में काला धन रखने वालों पर कसा शिकंजा, 11 भारतीयों को नोटिस

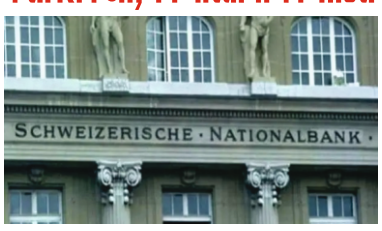

द रीव टाइम्स ब्यूरो

मोदी सरकार के एक बार फिर सत्ता में वापसी के साथ ही स्विट्जरलैंड ने भी अपने यहां बैंकों में पैसा रखने वाले भारतीयों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। स्विट्जरलैंड ने ऐसे भारतीयों के संबंध में सूचनाएं साझा करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। ब्लैक मनी जमा करने के लिए सबसे सुरक्षित जगह माने जाने वाले स्विटजरलैंड ने पिछले सप्ताह ही करीब एक दर्जन भारतीयों को इस संबंध में नोटिस थमाया है।

स्विट्जरलैंड के अधिकारियों ने मार्च से अब तक स्विस बैंकों के भारतीय ग्राहकों को कम से कम 25 नोटिस जारी कर भारत सरकार के साथ उनकी जानकारी साझा करने के खिलाफ अपील का एक आखिरी मौका दिया गया है।

पैदा होने वाले 11 हजार बच्चों में से एक इस बीमारी से पीड़ित 14 करोड़ की खुराक करेगी ठीक

द रीव टाइम्स ब्यूरो

अमेरिका के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने गंभीर किस्म की बीमारी स्पाइनल मस्क्युलर अट्रॉफी (एसएमए) के इलाज के लिए जीन-थेरेपी को मंजूरी दे दी है। जोलेगेंस्मा नामक इस नई थेरेपी के जरिये एक ही बार में इस बीमारी का इलाज हो जाएगा जिसकी कीमत 21 लाख डॉलर (करीब 14 करोड़ रुपये) है। एक खुराक के लिहाज से इसे अब तक का सबसे महंगा इलाज बताया जा रहा है। एसएमए के इलाज के लिए पहले भी कई ड्रग्स विकसित की गई थी, लेकिन उनकी एक खुराक की कीमत दस डॉलर से ऊपर नहीं थी।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

करंट अफेयर्स

- केरल का वह वार्षिकोत्सव जिसका हाल ही में शुभारंभ हुआ है – त्रिशूर पूरम
- वर्ष 2019 को इस नाम से मनाने के लिए भारतीय थल सेना ने हाल ही में घोषणा की है – ईयर ऑफ नेक्स्ट ऑफ किन
- प्रसिद्ध बिरहा गायक एवं बिरहा सम्राट जिनका हाल ही में निधन हो गया है – हीरालाल यादव
- वह टीम जिसने हाल ही में आईपीएल 2019 का खिताब जीता है –मुंबई इंडियन्स
- वह खिलाड़ी जिसने आईपीएल 2019 में पर्पल कैप का खिताब जीता है –इमरान ताहिर
- वह चक्रवाती तूफान जिससे प्रभावित हुए किसानों, मछुआरों, महिला समूहों और अन्य लोगों के लिए 1600 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की है –फेनी
- 7वीं चाइना पैरा ऐथलेटिक्स वर्ल्ड ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप्स में मेरठ की फातिमा खातून ने डिस्कस थ्रो में पदक जीता – कांस्य पदक
- पाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ इतने करोड़ रुपये के राहत पैकेज को लेकर समझौता हो गया है – 42,000 करोड़
- भारत का पड़ोसी देश जिसमें सांप्रदायिक झड़प के बाद पुलिस ने कर्फ्यू लगा दिया है और फेसबुक व वॉट्सऐप अस्थाई तौर पर ब्लॉक कर दिया है– श्रीलंका
- वह देश जो जलवायु आपातकाल की घोषणा करने वाला विश्व का दूसरा देश बना गया है– आयरलैंड
- केंद्र सरकार ने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (लिट्टे) के खिलाफ प्रतिबंध को और जितने साल के लिए तत्काल प्रभाव से बढ़ा दिया है– पांच साल
- वह देश जिसने पाकिस्तान की एक और चीन की कई कंपनी समेत 12 विदेशी कंपनियों को अपनी 'एन्टिटी' सूची में शामिल किया है– अमेरिका
- वित्तीय संकट से जूझ रही जिस विमानन कंपनी के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) अमित अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया है– जेट एयरवेज
- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने 13 मई 2019 को ओडिशा के चांदीपुर में जिस ड्रोन का सफल परीक्षण किया– अभ्यास
- वह सरकारी ईकाई जिसने हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों के स्टार्टअप्स को फंडिंग देने के लिए 700 करोड़ रुपये के बजट की घोषणा की गई है – नाबार्ड
- वह महिला खिलाड़ी जिसे हाल ही में CEAT महिला क्रिकेटर ऑफ द इयर के खिताब से सम्मानित किया गया है –स्मृति मंधना
- डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द्वारा हाल ही में ह्यूमन टिश्यू की मैपिंग करने के लिए जिस नाम से पहल आरंभ की गई है– मानव
- इन्हें हाल ही में मेक्कैन इंस्टिट्यूट अवार्ड–2019 से सम्मानित किया गया है –छाया शर्मा
- विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ियों पर समर्पित पत्रिका आरंभ करने वाले प्रकाशक का नाम है– यश लाहोटी
- अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने 14 मई 2019 को जिस को आईसीसी मैच रेफरी के अंतरराष्ट्रीय पैनल में शामिल किया है– जीएस लक्ष्मी
- राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने देश भर में भूजल संसाधनों पर दबाव कम करने और शोधित अपशिष्ट जल का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए 18 राज्यों और जितने केन्द्र शासित प्रदेशों को कार्य योजना जमा करने का निर्देश दीया है– दो
- हाल ही में जिस देश ने आधिकारिक रूप से परमाणु समझौते के अंतर्गत संयुक्त समग्र कार्य योजना (जेसीपीओए) के तहत किए गए वादों से खुद को अलग कर लिया है– ईरान
- जिस राज्य के पुलिस ने सार्वजनिक स्थलों पर जन्मदिन मनाने के दौरान चेहरे पर केक लगाने, टेप चिपकाने, फोम या अन्य केमिकल फेंकने पर प्रतिबंध लगाने को लेकर निषेधाज्ञा जारी की है– गुजरात पुलिस
- जिस देश के इगोर स्टिमैक को भारतीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है– क्रोएशिया
- वह देश जिसने मोबाइल फोन पर 20 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने को लेकर विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में भारत की शिकायत की है– जापान
- निजी क्षेत्र के जिस बैंक ने 14 मई 2019 को आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर आर. गांधी को अतिरिक्त निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की– येस बैंक
- जिस देश में स्थित एक लैबोरेटरी के सेंसर्स के अनुसार, वायुमंडल में कार्बन डायऑक्साइड का स्तर 415.26 पीपीएम (पार्ट्स पर मिलियन) पहुंच गया और मानव इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है– अमेरिका
- नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत जिस राज्य में गंगा के जलग्रहण क्षेत्र में स्थानीय समुदाय और अन्य हितधारकों के सहयोग से 10,000 रूद्राक्ष के पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है– उत्तराखंड
- वह देश जिसने भारतीय विमानों के अपने एयरस्पेस में घुसने पर लगा प्रतिबंध 30 मई तक बढ़ा दिया है– पाकिस्तान
- जिस देश के साथ व्यापार युद्ध के लगातार बढ़ते जाने की खबरों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक एक्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए– चीन
- भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली और जिस विकेटकीपर बल्लेबाज को देश की प्रमुख वेलनेस फर्म हिमालया ड्रग कंपनी का नया आधिकारिक ब्रांड दूत बनाया गया है– ऋषभ पंत
- अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने जिस देश के कप्तान इयोन मोर्गन को एक वनडे के लिए सस्पेंड कर दिया है– इंग्लैंड
- हाल ही में जीएसआई द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के जिस राज्य में भारत के कुल ग्रेफाईट का 35 प्रतिशत भाग मौजूद है– अरुणाचल प्रदेश
- अमेरिका के जिस संस्थान द्वारा पहली बार पूरी तरह रीसायकल होने वाली प्लास्टिक की खोज की है– लॉरेंस बर्कले नेशनल लेबोरेटरी
- सुप्रीम कोर्ट से हाल ही में रिटायर होने वाले जस्टिस जिन्हें फिजी ने अपनी सुप्रीम कोर्ट के गैर–नागरिक पैनल में जज के तौर पर नियुक्त किया– जस्टिस मदन बी. लोकुर
- आरबीआई ने ई–पेमेंट सिस्टम के लिए जिस नाम से पहल आरंभ की है– विजन–2021
- केन्द्रीय पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में देश में मौजूद जिस जंगली जानवर के डीएनए का डेटाबेस तैयार करने का निर्णय लिया है– गैंडा
- विशेषज्ञों के अनुसार, अमेरिका और जिस देश के बीच चल रहे ट्रेड वॉर से भारत के लिए दोनों देशों में निर्यात मौके बढ़ाने में सहायता मिलेगी– चीन
- इटली के क्लब लाजियो ने अटलांटा को 2–0 से हराकर जितनी बार कोपा इटालिया फुटबाल खिताब अपने नाम कर लिया है– सातवीं बार
- हाल ही में जिस देश ने भारतीय कंपनियों से देश में और ज्यादा निवेश करने का आग्रह किया है – नेपाल
- हाल ही में अमेरिका की संसद में जिस देश के सैन्य वैज्ञानिकों पर रोक संबंधी विधेयक पेश किया गया– चीन
- वह देश जिसकी संसद ने 17 मई 2019 को समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाले बिल को मंजूरी दे दी है– ताइवान
- मुंबई की आरोही पंडित जिस महासागर के ऊपर लाइट स्पोर्ट एयरक्राफ्ट में अकेली उड़ान भरने वाली दुनिया की पहली पायलट बन गई हैं– अटलांटिक महासागर
- रेल अधिकारियों ने 16 मई 2019 को बताया कि भारत की सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस ने बिना कोई ट्रिप (फेरी) छोड़े अपनी जितने लाख किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली है – 01 लाख किलोमीटर
- वह नेता जिसने लोकसभा चुनावों में अमेठी सीट से राहुल गांधी को हराकर जीत दर्ज की है –स्मृति ईरानी
- आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्होंने हाल ही में सीएम पद से इस्तीफा दे दिया – चंद्रबाबू नायडू
- लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की कुल 80 सीटों में से इतनी सीटों पर जीत दर्ज की है – 62
- दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले एचआईवी संक्रमित व्यक्ति – गोपाल श्रेष्ठ
- भारतीय वायुसेना की पहली फाइटर पायलट जिन्होंने हाल ही में अपनी ट्रेनिंग का पहला चरण पूरा किया है –भावना कांत
- वह भारतीय कम्पनी जिसने इतिहास रचते हुए जिसने विश्व की तीसरी सबसे बड़ी कम्पनी होने का कीर्तिमान स्थापित किया है –टीसीएस
- भारतीय राजनयिक जिसे हाल ही में जापान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन' के लिए नामित किया गया है –श्याम सरन
- वह भारतीय शांति सैनिक जिन्हें हाल ही में मरणोपरांत डैग हैमरसोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया– जितेन्द्र कुमार
- भारतीय वायुसेना ने सुखोई–30 MKI लड़ाकू विमान के जरिए 22 मई 2019 को जिस मिसाइल के एयर वर्जन का सफल परीक्षण किया– ब्रह्मोस मिसाइल
- जिस देश में ब्रेग्जिट को लेकर संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्र्स की नेता एंड्रिया लेडसम ने इस्तीफा दे दिया है– ब्रिटेन
- हाल ही में दक्षिण कोरिया की खिलाफ तीन मैचों की श्रृंखला के दूसरे मैच में मैदान पर उतरते ही जिस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने अपने 150 अंतरराष्ट्रीय मैच पूरे कर लिये है– सुनीता लाकरा
- श्रीलंका में ईस्टर रविवार पर हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के बाद देश में लागू किये गये आपातकाल को राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने हाल ही में और जितने महीने के लिये बढ़ा दिया– एक महीना
- भारत के युवा निशानेबाज सौरभ चौधरी ने जर्मनी के म्यूनिख में चल रहे आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जो पदक जीता– स्वर्ण पदक
- हरियाणा सरकार ने 01 जनवरी 2019 से कर्मचारियों–पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता जितना प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा की है–03 प्रतिशत
- हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पद पर जिसने शपथ ली– सिरिल रामफोसा
- क्रिकेट विश्व कप के अपने दूसरे अभ्यास मैच में भारत ने जिस देश को 95 रनों से हरा दिया है– बांग्लादेश
- नवीन पटनायक ने लगातार जितनी बार ओडिशा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली– पांचवीं बार
- जिस राज्य के ओरछा को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल किया गया हैं– मध्य प्रदेश
- सिक्किम के जिस मुख्यमंत्री ने 27 मई 2019 को शपथ लेने के बाद घोषणा किया कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों को हर हफ्ते 2 दिन छुट्टी मिलेगी– प्रेम सिंह तमांग
- वह राज्य सरकार जिसने गौरी लंकेश हत्याकांड के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) को सफल छानबीन व सटीक जांच के लिए 25 लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की है– कर्नाटक सरकार

हिमाचल सामान्य ज्ञान

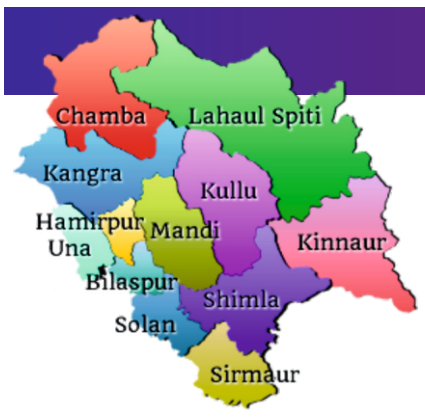

- हिमाचल में लोकसभा चुनावों की सीटों के लिए कितने प्रत्याशी चुनावा मैदान में थे –45
- हिमाचल में मतदाताओं की कुल संख्या– 53 लाख 30 हजार 154 पुरूष– 27 लाख 24 हजार 111 महिलाएं–26 लाख 5 हजार 996 तृतीय लिंग– 47
- प्रदेश में कहां सबसे अधिक मतदात है– कांगड़ा–14 लाख 27 हजार
- सबसे कम– शिमला में 12 लाख 59 हजार 85 मतदाता है
- इस बार कितने नए मतदाता पंजीकृत हुए–1 लाख 52 हजार 390 पुरूष– 82 हजार 500 महिलाएं–69 हजार 880
- कितने तृतीय श्रेणी के नए मतदात जुड़े–10
- प्रदेश में कितने शतायु मतदाता हैं– 999 पुरूष–337 महिलाएं– 662
- 30 साल से कम आयु के कितने मतदाता हैं– 12.4 लाख,
- हिमाचल से लोकसभा चुनावों में एकमात्र महिला उम्मीद्वार थीं– कांगड़ा से निशा कटोच, अखिल भारतीय हिंदुस्तान पार्टी
- सबसे अधिक प्रत्याशी किस संसदीय सीट से चुनाव मैदान में थे–मंडी सीट से 17
- इन चुनावों मे कितने केंद्र बनाए गए थे – 77,23 सामान्य और 7 सहायक केंद्र
- सहायक केंद्र कहां कहां पर स्थापित किए गए थे–1. वृद्धा आश्रम दाड़ी (कांगड़ा) 2.बड़ा भंगाल बैजनाथ (कांगड़ा) 3. लाहुल स्पीति में की गोंपा 4. मंडी के माया मंदिर के पास 5. बल्ह में भंरोटू वृद्धाआश्रम 6. सोलन में जोनल अस्पताल
- चुनावों के दौरान चर्चा में रहे स्वीप कार्यक्रम की फुल फार्म क्या है– सिस्टेमेटिक वोटर ऐजूकेशन एंड इलेक्टोरोल पार्टीसिपेशन
- सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा है और उसकी ऊंचाई कितनी है– लाहौल स्पीति स्थित टाशीगंग, इसकी ऊंचाई 15 हजार 256 फीट है और यहां पर कुल 49 मतदाता हैं। इनमें 29 पुरूष और 20 महिलाएं हैं।
- शिमला से भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किस ने किया था। राजकुमारी अमृत कौर
- शिमला मे प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला की स्थापना कब की गई थी? – 1970 में
- अंबुजा सीमेंट फैक्टरी हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर है ? दाड़लाघाट सोलन
- इरविन गांधी समझौते पर हस्ताक्षर करने गाँधी जी किस वर्ष शिमला आए थे? – 1931 में
- प्रदेश के प्रथम भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी का क्या नाम था।– ठाकुर सेन नेगी
- 1987 में हिमाचल सरकार द्वारा स्थापित परशुराम पुरस्कार किस से संबंधित है? – खेल – कूद से
- प्रसिद्ध 'बालासुंदरी मंदिर' किस जिले में स्थित है?– सिरमौर में
- प्रसिद्ध रेणुका मेला हिमाचल के किस जिले में आयोजित किया जाता है?– सिरमौर में
- 1863 में विशप कॉटन स्कूल की स्थापना किस ने की थी ?– जॉन लारेंस ने
- हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक आबादी गांव वाला जिला कौन सा है?– कांगड़ा
- प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में हिमाचल प्रदेश के किस भाग को त्रिगर्त कह कर पुकारा गया है ? कांगड़ा
- कौन सा जिला मशरूम की खेती के लिए प्रसिद्ध है ?–सोलन
- हिमाचल प्रदेश में किस घाटी को देवताओं की घाटी कहा जाता है ?– कुल्लू घाटी
- गुरु घंटाल क्या है?– प्रसिद्ध भिक्षु आश्रम
- 1909 में मंडी के राजा के विरुद्ध किसने आंदोलन किया ? –शोभा राम
- पहाड़ी भाषा की लिपि क्या है ?–टांकरी लिपि
- 1948 तक हिमाचल प्रदेश मे कितने जिले थे ?–4
- जिले के रूप मे शिमला का गठन कब हुआ ?–1972
- हिमाचल प्रदेश मे सबसे पहले कौन सा जिला बनाया गया था ?–चम्बा

मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना

हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए एक नई योजना की शुरूआत की है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना रखा गया है। यह योजना खेतों की सुरक्षा के लिए चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत खेतों की संरक्षण के लिए सौर फेंसिंग लगवाई जाएगी। इसके लिए सरकार 85 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान करती है।

यह सब्सिडी 3 या उससे अधिक समूह के किसानों को मुहैया करवाई जाती है। आए दिन खेतों को जानवर बर्बाद कर देते हैं जिससे कि फसल का बहुत नुकसान हो जाता है। सोलर फेंसिंग की मदद से किसान अपने खेतों और उसमें लगी हुई फसल को बचा पाएंगे। इस योजना के अंतर्गत खेत के चारों तरफ सोलर फेंसिंग लगाई जाएगी।

इस योजना के अंतर्गत किसानों को कृषि विभाग में जाकर सोलर बाढ़ लगाने के लिए 15 प्रतिशत हिस्सा ही जमा करना होगा। इसका कारण यह है कि 85 प्रतिशत खर्चा सरकार द्वारा सब्सिडी के तौर पर दिया जाएगा। पहले किसानों को 20 प्रतिशत हिस्सा देना पड़ता था, लेकिन अभी राशि और भी घटकर 15 प्रतिशत कर दी गई है क्योंकि सरकार ने सब्सिडी को 80 से बढ़ाकर 85 प्रतिशत कर दिया है।

यह खेत संरक्षण योजना सब्सिडी सरकार तब मुहैया करवाएगी जब 3 या उससे अधिक किसान समूह में आकर इस योजना के लिए आवेदन करेंगे। इस योजना को अच्छी तरह से लागू करने के लिए इस साल सरकार ने 35 करोड़ रुपए का बजट पास किया है। इस योजना से जुड़ी अन्य जानकारी जैसे कि इस योजना के लाभ, जरूरी कागजात, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के बारे में हम द रीव टाइम्स के इस अंक में जानकारी दे रहे हैं।

योजना का नाम	मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना
पात्र	हिमाचल के किसान
बजट	33 करोड़ रुपए का
पात्रता	3 या उससे अधिक किसानों का समूह बनाकर आवेदन
सब्सिडी	85 प्रतिशत

इस योजना के तहत सरकार ने अब तक 32 कंपनियों को सोलर फेंसिंग लगाने के लिए चुना है। जैसे ही किसान आवेदन करते हैं यह कंपनियां आकर उनके खेतों में फेंसिंग लगा जाती है। इस योजना का मकसद जानवरों से होने वाली फसल के नुकसान को कम करना है। इस योजना के तहत सोलर फेंसिंग 1500 मीटर की रनिंग तार लगाई जाएगी, जो खेतों के चारों तरफ होगी। इसके लिए करंट सोलर प्लांट द्वारा जनरेट किया जाएगा। इसके लिए सोलर प्लांट भी विस्थापित किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत अब किसान चुनी गई कंपनियों में से अपनी पसंद की कंपनी को आवेदन करके सेंसिंग लगवा सकता है। अगर किसान को किसी कंपनी का काम पसंद नहीं आता वह दूसरी कंपनी की तरफ जा सकता है।

खेत संरक्षण योजना सोलर के लिए सब्सिडी – 85 प्रतिशत

जो किसान अकेले आवेदन करवाना चाहते हैं उन्हें 80 प्रतिशत तक का सब्सिडी अनुदान दिया जाता है। इस योजना के लाभ उठाने के लिए किसानों को जिला कृषि खंड में जाकर आवेदन करना होगा। जब योजना शुरू की गई थी तब किसानों को 60 रू 40 के अनुपात में अनुदान मिलता था। इसकी वजह से किसान को फेंसिंग करवाने में काफी खर्च करना पड़ता था। इस वजह से यह योजना किसानों में ज्यादा लोकप्रिय नहीं हुई। लेकिन अब अनुदान राशि 80 से 85 प्रतिशत कर देने के कारण किसानों में इस योजना के प्रति दिलचस्पी दिखाई दे रही है।

तीन तरह की फेंसिंग

इस योजना के अंतर्गत तीन प्रकार की जाती है। किसान अपने मनपसंद के हिसाब से इन तीनों में से किसी भी प्रकार की फेंसिंग को चुन सकता है। यह तीन प्रकार की फसल किस प्रकार से है-

- पांच फीट की ऊंची फेंसिंग
- सात फीट की ऊंची फेंसिंग
- नौ फीट की ऊंची फेंसिंग
- **सोलर फेंसिंग योजना के लाभ**
- इस योजना से जानवर द्वारा फसल का किया जाने वाला नुकसान कम हो पाएगा।
- इसे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
- प्रदेश में फसल की पैदावार में वृद्धि होगी।

हिमाचल प्रदेश खेत संरक्षण योजना

खेत संरक्षण योजना मुख्यमंत्री ऑनलाइन आवेदन फॉर्म

आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको बागवानी विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इस बारे में अधिक जानकरी बागवानी अधिकारी से प्राप्त की जा सकती हैं।

गुड़िया हेल्पलाइन नंबर 1515

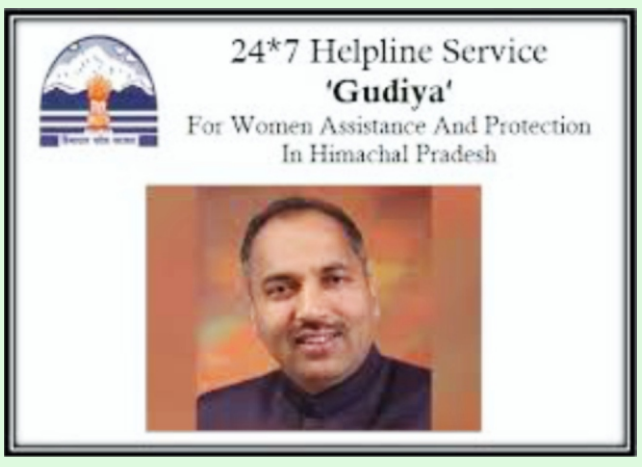

हिमाचल प्रदेश पूरे भारतवर्ष में एक शांत राज्य के तौर पर जाना जाता है। लेकिन 2017 में हिमाचल प्रदेश के कोटखाई में एक बहुत ही बुरी घटना घटी थी। इस घटना में कोटखाई की एक छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के बाद बेहद निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले को लेकर पूरे प्रदेश की जनता सड़कों पर आ गई थी। प्रदेश में महिला सुरक्षा पर सवालिया निशान लग गया था।

इस घटना के तुरंत बाद राज्य में चुनाव हुए जिसमें बीजेपी को भारी मतों से विजय मिली। नई सरकार ने हिमाचल में महिलाओं की सुरक्षा के लिए "गुड़िया हेल्पलाइन नंबर 1515" की शुरूआत की। इसके साथ ही राज्य में क्राइम को रोकने के लिए होशियार सिंह हेल्पलाइन 1090 भी शुरू की गई। इस समय पूरे हिमाचल प्रदेश में लगभग 7 से 8 हेल्पलाइन नंबर चल रहे हैं। यह हेल्पलाइन नंबर विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जारी किए गए हैं। राज्य में बीजेपी की सरकार आने के बाद, बहुत सी हेल्पलाइन को शुरू किया गया है। इन सभी हेल्पलाइनो की सूची हम आपको नीचे देने जा रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए मुख्य रूप से गुड़िया हेल्पलाइन नंबर 1515 को जारी किया गया है। इसके अलावा महिला हेल्पलाइन 1091 भी चल रही है।

गुड़िया हेल्पलाइन को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य स्कूल एवं कॉलेज में पढ़ रही छात्रों को सुरक्षा प्रदान करना है। अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को परेशान अथवा कोई भी कष्ट पहुंचाने की कोशिश करता है, तो वह इस गुड़िया हेल्पलाइन 1515 कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती हैं। उसके द्वारा दर्ज करवाई की शिकायत उनके नजदीकी थाना को भेजी जाएगी जिसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

हिमाचल और पहले से ही एक शांतिपूर्ण रहा है। लेकिन पिछले कुछ राज्य में हुई बहुत ही और बुरी घटनाओं से, राज्य का माहौल खराब हुआ है। इसी को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार को यह कदम उठाने पड़े हैं। इस सूची को नीचे विस्तार से बताया गया है। इस सूची की मदद से, आप कभी भी इन हेल्पलाइन नंबरों को देखकर डायल कर सकती हैं।

गुड़िया हेल्पलाइन : 1515

होशियार हेल्पलाइन : 1090

हिमाचल प्रदेश मुख्य हेल्पलाइन नंबर सूची

गुड़िया हेल्पलाइन नंबर	1515
महिला हेल्पलाइन नंबर	1091
होशियार सिंह हेल्पलाइन	1090
चाइल्ड हेल्पलाइन	1098
मेडिकल चिकित्सा हेल्पलाइन	102 एवं 108
पुलिस हेल्पलाइन	100
आपदा प्रबंधान हेल्पलाइन - टोल फ्री नंबर	1077
फायर ब्रिगेड नंबर	101
एंटी करप्शन विभाग - भ्रष्टाचार के खिलाफ रिपोर्ट हेतु हेल्पलाइन	0177-2629813
साइबर सेल हिमाचल प्रदेश हेल्पलाइन	0177-2621714

लघु उद्योग

59 मिनट में 1 करोड़ का ऋण

लघु एवं मझोले उद्यम को सरकार की ओर से तोहफा

अब मध्यम, छोटे और लघु उद्यमों के लिए 59 मिनट में 1 करोड़ रुपये तक के लोन के आड़े आने वाली सभी बाधाएं समाप्त हो गई हैं। इसके अलावा पात्र संगठन, जो माल और सेवा कर के तहत पंजीकृत हैं, को अब 1 करोड़ रुपये की सीमा में अतिरिक्त कर्ज पर ब्याज दर में 2% ब्याज सहायता दी जाएगी।

एमएसएमई क्या है?

एमएसएमई का तात्पर्य है लघु, छोटे और मध्यम उद्यम। निवेश के मामले में ये उद्यम छोटे माने जाते हैं। ये आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये देश में बड़े समय के नियोक्ता हैं। दूसरी बात, प्रतिवर्ष औद्योगिक उत्पादन का लगभग 40% इन उद्यमों द्वारा निर्मित किया जाता है।

- एक सूक्ष्म उद्यम के लिए: टर्नओवर (कुल बिक्री) प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपये से कम या इसके बराबर हो
- एक छोटे उद्यम के लिए: टर्नओवर (कुल बिक्री) प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपये से अधिक और 75 करोड़ रुपये से कम हो
- एक मध्यम उद्यम के लिए: टर्नओवर (कुल बिक्री) प्रतिवर्ष 75 करोड़ रुपये से अधिक और 250 करोड़ रुपये से कम हो

प्रक्रिया क्या है?

सिडबी (भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक) ने https://www-psbloansin59minutes-com/home पर एक पोर्टल स्थापित किया है। सभी योग्य उद्यमों को वहां पंजीकरण करना है और ऋण के लिए आवेदन करना है। सर्वोत्तम ब्याज दरें संभव बनाने के लिए उनके आवेदन 2–3 बैंकों तक प्रसारित किए जाएंगे। एक अनुमोदन प्राप्त करके इस प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। लगभग सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इसमें भाग ले रहे हैं।

इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?

इस कार्यक्रम में सरकार का मुख्य उद्देश्य भारत के एमएसएमई (लघु एवं मझोले उद्यम) क्षेत्र को मजबूत करना है। इसका उद्देश्य व्यवसायियों को ऋण प्राप्त करने में उनके लंबे समय तक के इंतजार को कम करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान में कहा है कि, 'छोटे व्यवसायी सस्ती ब्याज दर पर, अक्सर बैंक शाखाओं के चक्कर लगाए बिना आसानी से एक करोड़ रुपये का ऋण मात्र 59 मिनट में प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए यह पहली आवश्यकता होती है।'' वित्त मंत्री पैनल भी स्थापित किया गया है जो छोटे व्यवसायों के साथ डील करके उनके मुद्दों को हल करेगा।

इसके अलावा, मोदी के प्रशासन की नई घोषणा से यह भी पता चलता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को अब एमएसएमई से अपने इनपुट, पिछले 20 प्रतिशत की तुलना, का 25 प्रतिशत खरीदना होगा। 25% में से, इसका 3% महिला नेतृत्व वाली एमएसएमई या महिला उद्यमियों द्वारा प्राप्त किया जाएगा।

एमएसएमई के लिए अन्य 'दीवाली उपहार'

एमएसएमई को बेहतर नकदी चक्र का लाभ मिलेगा क्योंकि अब सभी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां जिनके पास 500 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार है, अनिवार्य रूप से ट्रेड रिसीवबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम के पोर्टल पर पंजीकृत होंगी।

फार्मा एमएसएमई कंपनिया उनके लिए समूहों (क्लस्टर) का सृजन करेंगी। केंद्र सरकार इसकी लागत का 70% वहन करेगी। क्लस्टर कंपनियों को आसानी से ग्राहकों तक पहुंचने में मदद मिलेगी।

एमएसएमई (लघु एवं मझोले उद्यम) इंस्पेक्टर राज से मुक्त हो जाएंगे।

एमएसएमई (लघु एवं मझोले उद्यम) के लिए पर्यावरणीय मंजूरी प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। वायु और जल अधिनियम के तहत, अब उन्हें ''स्थापित करने की सहमति'' और ''पर्यावरणीय मंजूरी'' के लिए केवल एक अनुमोदन की आवश्यकता है।

कंपनी अधिनियम के तहत मामूली अपराधों में दंड को सरल बनाने के लिए एक अध्यादेश जारी किया गया है। यह छोटे व्यवसायों के मालिकों के अनावश्यक उत्पीड़न को रोक देगा।

सरकार ने छोटे व्यवसायों के लिए प्रौद्योगिकी के केंद्रों को बढ़ाने के लिए 6,000 करोड़ रुपये तक का निवेश करने का फैसला किया है।

अब, 8 श्रम कानूनों के नियमों के संबंध में सिर्फ एक वार्षिक रिटर्न दाखिल करना होगा।

रियायती वित्तपोषण योजना Concessional Financing Scheme (CFS)

द रीव टाइम्स ब्यूरो

विदेश की रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण आधारभूत संरचना से सम्बंधित परियोजनाओं के लिए बोली लगाने वाले भारतीय प्रतिष्ठानों को श्रय देने के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने रियायती वित्त योजना (Concessional Financing Scheme & CFS) के पहले विस्तार की मंजूरी दी है।

इस योजना का उद्देश्य विदेशों में रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण अवसरंचना परियोजनाओं के लिए बोली लगाने वाले भारतीय निकायों को आर्थिक समर्थन प्रदान करना है।

CFS कैसे कार्य करता है?

सर्वप्रथम आर्थिक कार्य मंत्रालय भारत के रणनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए विशेष परियोजनाओं का चयन करता है तथा उन्हें आर्थिक कार्य विभाग को भेज देता है।

आर्थिक कार्य विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं पर विचार करके यह निर्धारित करता है कि कौन-सी योजनाओं में इस योजना के तहत वित्त लगाया जा सकता है।

समिति के अनुमोदन के पश्चात् आर्थिक कार्य विभाग EXIM ठंदा को एक औपचारिक पत्र देता है जिसमें CFS के अन्दर परियोजना को वित्त देने सम्बन्धी अनुमोदन की सूचना होती है।

CFS योजना वर्तमान में भारतीय निर्यात-आयात बैंक (**EXIM Bank**) के माध्यम से संचालित होती है और यही बैंक रियायती वित्त मुहैया करने हेतु बाजार से वित्त उठाता है।

भारत सरकार (GoI) EXIM बैंक को काउंटर गारंटी देती है तथा साथ ही 2: ब्याज समानीकरण समर्थन (interest equalization support) भी प्रदान करती है।

इस योजना के अंतर्गत EXIM बैंक जो कर्ज देता है उसकी दर LIBOR (छह महीने का औसत) 100 इचे से अधिक नहीं होती है। कर्ज की वापसी के लिए विदेशी सरकार गारंटी देती है।

योजना का महत्त्व

CFS योजना के लागू होने के पहले भारतीय प्रतिष्ठान विदेश में बड़ी-बड़ी परियोजनाओं में बोली लेने में असमर्थ रहते थे क्योंकि उन्हें कठोर शर्तों पर इसके लिए धन की व्यवस्था की करनी पड़ती थी।

रियायती वित्तपोषण योजना (CFS) के आरम्भ से पूर्व भारतीय संस्थाएँ विदेशों में बड़ी परियोजनाओं के लिए बोली लगाने में सक्षम नहीं थीं क्योंकि वित्त पोषण की लागत अत्यधिक थी और जापान, यूरोप और अमेरिका जैसे अन्य देशों के बोलीदाता (bidders) बेहतर शर्तों पर क्रेडिट प्राप्त करने में सक्षम थे, अर्थात् कम ब्याज दरों पर और दीर्घावधि के लिए, जिसमें इन देशों के बोलीदाता लाभ की स्थिति में रहते थे।

भारतीय प्रतिष्ठानों को रणनीतिक हितों वाली विदेशी योजनाओं में काम मिल जाने का लाभ यह होगा कि भारत में नए रोजगारों का सृजन होगा, सामग्रियों तथा मशीनों की माँग बढ़ेगी और भारत के लिए विश्व में प्रचुर सद्भाव उत्पन्न होगा।

इस योजना से भारत में रोजगार का सृजन होगा और यहाँ मशीनों और निर्माण-सामग्रियों की माँग भी बढ़ेगी।

हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना

द रीव टाइम्स ब्यूरो : महिला और बाल विकास मंत्रालय, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनाथ बच्चों का कल्याण है। अनाथ बच्चा वह है जिसका माता पिता मृत, अज्ञात है, या उसे स्थायी रूप से त्याग दिया है, इस तरह के बच्चों की देखभाल और रखरखाव के लिए यह योजना हैं। इस योजना के तहत हिमाचल सरकार को मुफ्त आश्रय, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त भोजन और पेशेवर मार्गदर्शन और कई अन्य आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई हैं। राज्य में सभी अनाथ बच्चों की सहायता करने के लिए, बाल उधार योजना का हिस्सा बनने और योजना द्वारा प्रदान किए गए सभी लाभ प्राप्त करने के लिए रिश्तेदार मद्द करें। महिलाओं और बाल विकास कार्यालय में अधिक विवरण और आवेदन पत्र प्राप्त किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना के लाभ

अनाथ बच्चों को कई लाभ प्रदान करने के लिए बाल कल्याण योजना

इस योजना के तहत, हिमाचल सरकार ने अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा, आवास, खाना, व्यावसायिक मार्गदर्शन और कई अन्य आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई हैं।

मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना के लिए आवेदन करने की आवश्यक पात्रता और शर्तें

- हिमाचल प्रदेश के अनाथ लड़की या लड़कें

मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना के लिए आवेदन करने वाले आवश्यक दस्तावेज:

- पहचान प्रमाण
- आवेदन पत्र (कार्यालय में उपलब्ध)
- निवासी प्रमाण
- आधार कार्ड

मिशन रीव : आपकी समस्त जिम्मेवारियों का संवाहक

मिशन रीव का दूसरा संस्करण : दिल से सेवा-दिल से भुगतान

द रीव टाइम्स : हेम राज चौहान

मिशन रीव (रुरलाइजिंग इंडिया–एंपावरिंग विलेजिज) आमजन के सपनों को पूरा करने, उनकी जन्म से परधाम तक की समस्याओं को समाधान की राह पर लाने हेतु अपनी बेहतरीन और गुणात्मक सेवाओं के साथ हिमाचल के जनमानस के साथ द्वितीय संस्करण लेकर प्रस्तुत है । इन सेवाओं को 10 प्रभागों में विभाजित कर सरलीकरण किया गया है । इस प्रकार का यह प्रयास प्रदेश या देश ही नहीं पूरे विश्व में अनूठा है जिसके अंतर्गत बहुत कम कीमत पर आपकी हर समस्या को समाधान तक लाने के प्रति मिशन रीव क्रियाशील है । मिशन रीव ने अपने प्रथम वर्ष के अनुभव के आधार पर द्वितीय संस्करण को 'दिल से सेवा–दिल से भुगतान' के उद्घोष के साथ प्रस्तुत किया ।

गौरतलब है कि मिशन रीव की स्थापना प्रदेश भर में एक लंबे सर्वे/अवलोकन करने के बाद हुई । इसका उद्घाटन भारत सरकार के **केंद्रीय राज्य मंत्री कृषि एवं पंचायती राज परषोत्तम रुपाला** द्वारा 30 सितंबर 2017 को किया गया और अपनी आरंभिक चुनौतियों के बाद एक वर्ष का सफल कार्यकाल इस मिशन ने पूरा किया है । केंद्रीय मंत्री ने इस मिशन को भारत में एक अनूठी पहल कहा था और मंशा ज़ाहिर की थी कि हिमाचल में सफलता के बाद इस मिशन को पूरे देश में लागू करने के लिए सरकार भी इसके लिए हरसंभव मदद करेगी । इसके अलावा मंत्री ने इच्छा ज़ाहिर की थी कि गांव–गांव में सरकार की योजनाओं को सही प्रकार से ले जाने और जागरुकता में इस मिशन की सकारात्मक भूमिका रहेगी । इस उद्देश्य में रीव अपने वांछित लक्ष्य को अनेक माध्यमों से पूरा करने के लिए दिन–रात प्रयासरत है । सरकार की योजनाओं की जानकारी मिशन रीव के स्वयंसेवकों और रीव प्रकाशन 'द रीव टाइम्स' के विशेष पृष्ठों में स्थान पा चुकी है । उसके बाद महत्वकांक्षी सेवाओं का विधिवत लोकार्पण प्रदेश **सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री विरेन्द्र कंवर** द्वारा किया गया तथा उन्होंने इस मिशन को एक सराहनीय क़दम बताया । एक वर्ष पूरा होने पर तथा प्रदेशव्यापी नशामुक्ति अभियान के प्रथम चरण के समापन अवसर पर आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में **प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज** ने इसे सफल प्रयास बताया और नए संस्करण पर प्रसन्नता ज़ाहिर की ।

सेवाओं तक पहुंचने की प्रक्रिया

- मिशन रीव का प्राथमिक चरण इसके सदस्य बनने से आरंभ होता है । सदस्य बनने के लिए सर्वप्रथम ऑनलाईन फॉर्म भरे जाते हैं । इसमें कुछ आधारभूत औपचारिकताओं को पूरा करना होता है ।
- दूसरे संस्करण में सदस्यता के प्रारुप में परिवर्तन किए गए हैं । जिसमें इसे तीन चरणों में विभाजित किया गया है । वार्षिक प्रदत सदस्यता जिसमें 2000/रुपये यथावत ही रहेंगे । आजीवन सदस्यता का एक नवीन विकल्प रहेगा जिसमें आजीवन सदस्यता लेने वालों के लिए एक मुश्त 10,000/रुपये अदा करने होगें । तीसरा विकल्प स्वैच्छिक सदस्यता का रहेगा जिसके लिए सदस्य को कोई भी शुल्क अदा नहीं करना होगा । मिशन रीव का यह प्रयास द्वितीय संस्करण को अद्वितीय बनाता है ताकि अधिकतम परिवारों को मिशन रीव की सेवाओं से जोड़ा जा सके ।
- सदस्यता के किसी भी प्रारुप के साथ जुड़ते ही आम–जन अपनी चिंताओं को रीव के साथ साझा करने व समाधान हेतु संबद्ध हो जाता है । इसमें उसके परिवार के सभी सदस्य सेवाओं के लाभ के पात्र बन जाते हैं ।
- सदस्यता के बाद सबसे महत्वपूर्ण क़दम आवश्यकता आकलन का है जो कि आयु विशेष वर्ग को आधार बनाकर तैयार किया गया है । अपनी आयु वर्ग में अपनी आवश्यकताओं एवं समस्याओं को मात्र एक क्लिक करके समाधान तक की प्रक्रिया को ऑनलाईन देख सकता है । यह इस प्रकार का ऑनलाईन पोर्टल है जिसमें समस्या/ आवश्यकता पर क्लिक करते ही सामने उस समस्या के निदान के लिए किस विभाग या योजना से संपर्क करना है, उसका पूर्ण विवरण सामने आ जाता है । यानि समस्या के निदान की प्रक्रिया स्पष्ट रुप से सामने आ जाती है । उसके साथ ही उस सेवा के लिए भुगतान की जाने वाली राशि का पूर्ण विवरण भी सामने आ जाता है । इसमें किसी भी प्रकार की मध्यस्तता की आवश्यकता ही नहीं रहती और ऑनलाईन ही सारी सुविधाओं को देखने, समझने और स्वीकार करने की यह एक अनूठी पहल है । शर्तों को स्वीकार करने के साथ ही मिशन रीव के स्वयंसेवक आपकी आवश्यकता आकलन को आधार बनाकर एक निश्चित समय के अंदर समाधान हेतु अनुबंधित हो जाते हैं ।

मिशन रीव की सेवाऐं :

मिशन रीव में महत्वकांक्षी सेवाओं का समायोजन अपनी तरह का अनूठा प्रयास है जो कि विशेष तौर से ग्रामीण परिवेश में सुविधाओं और व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास का आधार भी है ।

स्वास्थ्य डिविजन

- स्वास्थ्य स्लेट–12 विभिन्न टेस्टों के साथ प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच
- मोबाईल मेडीकल लैब–78 मानकों पर आधारित स्वास्थ्य जांच
- जनऔषधी केंद्र– लोगों को घर द्वार पर सस्ती दवा उपलब्ध कराना
- टेलीमेडीसन– लोगों के घर पर ही स्वास्थ्य जांच और ऑनलाइन स्वास्थ्य परामर्श की सुविधा

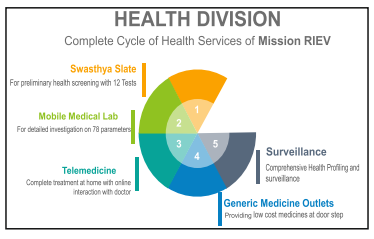

कृषि डिविजन

- मृदा परीक्षण लैब– सदस्यों और किसानों के लिए सेवाऐं
- जैविक खाद निर्माण–किसानों को जैविक खाद निशुल्क प्रशिक्षण और उनके द्वारा निर्मित खाद को बाजार उपलब्ध कराना
- बीज और कृषि उपकरण–किसानों को उनकी मांग के आधार पर उत्तम किस्म के बीज और आधुनिक उपकरण
- फीड सप्लीमेंट– पशुओं में दुग्ध उत्पादन और स्वास्थ्य सुधार के लिए
- जैविक कृषि को प्रोत्साहन देना और कृषि विकास के लिए योजना बनाकर किसानों को सहयोग देना

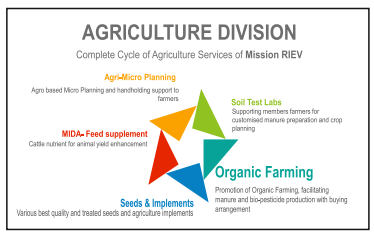

यूटिलिटी, लाइसेंस व अन्य ऑनलाइन सर्विसेज डिविजन

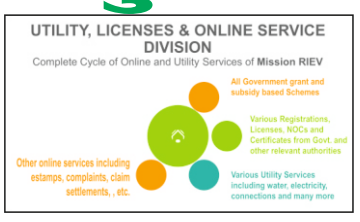

- सरकारी योजनाओं और उन पर मिलने वाली छूट की जानकारी आमजन तक पहुंचाना
- पंजीकरण, लाइसेंस, एनओसी और सर्टीफिकेट व अन्य संबंधित दस्तावेजों के निर्माण में सहयोग करना
- बिजली, पानी, व अन्य रोजमर्रा से संबंधित यूटीलिटी सेवाऐं उपलब्ध कराना
- ई– स्टेंप, ऑनलाइन शिकायत व अन्य ऑनलाइन सेवाऐं

उद्यमिता और व्यवसाय विकास डिविजन

- क्षमतानुसार बेहतर व्यवसाय चयन और संसाधन जुटाने में सहयोग
- प्रशिक्षण, कौशल विकास और क्षमता संवर्द्धन में सेवाऐं
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना, लोन दिलाने और व्यवसाय स्थापित करने में सहयोग
- व्यवसाय शुरु करने से लेकर एक साल तक विभिन्न चरणों में सहयोग
- पहले से स्थापित व्यवसाय को बढ़ाने में सहयोग

बैंकिंग, फाइनेंस और इंशोरेंस डिविजन

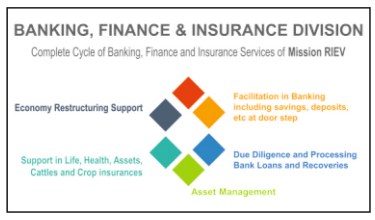

- बचत, जमा और अन्य बैंकिंग सेवाओं में सहयोग
- बैंक लोन देना और रिकवरी व देनदारी संबंधि सेवाऐं
- संपत्ति प्रबंधन,जीवन, स्वास्थ्य, संपत्ति, पशुधन और फसल बीमा संबंधि सेवाऐं

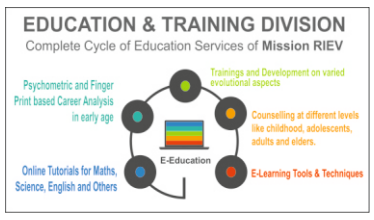

शिक्षा और प्रशिक्षण डिविजन

- गणित, विज्ञान और अंग्रेजी और अन्य विषयों पर ऑनलाइन कोचिंग
- साइकोमीट्रिक और फिंगर प्रिंट आधारित करियर परीक्षण
- व्यक्तित्व विकास और अन्य विकासात्मक पहलुओं में सहयोग
- बचपन, किशोरावस्था व व्यस्क आयुवर्ग आधार पर काउंसलिंग
- ई–लर्निंग टूल्ज और अन्य तकनीक

सामाजिक सुरक्षा और आपदा जोखिम सेवा डिविजन

- बच्चों और बजुर्गों की देखभाल व महिला सशक्तिकरण व अक्षम वर्ग की देखभाल से संबंधित सेवाऐं
- पेंशन व उपलब्ध समय के सदुपयोग में सहयोग
- किसी भी आपदा और आकस्मिक दुर्घटना के समय सेवाऐं
- सामाजिक समस्या, कुरितियों और बुराईयों के निराकरण में पहल

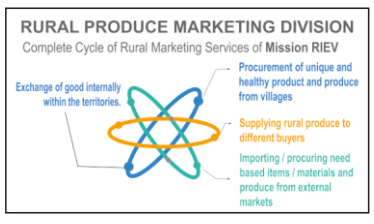

ग्रामीण उत्पाद मार्केटिंग डिविजन

- गांवों में तैयार होने वाले शुद्ध उत्पादों का क्रय– विक्रय
- खरीददारों तक ग्रामीण उत्पादों को पहुंचाना
- गांवों में मांग आधारित उत्पादों की आपूर्ति करना और गांवों से उत्पादों को बाजार तक पहुंचाना
- प्रदेश के भीतर आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देना

संपत्ति प्रबंधन डिविजन

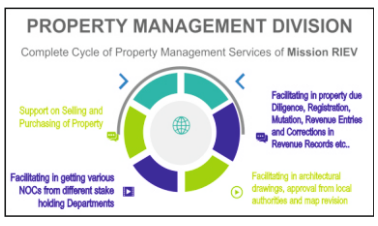

- संपत्ति संबंधि देनदारियों, पंजीकरण, इंतकाल, राजस्व से संबंधित विभिन्न सेवाऐं
- नक्शा तैयार करवाने और स्थानीय प्राधिकरणों से मंजूरी आदि में सहयोग करना
- विभिन्न विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र दिलाने में सहयोग

मीडिया, प्रिंटिंग और पब्लिकेशन डिविजन

- द रीव टाइम्स समाचार पत्र का प्रकाशन, ऑनलाइन न्यूज पोर्टल
- ग्रामीण विकास से जुड़ी समस्याओं को विभिन्न प्रकाशनों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना

- मिशन रीव ने इस सेवाओं को सार्वजनिक कर आम आदमी को उसकी परेशानियों से मुक्त करने और देश हित तथा स्वयं के विकास के लिए स्वतंत्रता एवं समय प्रदान करने का एक सुअवसर प्रदान किया है ।

मिशन रीव के एक वर्ष पूरे होने पर शुरु हुआ रीव संस्करण-2

मानसिक संपन्नता से ही आर्थिक संपन्नता का उद्भव संभव | **सबके चेहरे पर मुस्कान ही मिशन रीव का परम् लक्ष्य**

दिल से सेवा-दिल से भुगतान : इन चरणों में आपके मध्य

- मिशन रीव के पुराने सदस्य और जिन्होंने 31 मार्च 2018 तक सदस्यता ली है, उनकी सदस्यता का स्वतः ही एक वर्ष के लिए निशुल्क नवीकरण कर दिया गया है।

सदस्यता के प्रारुप

- **क. वार्षिक प्रदत/paid सदस्यता**

इस प्रारुप में पहले जैसे ही ढांचे पर एक वर्ष के लिए 2000/– रुपये के भुगतान पर सदस्यता प्रदान की जाएगी ।

ख. आजीवन सदस्यता

मिशन रीव के दूसरे संस्करण में आजीवन सदस्यता का नया विकल्प रखा गया है । इसके लिए एक बार के 10,000/रू. के भुगतान पर इसका आजीवन सदस्य बना जा सकता है । इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रत्येक पंचायत से जो भी आजीवन सदस्य होंगे उन्हें ही रीव सलाहकार बोर्ड का सदस्य बनने का अवसर प्राप्त होगा ।

ग. स्वैच्छिक सदस्यता

इस प्रारुप में सदस्य बनने के लिए कोई भी भुगतान नहीं किया जाऐगा । इसमें कोई भी सदस्य बन सकता है तथा सदस्य बनने के बाद उनका आवश्यकता आकलन होगा ।

12 ज़िलें-12 ब्लॉक : दिल से सेवा-दिल से भुगतान

प्राथमिक चरण में दूसरा संस्करण प्रदेश के 12 ज़िलों के 12 ब्लॉक में लागु किया जा रहा है । मिशन रीव अपने 10 प्रभागों में विभाजित समस्त सेवाओं को आम लोगों में ले जाकर आवश्यकता आकलन के आधार पर समस्याओं का समाधान करेगा । दिल से सेवा भाव रखते हुए रीव सेवाकर्मी आपके पास आकर आपसे बात करेंगें और आपके लिए सेवाऐं देंगें । निश्चित भुगतान की स्थिति में भी आपसे हमारे साथी एक मुस्कान और दिल से भुगतान की बात करेंगे ... यही ध्येय मिशन रीव को अन्यों से पृथक करता है ।

पहले सेवा-बाद मे आमदन-आपके चेहरे पर मुस्कान

इसी मूलमंत्र को मिशन रीव आपके आंगन में दस्तक दे रहा है । आपकी चिंता ही हमारी सेवा को दिशा देता है । समस्या का निदान हमारा सर्वोपरी लक्ष्य है ।

कैशलैस होगी पूरी प्रक्रिया और भुगतान

सदस्यता अभियान और अन्य किसी भी भुगतान की स्थिति में इसे पूर्णतः पारदर्शी रखा जाएगा । इसके लिए कोई भी कैश हस्तांतरण नहीं किया जाएगा । समस्त भुगतान कैशलैस होगा जिसके लिए पॉस मशीनें एवं अन्य संसाधनों का प्रबन्ध किया जा चुका है । इसकी शुरूआत चम्बा जिला से हो चुकी है।

IIRD
हम जानते हैं गाँव को बेहतर

सदस्यता के लिए किसी भी प्रारूप में जुड़ने के लिए हमारे ब्लॉक, जिला समन्वयकों से अथवा सीधे हमारी Website : www.missionriev.in या दूरभाष न. – 0177-2640761, 2844073 पर संपर्क करें।